ISSN-0971-8397

योजना

अप्रैल 2022 विकास को समर्पित मासिक ₹ 22

Elite Academy For Education & Training Pvt Ltd * Delhi *

फ़िनटेक

विशेष आलेख

फ़िनटेक सीमाओं से परे
इन्जेती श्रीनिवास

सामाजिक-आर्थिक विकास की बढ़ती गति
भरत लाल

प्रमुख आलेख

डिजिटल पहचान
डॉ सौरभ गर्ग

फ़ोकस

वित्तीय प्रौद्योगिकी क्रांति
देबजानी घोष

प्रधानमंत्री गति शक्ति

प्रधानमंत्री गतिशक्ति आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है। यह विकास के सात वाहकों- सड़कें, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, सार्वजनिक परिवहन, जलमार्ग और रसद अवसंरचना द्वारा संचालित है, एक साथ अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे। ये क्षेत्र ऊर्जा प्रेषण, सूचना प्रौद्योगिकी संचार, सीवरेज और सामाजिक अवसंरचना की पूरक भूमिकाओं द्वारा समर्थित हैं। यह दृष्टिकोण स्वच्छ ऊर्जा और सबका प्रयास द्वारा संचालित है जो केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र के प्रयासों से सभी के लिए, विशेष रूप से युवाओं के लिए नौकरी और उद्यमशीलता के व्यापक अवसर उपलब्ध कराता है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21 अक्टूबर 2021 को आर्थिक क्षेत्रों के लिए बहु-मोडल कनेक्टिविटी के लिए प्रधानमंत्री गतिशक्ति-राष्ट्रीय मास्टर प्लान को मंजूरी दी। यह 5 ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनने के भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। लाल किले से 75 वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित, पीएम गति शक्ति (गति और शक्ति) भारत के नागरिकों, उद्योगों, निर्माताओं, किसानों और गांवों पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री गतिशक्ति को प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में हितधारकों के लिए कई विभागों की संलग्नता को कम करना और समग्र योजना को संस्थागत बनाना है।

प्रधानमंत्री गतिशक्ति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि 21वीं सदी का भारत बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में समन्वय की कमी के कारण पैसा या समय बर्बाद न करे। हर बड़ी परियोजना के लिए एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म भी तैयार किया गया है ताकि हर विभाग को समय पर सटीक जानकारी मिल सके। यह विभिन्न हितधारकों को एक साथ लाएगा और परिवहन के विभिन्न तरीकों को एकीकृत करने में मदद करेगा। यह 21वीं सदी के भारत के निर्माण के लिए देश की वर्तमान और भावी पीढ़ियों को नई ऊर्जा देगा और अगले 25 वर्षों के लिए आत्मनिर्भरता की नींव रखेगा।

मास्टर प्लान में, 100 लाख करोड़ रुपये के निवेश को लागू करने और उसकी निगरानी करने के लिए एक संयुक्त समिति में 16 मंत्रालयों को एकीकृत करके क्षेत्रवार विकास के लिए एक समग्र दृष्टिकोण है। क्षेत्रवार कार्यों का विवरण इस प्रकार है:

- दूरसंचार क्षेत्र में 2024-25 तक 35,00,000 कि.मी. में ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क बिछाई जानी है। 2022 तक सभी 2,50,000 ग्राम पंचायतों को हाई-स्पीड इंटरनेट और 4जी मोबाइल कनेक्टिविटी से जोड़ा जाना है।
- 2024-25 तक नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की क्षमता को 87.7 गीगावाट से बढ़ाकर 225 गीगावाट किया जाना है। भारत की बिजली उत्पादन क्षमता का लगभग 50 प्रतिशत 2024-25 तक अक्षय ऊर्जा स्रोतों से पूरा किया जाना है।
- बिजली प्रेषण नेटवर्क को 4,25,500 सर्किट कि.मी. से बढ़ाकर 2024-25 तक 4,54,200 सर्किट कि.मी. में अपग्रेड किया जाना है। प्रेषण नेटवर्क निष्पादन मानदंडों को सर्वोत्तम वैश्विक मानकों के अनुरूप किया जाना है।
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में, उद्योगों के लिए प्रमुख मांग और आपूर्ति केंद्रों को जोड़ने वाली 17,000 कि.मी. लंबी ट्रंक पाइपलाइन को 2024-25 तक जोड़ा जाना है, जिससे देश भर में पाइपलाइन की लंबाई कुल 34,500 कि.मी. हो जाएगी। 2027 तक सभी राज्यों को ट्रंक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क से जोड़ा जाना है।
- सागरमाला द्वारा संचालित, शिपिंग क्षेत्र को बंदरगाहों पर कार्गो क्षमता को 2020 में 1282 प्रति वर्ष एमएमटीपीए से बढ़ाकर 2024-25 तक 1759 मिलियन मीट्रिक टन

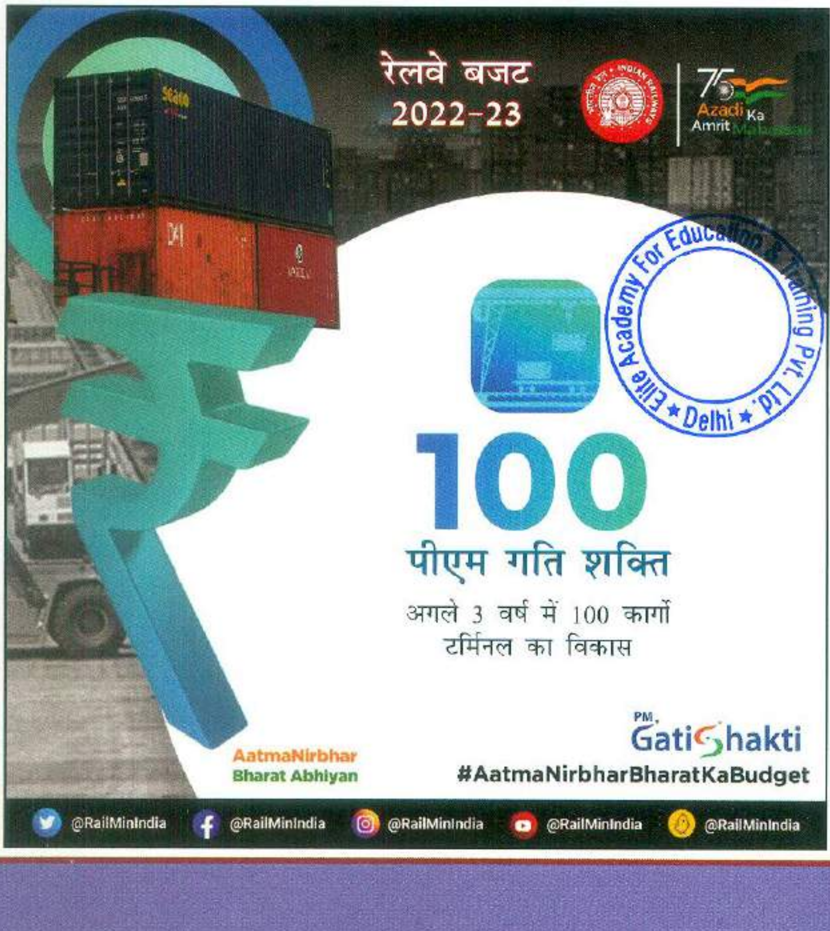

शेष भाग पृष्ठ 58 पर...

योजना

वर्ष : 66
अंक : 04

अप्रैल 2022
चैत्र-वैशाख, शक संवत् 1944

मूल्य : ₹ 22
पृष्ठ : 60

वेबसाइट www.publicationsdivision.nic.in

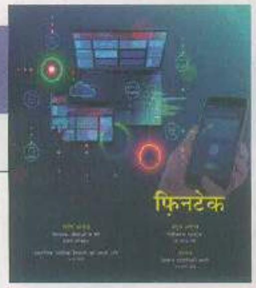

वरिष्ठ संपादक : कुलश्रेष्ठ कमल
संपादक : डॉ ममता रानी

संपादकीय कार्यालय
648, सूचना भवन, सीजीओ परिसर,
लोधी रोड, नयी दिल्ली-110 003

उत्पादन अधिकारी : डी के सी हृदयनाथ
आवरण : बिंदु वर्मा

योजना का लक्ष्य देश के आर्थिक विकास से संबंधित मुद्दों का सरकारी नीतियों के व्यापक संदर्भ में गहराई से विश्लेषण कर इन पर विमर्श के लिए एक जीवंत मंच उपलब्ध कराना है।

योजना में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने और व्यक्तिगत हैं। ज़रूरी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से संबद्ध हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण हो।

योजना में प्रकाशित विज्ञापनों की विषयवस्तु के लिए योजना उत्तरदायी नहीं हैं।

योजना में प्रकाशित आलेखों में प्रयुक्त मानचित्र व प्रतीक आधिकारिक नहीं है, बल्कि सांकेतिक हैं। ये मानचित्र या प्रतीक किसी भी देश का आधिकारिक प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

योजना लेखकों द्वारा आलेखों के साथ अपने विश्वसनीय स्रोतों से एकत्र कर उपलब्ध कराए गए आंकड़ों/तालिकाओं/इन्फोग्राफिक्स के संबंध में उत्तरदायी नहीं है। योजना किसी भी लेख में केस स्टडी के रूप में प्रस्तुत किसी भी ब्रांड या निजी संस्थाओं का समर्थन या प्रचार नहीं करती है।

योजना घर मंगाने, शुल्क में छूट के साथ दरों व प्लान की विस्तृत जानकारी के लिए **पृष्ठ-57** पर देखें।

योजना की सदस्यता का शुल्क जमा करने के बाद पत्रिका प्राप्त होने में कम से कम 8 सप्ताह का समय लगता है। इस अवधि के समाप्त होने के बाद ही योजना प्राप्त न होने की शिकायत करें।

योजना न मिलने की शिकायत या पुराने अंक मंगाने के लिए नीचे दिए गए ई-मेल पर लिखें -
pdjucir@gmail.com

या संपर्क करें- **दूरभाष : 011-24367453**
(सोमवार से शुक्रवार सभी कार्य दिवस पर प्रातः 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक)

योजना की सदस्यता की जानकारी लेने तथा विज्ञापन छपवाने के लिए संपर्क करें–
अभिषेक चतुर्वेदी, संपादक, पत्रिका एकांश
प्रकाशन विभाग, कमरा सं. 779, सातवां तल,
सूचना भवन, सीजीओ परिसर, लोधी रोड,
नयी दिल्ली-110003

@DPD_India
@dpd_india

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

इस अंक में

विशेष आलेख

फ़िनटेक सीमाओं से परे
इन्जेती श्रीनिवास 7

सामाजिक-आर्थिक विकास की बढ़ती गति
भरत लाल, स्फूर्ति कोलिपाका 11

प्रमुख आलेख

डिजिटल पहचान
डॉ सौरभ गर्ग 19

फोकस

वित्तीय प्रौद्योगिकी क्रांति
देबजानी घोष 24

वित्तीय क्षेत्र में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस
बालेन्दु शर्मा दाधीच 29

ग्रामीण भारत में बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं
ओसामा मंज़र, मेघा कठेरिया,
डॉ सैयद एस काज़ी 33

समावेशी बुनियादी ढांचा
सचिन चतुर्वेदी 39

भविष्य है नवाचारों का
ऋषभ कृष्ण सक्सेना 45

डिजिटल मुद्रा की तैयारी
अनिल बंसल 51

ई-रुपी क्या है और यह कैसे काम करता है? 54

आज़ादी का अमृत महोत्सव

पुस्तक चर्चा
भगत सिंह: अद्वितीय व्यक्तित्व 55

नियमित स्तंभ

विकास पथ
प्रधानमंत्री गति शक्ति कवर-2

क्या आप जानते हैं?
अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी में स्टार्टअप 44

आगामी अंक : सामाजिक सुरक्षा

प्रकाशन विभाग के देश भर में स्थित विक्रय केंद्रों की सूची के लिए देखें पृ.सं. 42

हिंदी, असमिया, बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, मराठी, ओडिया, पंजाबी तथा उर्दू में एक साथ प्रकाशित।

आपकी राय

yojanahindi-dpd@gov.in

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

ग्रामीण महिलाओं के लिए पहल

योजना पत्रिका के मार्च 2022 के अंक में प्रकाशित सभी लेख प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बहुपयोगी है। कोविड-19 महामारी के चुनौतियों के बावजूद जिस तरह से बजट को संतुलित किया गया है, वह एक आदर्श और उत्साहवर्धक है। इस अंक में प्रकाशित 'ग्रामीण महिलाओं के लिए पहल' विषयक लेख में ग्रामीण परिवेश की महिलाओं की बढ़ती भूमिका का उल्लेख किया गया है।

इसमें परंपरागत धारणाओं को तोड़ते हुए ग्रामीण महिलाएं भी स्वयं सहायता समूह से जुड़ कर राष्ट्र के नवनिर्माण में भागीदारी सुनिश्चित कर रही है। कोविड-19 महामारी के दौरान सहायक संस्थाओं में समूहों के सदस्यों द्वारा किए गए योगदान की देश भर में काफी सराहना की गई है। आज समूह की महिलाएं डिजिटल क्रांति की गवाह बन रही है। सरकार द्वारा समूहों के उत्पादों को ई-विपणन के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के कार्यक्रमों के साथ अभिसरण करके समूह सदस्यों को सतत आय का स्रोत उपलब्ध कराया जा रहा है। इन समूहों को स्व-प्रबंधित संस्था के रूप में विकसित किया जा रहा है। महिलाएं सामाजिक और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रही हैं।

– डॉ. नंदकिशोर साह
बनकटवा, पूर्वी चंपारण, बिहार

बजट अंक सराहनीय

योजना के मार्च अंक में बजट के विभिन्न पक्षों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है जो आम आदमी के लिए देश की अर्थव्यवस्था को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी। बजट सरकार के सामने चुनौतियां उत्पन्न करती ही हैं। कोविड-19 महामारी ने भी सरकार के सामने बड़ी चुनौतियां पेश की थी किन्तु सरकार ने तत्काल निर्णय लेकर इनका सामना किया जिससे सरकार की आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ा, फिर भी सरकार के निर्णयों ने जनता को राहत पहुंचाई। जिसके लिए सरकार बधाई की पात्र है।

वर्तमान में युक्रेन और रूस का युद्ध सरकार के सामने आर्थिक और राजनैतिक चुनौतियां उत्पन्न कर रही है। युद्ध युक्रेन और रूस के मध्य हो रहा है किन्तु इसके दुष्परिणाम हमें भुगतने पड़ रहे हैं। हम आशा करते हैं सरकार इनका समाधान भी सफलतापूर्वक करने में सफल होगी।

केंद्रीय बजट-2022-23 में विभिन्न विषयों पर बेबाक विश्लेषण के लिए सभी लेखकों को साधुवाद।

– विश्वनाथ सिंहानिया
जयपुर, राजस्थान

मोटे अनाज का अंतरराष्ट्रीय वर्ष

योजना पत्रिका के मार्च 2022 के अंक में प्रकाशित 'क्या आप जानते हो' के अंतर्गत मोटे अनाज का अंतरराष्ट्रीय वर्ष लेख अच्छा लगा। मोटे अनाज के प्रति विश्वभर में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार का प्रस्ताव अत्यंत सराहनीय है। यह देश की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान देता है। मोटा अनाज- ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, सरवां, कोदो, कुटकी आदि पौष्टिकता से भरपूर होता है। शरीर में स्फूर्ति बनाये रखने में काफी मददगार होता है। हमारे यहां ज्वार, चना, बाजरा, मक्का और रागी जैसे मोटे अनाज की परंपरा थी। पुराने जमाने में लोग यात्राओं पर जाते समय इसका सत्तू बनाकर पोटलियों में बांध कर ले जाते थे। भूख लगने पर पानी में घोल-घोलकर इसका सेवन किया करते थे। आज फिर से थालियों से गायब हुए इस पोषक आहार की पूरी दुनिया में डिमांड जारी है। चूंकि धान और गेहूं की तुलना में मोटे अनाज के उत्पादन में पानी की खपत कम होती है। इसकी खेती में यूरिया और दूसरे रसायनों की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये अनाज जल्दी खराब भी नहीं होते। यह सेहत के साथ-साथ पर्यावरण के लिए भी बेहतर है।

– उत्कर्ष
अत्तापुर, हैदराबाद

डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर

योजना पत्रिका के मार्च 2022 के अंक में प्रकाशित सभी लेख सराहनीय हैं किन्तु 'बुनियादी सुविधाओं का विस्तार' लेख प्रासंगिक लगा। डिजिटल क्रांति ने आम लोगों को जागरूक करके आधुनिकता की दौड़ में अग्रसर करने का अवसर दिया है। मोबाइल में डाउनलोड एक छोटा-सा ऐप पर्स में पैसे के अभाव से अपनी भूख को मिटाने में कारगर सिद्ध होता है। रेहड़ी पर चाय बेचने वाले की चाय की चुस्कियों से लेकर पानी से भरे गोलगप्पों का मज़ा प्राप्त कर सकता है।

बुनियादी ढांचे में निवेश के निरंतर बढ़ने से रोज़गार के अवसर पैदा होते हैं और निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहन मिलता है। इससे माल-सामान लाने ले जाने की लागत कम हो जाती है। घरेलू और वैश्विक बाज़ारों में निर्माण क्षेत्र के उद्योगों में स्पर्धा की भावना बढ़ती है और लोगों के लिए जीवन आसान हो जाता है।

– श्रीया
नई दिल्ली

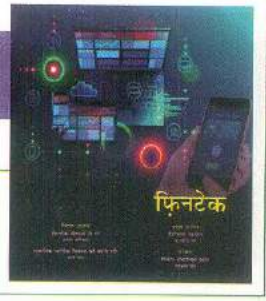

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd ★ Delhi ★

फ़िनटेक से हो रहा संभव

ऐसा भी समय था जब रुपयों से भरा बटुआ लिए बिना बाज़ार जाने की बात सोची भी नहीं जा सकती थी। फिर एटीएम कार्ड का दौर आया और पर्स या बटुए का बोझ कुछ हद तक कम हो गया। और अब ऐसी स्थिति है कि सड़क किनारे या पटरी पर सब्ज़ी बेचने वाला रेहड़ीवाला या बड़े-बड़े मॉल, सभी डिजिटल भुगतान स्वीकार कर रहे हैं। सबसे बड़ी दिलचस्प बात तो यह है कि बैंकों से निकाली जाने वाली नक़द राशि के मुक़ाबले मोबाइल से किए जाने वाले भुगतान की राशि कहीं ज़्यादा है।

इससे उपभोक्ताओं के लिए बहुत सुविधा हो गई और वित्तीय क्षेत्र में डिजिटल प्रणालियां विकसित करने की दिशा में निरंतर विस्तार हो रहा है। फ़ास्टैग की स्वचालित व्यवस्था लागू होने के बाद से सड़कों पर टोल-टैक्स भुगतान के कारण लगने वाली वाहनों की कतारें अब बीते समय की बात हो चुकी है। एक तरह से देखें तो कह सकते हैं कि वैश्विक महामारी के प्रकोप के दौरान बिना छुए भुगतान या लेनदेन केवल शान की बात न रहकर संक्रमण से बचाव का अनिवार्य उपाय बन गया। अधिकांश लेनदेन पुराने परंपरागत तरीकों की बजाय कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से किए जाने लगे। इसी कारण फ़िनटेक अर्थात् वित्तीय प्रौद्योगिकी का चलन जन-जन तक पहुंच गया। आर्थिक मंदी के बावजूद 2020 की पहली छमाही के दौरान फ़िनटेक लेनदेन के माध्यम से निवेश दोगुने हो गए। डिजिटल इंडिया से नवाचार के नए मार्ग खुल गए और वित्तीय प्रौद्योगिकी से जीवन को सरल बनाने में ज़बरदस्त मदद मिली। इससे वित्तीय समावेशन और नवाचारों को सशक्त बनाने की दिशा में प्रगति होने लगी है।

फ़िनटेक वास्तव में उपभोक्ताओं को बेहतर वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से टेक्नोलॉजी-समन्वयन ही है और मुख्य रूप से आय, निवेश, बीमा और संस्थागत ऋण के चार स्तंभों पर आधारित है। नागरिकों के लिए फ़िनटेक के एक अन्य चरण के तहत उन तक वित्तीय लाभ और पहलों के फायदे पहुंचाने के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी बेशुमार एप्लीकेशंस (अनुप्रयोग) होने के कारण भविष्य में अनगिनत अवसर और संभावनाएं भी बनेंगी।

जनधन-आधार-मोबाइल यानी जेएएम की तिकड़ी से देश में वित्तीय समावेशन की दिशा में चमत्कारिक बदलाव आए हैं। इस वर्ष के केंद्रीय बजट ने फ़िनटेक की पक्की दिशा तय कर दी है और इसके तहत लोगों को उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं में बढ़ोतरी भी होगी और उनमें काफी सुधार भी लाए जाएंगे। डिजिटल करेंसी शुरू करने और डाकघरों में कोर बैंकिंग से इस दिशा में एक और बड़ी सफलता अर्जित की जा सकेगी। लाभ सीधे खातों में हस्तांतरित करने और ई-रुपी लागू होने से लक्षित वर्ग तक सेवाएं पहुंचाना संभव हो रहा है और प्रणाली की खामियां दूर हो रही हैं और दूसरी ओर पीएम स्वनिधि योजना जैसी पहलों से देशभर के छोटे दुकानदार और रेहड़ी-पटरी वाले आसानी से ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

हालांकि शहरी बाज़ार तो फ़िनटेक अपना रहे हैं परंतु ग्रामीण बाज़ारों तक यह सुविधा अभी कम ही पहुंची है। इस प्रणाली के लाभ ग्रामीणों तक पहुंचाने के लिए फ़िनटेक समाधानों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा और जनशक्ति को और विस्तार तथा मज़बूती देने की ज़रूरत है। साथ ही, लोगों में इन प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल के प्रति भरोसा जगाना होगा और उन्हें आश्वस्त करना होगा कि उनका धन और निवेश सुरक्षित और महफ़ूज़ है। आंकड़ों की सुरक्षा और धोखाधड़ी से निपटने के समुचित और ठोस उपाय करने होंगे। ब्लॉकचेन, जिओ-फैंसिंग, जिओ-टैगिंग या धांधली के इरादे से होने वाले हमलों की रोकथाम के लिए नीतिगत समर्थन भी होना चाहिए। तभी सुरक्षित और स्थिर डिजिटल वित्तीय वातावरण बनाया जा सकेगा। अपनी असीम संभावनाओं के बल पर ही फ़िनटेक और इससे जुड़ा आर्थिक पारिस्थितिकी तंत्र सफल और प्रभावी माध्यम बन सकेंगे और लोग अपनी आर्थिक-सामाजिक प्रगति के लिए फ़िनटेक और उससे जुड़ी व्यवस्थाओं पर भरोसा कर सकेंगे। ■

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

फ़िनटेक सीमाओं से परे

इन्जेती श्रीनिवास

भारत का फ़िनटेक तंत्र के रूप में शानदार आविर्भाव हुआ है जहां फ़िनटेक की वित्तीय संस्थाओं, विनियामकों और सरकारों ने इस क्षेत्र के विकास को समग्र एवं निरंतर गति देने के लिए मिलकर काम किया। सरकार की ओर से अपनाए गए परिवर्तनकारी डिजिटल प्रयासों ने दुनिया में लाखों लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण को बढ़ाने में फ़िनटेक कंपनियों की मदद की है। डिजिटल क्रांति का अगला चरण बिखरे हुए डिजिटल समाधानों से आगे बढ़कर ऐसी डिजिटल अवसंरचना की ओर बढ़ने का है जो अर्थव्यवस्थाओं एवं समाजों में डिजिटिकरण को गति देगी।

सरकार ने इंडिया स्टैक (भारत पुंज) में मज़बूत सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के ज़रिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी का एक अद्‌भुत प्रारूप दुनिया के सामने रखा है। इंडिया स्टैक निजी क्षेत्र के नवाचार को सुगमता तथा सामर्थ्य प्रदान करता है। इंडिया स्टैक के चार स्तम्भ हैं। पहला, पहचान हेतु आधार के रूप में बायोमीट्रिक पहचान; दूसरा प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) के ज़रिए सबके बैंक खाता खुलवाना तथा वित्तीय समावेशन का निर्माण; तीसरा, धन के अंतरण हेतु आवश्यकतानुसार अपनाए जा सकने वाले प्लेटफॉर्म का निर्माण [इम्मिडेट पेमेंट सर्विस (आईएमपीएस), यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई), भारत बिल पेमेंट सिस्टम (बीबीपीएस) आदि] तथा चौथा, बैंकों एवं फ़िनटेक (वित्तीय प्रौद्योगिकी) कंपनियों को यूपीआई, माल और सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) तथा डिजीलॉकर जैसे प्लेटफॉर्म के उपयोग की अनुमति देना। वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनियों ने विविध प्रकार के यूज़ केसिस (एक पद्धति जिसका उपयोग प्रणाली की आवश्यकताओं की पहचान, उन्हें स्पष्ट और व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है) के समाधान हेतु इस खुले-एपीआई अवसंरचना का भरपूर उपयोग किया है तथा यह विकास की अगली लहर को बल देने के लिए मज़बूत स्तंभ के रूप में कार्य करती रहेगी।

2020 में महामारी के कारण आर्थिक गतिविधि में मंदी के बावजूद भारत में फ़िनटेक उद्योग, महामारी के कारण उत्पन्न डिजिटिकरण अवसरों का लाभ उठाकर और अन्य चीज़ों के अलावा सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हुए वृद्धि के पथ पर अग्रसर रहा। भारत 2,100 फ़िनटेक से अधिक के साथ विश्व में सबसे बड़ा एवं सबसे तेज़ी से बढ़ता फ़िनटेक बाज़ार है तथा अमरीका एवं चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा फ़िनटेक तंत्र है। भारत में फ़िनटेक अपनाने की दर 87 प्रतिशत है जो कि विश्व में सबसे अधिक है जबकि वैश्विक औसत लगभग 64 प्रतिशत है। दिसंबर 2021 तक भारत में एक अरब अमरीकी डॉलर से अधिक मूल्य की 17 से अधिक फ़िनटेक कंपनियां थीं जिन्हें 'यूनिकॉर्न दर्जा' मिला है तथा वित्त वर्ष 2020 में अकेले भारत

लेखक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। ईमेल: chairperson@ifsca.gov.in

का बाज़ार 50-60 अरब अमरीकी डॉलर था और बॉस्टॉन कंसलटेंसी ग्रुप के हाल के अध्ययन के अनुसार 2025 तक यह बढ़ कर 150 अरब का हो सकता है।

सरकार के परिवर्तनकारी डिजिटल प्रयासों ने दुनिया में लाखों लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण को बढ़ाने में फ़िनटेक कंपनियों की मदद की है। डिजिटल क्रांति का अगला चरण बिखरे हुए डिजिटल समाधानों से आगे बढ़कर ऐसी डिजिटल अवसंरचना की ओर बढ़ने का है जो अर्थव्यवस्थाओं एवं समाजों में डिजिटिकरण को गति देगी। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) समाधान डिजिटल समावेशन के ज़रिए दुनिया में लोगों के जीवन में सुधार ला सकते हैं। सफल सरकारों ने अपने देशों के समक्ष तत्काल चुनौतियों को हल करने में इन डिजिटल सुविधाओं का उपयोग किया है। जिन देशों के पास महामारी से पहले समग्र एवं सक्रिय डीपीआई था वे वायरस से निपटने के लिए स्पष्ट तथा त्वरित कार्रवाई प्रक्रिया बना पाए।

डिजिटल सार्वजनिक सुविधाएं डीपीआई को वैश्विक स्तर तक पहुचांने में मदद कर रही हैं। डिजिटल सार्वजनिक सुविधाओं की विशेषता, अर्थात, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, खुला डाटा, खुला एआई मॉडल, खुले मानक आदि। यह है कि कोई भी, कहीं से भी इसमें योगदान और इनका इस्तेमाल कर सकता है। ये बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु महत्वपूर्ण साधन बन रहे हैं जो लाइसेंसी (प्रोपाइटरी) सॉफ्टवेयर पर निर्भर समाधानों की कुछ बंदिशों को हल करते हैं तथा इन्हें जैसे-जैसे बार-बार साझा और इस्तेमाल किया जाता है इनका मूल्य बढ़ता है। भारत कम लागत पर आवश्यकतानुसार किसी भी पैमाने पर अपनाने योग्य ऐसी डिजिटल सार्वजनिक सुविधाएं तैयार करने में अग्रणी है जो समावेशी विकास को बढ़ावा देती हैं। भारत द्वारा विकसित कोविन पोर्टल डिजिटल सार्वजनिक सुविधा का एक उदाहरण है। एक अन्य उल्लेखनीय उदाहरण ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटलकॉमर्स (ओएनडीसी) का है जिससे ई-वाणिज्य उद्योग की मौजूदा कार्यशैली में क्रांति आने की संभावना है।

भारत 2, 100 फ़िनटेक से अधिक के साथ विश्व में सबसे बड़ा एवं सबसे तेज़ी से बढ़ता फ़िनटेक बाज़ार है तथा अमरीका एवं चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा फ़िनटेक तंत्र है। भारत में फ़िनटेक अपनाने की दर 87 प्रतिशत है जो कि विश्व में सबसे अधिक है जबकि वैश्विक औसत लगभग 64 प्रतिशत है।

डीपीआई समावेशी, नागरिकों की निजता तथा सुरक्षा का संरक्षक तथा विनियामक तंत्रों से संचालित होना चाहिए जो उसके कार्यान्वयन में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करे। इसकी रचना इस तरह होनी चाहिए जिससे सरकारें निजी क्षेत्र के साथ सहयोग कर सकें तथा बुनियादी स्तरों के ऊपर नवोन्मेष को बढ़ावा देकर उससे कुछ नया सृजन कर सकें। नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा, बीमा, वित्तीय संसाधन तथा अन्य सेवाएं सुलभ कराने के लिए ऐसा करना आवश्यक है।

सार्थक सार्वजनिक-निजी भागीदारी बनाना अच्छे डीपीआई के विकास में सहायक होगी। जैसा कि हम बता चुके हैं कि भारत में डिजिटल भुगतान तंत्र का विकास, आधार और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) स्थापित होने के बाद हुआ तथा कई कंपनियां नई सेवाएं प्रदान करने और बाज़ार अच्छी खासी हिस्सेदारी जुटाने के लिए बुनियाद तैयार करने में समर्थ हो सकीं। इसके बल पर विभिन्न भुगतान एप्लीकेशनों के बीच स्पर्धा एवं नवाचार को भी बढ़ावा मिला। देशभर में डिजिटल लेन-देन बड़े एवं छोटे सभी बैंकों के लिए नई ऊंचाईं पर पहुंच गया है। यूपीआई ने पुराने और नए दोनों तरह के व्यवसायों में नवाचारी गतिविधियों को समान रूप से अपनाने की सुविधा देकर प्रवेश बाधाएं हटा दी हैं।

कई देश अपनी डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना तैयार करने के लिए प्रयत्नशील हैं पर उसमें सफलता पाना आसान नहीं है। इसका कोई सरल समाधान नहीं है। केवल, बेहतर समन्वय, अधिक संसाधन जुटाने तथा डीपीआई से जुड़ी इन बातों की स्पष्ट समझ से यह संभव हो पाएगा कि इसका क्या महत्व है, क्या हम इसे अपनाने की गति तेज़ कर सकते हैं और स्थानीय स्तर पर इसे मूल्यवान कैसे सिद्ध किया जा सकता है।

सीमाओं से परे फ़िनटेक (फ़िनटेक बियांड बाउंड्रीज) की परिकल्पना पहली बार इनफिनिटी फोरम' में प्रस्तुत की गई। यह फोरम एक प्रमुख वित्तीय प्रौद्योगिकी तथा वैश्विक चिंतन नेतृत्व कार्यक्रम था, जिसका आयोजन 3 दिसंबर 2021 से किया था जिसमें ब्रिटेन, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका ने साझेदार

देशों के रूप में भाग लिया था। इस आयोजन के लिए 70 से अधिक देशों से 96, 528 प्रतिनिधियों ने पंजीकरण कराए। इसमें चार देशों के वित्त मंत्रियों तथा तीन प्रौद्योगिकी मंत्रियों ने भाषण दिए। कार्यक्रम में 9 देशों के 62 वक्ता थे जिसमें आठ 'इनफिनिटी' वार्ताओं तथा 9 'इनफिनिटी' समितियों का संयोजन हुआ। यह फोरम दुनियाभर की विकट समस्याओं, प्रगतिशील विचारों तथा नई तकनीकों को पहचानने, चर्चा करने तथा समाधान निकालने हेतु मंच प्रदान करता है। यह नीति, व्यवसाय तथा प्रौद्योगिकी में विश्व के प्रमुख विचारकों को चर्चा के लिए एकजुट करता है और इस बारे में कार्रवाई योग्य उपायों का सुझाव देता है कि फ़िनटेक उद्योग समावेशी वृद्धि एवं समूचे मानव समुदाय के हित में प्रौद्योगिकी तथा नवाचार का उपयोग कैसे कर सकता है।

फ़ोरम तीन विषयों पर केंद्रित है (i) सीमाओं से परे फ़िनटेक (फ़िनटेक बियांड बाउंड्रीज) जिसमें सरकारें और व्यवसाय, भौगोलिक सीमाओं से परे हट कर वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने हेतु ग्लोबल स्टैक (वैश्विक पुंज) के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं, (ii) 'फ़िनटेक बियॉंड फाइनेंस' जिसमें टिकाऊ विकास के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, हरित प्रौद्योगिकी तथा कृषि प्रौद्योगिकी जैसे उभरते क्षेत्रों को एक साथ लाया जाए तथा (iii) 'फ़िनटेक बियांड नेक्स्ट' जिसमें इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि क्वांटम कंप्यूटिंग भविष्य में फ़िनटेक उद्योग की प्रकृति पर कैसे असर डाल सकती है और नए अवसरों को बढ़ावा दे सकती है। प्रत्येक विषय ने समारोह की समग्रता की भावना के अनुरूप सीमाओं से परे फ़िनटेक की अवधारणा के दायरे का विस्तार किया।

फ़िनटेक बियांड बाउंड्रीज़ विषय पर हुई चर्चा में बंटी हुई ग्लोबल स्टैक (वैश्विक पुंज) की आवश्यकता बताई गई जिसमें हर देश की अपनी भूमिका हो/जोड़ने के लिए अपना अंश हो। हर देश का अपना पुंज हो सकता है जो एक-दूसरे के साथ जुड़ा हो सकता है। इसे सफल बनाने के लिए क्षेत्रीय सरकारों को मिलकर भागीदारी करने और मानकीकृत मंच विकसित करने की ज़रूरत पड़ सकती है जिससे सीमाओं के आर-पार व्यापार, सीमाओं के आर-पार से लोगों की सुगम और सुरक्षित आवाजाही में मदद मिले। धन, वस्तुओं, सेवाओं आदि की निर्बाध आवाजाही से समूचे क्षेत्र को लाभ होगा।

भविष्य में, भारत अन्य देशों के साथ इस बारे में सहयोग कर सकता है कि कैसे भारत में विकसित डिजिटल संरचना और प्रणालियों का उपयोग करके अन्य देशों के लिए डिजिटल पहचान की रचना की जा

आईएफएससीए के पास सर्वश्रेष्ठ अलग-अलग पुंजों को आपस में जोड़ने की पहल करते हुए वैश्विक स्तर पर ध्यान देने और ग्लोबल स्टैक (वैश्विक पुंज) की परिकल्पना को मूर्त रूप देने का अनूठा अवसर है जिससे फ़िनटेक उद्योग की व्यापक वृद्धि होगी और समावेशी विकास में मदद मिलेगी। 'ग्लोबल स्टैक' की परिकल्पना में 'फ़िनटेक बियांड बाउंड्रीज़' के एजेंडा को आगे ले जाने की क्षमता है।

सकती है। इतना ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय पहचान के मानक विकसित करने में भारत अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग कर सकता है ताकि सशक्तिकरण के माध्यम के रूप में डिजिटल पहचान पूरी दुनिया में उपलब्ध हो।

भारत की फ़िनटेक गाथा की सफलता का श्रेय इंडिया स्टैक (भारत पुंज) के विकास को जाता है। इसी तरह अन्य देश भी सफलताओं के अलग-अगल पैमानों के साथ अपने-अपने पुंज बना रहे हैं। फिलहाल सभी सभी पूंजों के अधिकार क्षेत्र अपने-अपने देश के भीतर तक सीमित हैं, किंतु आईएफएससीए के पास सर्वश्रेष्ठ अलग-अलग पुंजों को आपस में जोड़ने की पहल करते हुए वैश्विक स्तर पर ध्यान देने और ग्लोबल स्टैक (वैश्विक पुंज) की परिकल्पना को मूर्त रूप देने का अनूठा अवसर है जिससे फ़िनटेक उद्योग की व्यापक वृद्धि होगी और समावेशी विकास में मदद मिलेगी। ग्लोबल स्टैक का विचार आईएमएफ ने 2018 में बाली फ़िनटेक एजेंडा नाम से रखा था और 'ग्लोबल स्टैक' की परिकल्पना में 'फ़िनटेक बियांड बाउंड्रीज़' के एजेंडा को आगे ले जाने की क्षमता है।

आधार 2.0 के बारे में एक कार्यशाला नवंबर 2021 में आयोजित हुई थी। इसमें डिजिटल पहचान और स्मार्ट प्रशासन के नए युग का सूत्रपात करने पर ध्यान दिया गया तथा इसकी एक प्रमुख परिकल्पना और मुख्य विषय 'आधार को अंतरराष्ट्रीय डिजिटल पहचान मानक के रूप' में शामिल करना था। डिजिटल पहचान के प्रारूप और संरचना पर काम कर रहे देशों के लिए आधार ने अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में अहम स्थान हासिल कर लिया है और यह अंतरराष्ट्रीय डिजिटल पहचान मानक स्थापित करने वाले संगठन के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

विश्व में अब भी 1.7 अरब से अधिक वयस्क ऐसे हैं जिनकी वित्तीय सेवाओं तक पहुंच नहीं है और फ़िनटेक कंपनियां उन पर काफी बड़ा सामाजिक एवं आर्थिक असर डाल सकती हैं। सभी देश जोखिमों को कम से कम करते हुए इनसे फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें सफल होने और फ़िनटेक क्रांति का लाभ केवल कुछ लोगों तक नहीं बल्कि अनेक लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिक सहयोग की ज़रूरत है। ग्लोबल स्टैक की परिकल्पना से देशों को ऐसा उपयोगी ढांचा उपलब्ध होगा जिससे वे अपनी परिस्थितियों और प्राथमिकताओं के लिए उपयुक्त डिजिटल अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु नीतिगत विकल्प चुनकर सही नींव डाल सकें।

फ़िनटेक कंपनियां बैंकिंग, पूंजी बाज़ारों, बीमा, फंड आदि जैसे विभिन्न वित्तीय क्षेत्रों में उत्पन्न समस्याओं का समाधान करती हैं। आईएफएससी के लिए एकीकृत नियामक होने के नाते आईएफएससीए फ़िनटेक कंपनियों को खुली बैंकिंग, खुले बीमा, खुले निवेश हेतु समाधान तैयार करने के अनूठे अवसर प्रदान करता है जिससे एक खुले वित्तीय तंत्र की राह खुलती है जो भविष्य की खुली डाटा अर्थव्यवस्था के लिए हितकारी है। वास्तव में यह एक नया साहसिक जगत है जो फ़िनटेक कंपनियों के लिए खुला है और सीमाओं के बंधन से परे हैं। ■

संदर्भ

1. इन्वेस्ट इंडिया
2. ग्लोबल फिन्डेक्स डाटाबेस 2017, विश्व बैंक

सामाजिक-आर्थिक विकास की बढ़ती गति

भरत लाल
स्फूर्ति कोलिपाका

हाल में भारत सरकार ने आवास, शौचालय, बिजली, स्वच्छ रसोई गैस, स्वास्थ्य देखभाल, वित्तीय सेवाएं, सामाजिक सुरक्षा, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, सड़कें आदि बुनियादी सुविधाओं की सुनिश्चित व्यवस्था करके खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की ग़रीबी दूर करने के उद्देश्य से 'जीवन-स्तर' सुधारने और 'जीवन सरल' बनाने की दिशा में अनेक उपाय किए हैं। अब ये लोग अपने घरों में ही नल से पीने का साफ पानी उपलब्ध कराए जाने की आशा पाल रहे हैं। इस डिजिटल युग में आंकड़ों का विश्लेषण करके विभिन्न पहलों का प्रभाव आंकने और उसे मॉनीटर करने का अवसर प्राप्त रहता है जिससे डिजिटल प्रशासन में समन्वय रखकर उसे और प्रभावी बनाया जा सके। ग्रामीण परिवारों को बड़े पैमाने पर आधार से जोड़ने से यह कार्य और सरल हो गया है। अब ज़रूरत इस बात की है कि इन सेवाओं को ग़रीबों और समाज के वंचित वर्गों तक पहुंचाने से होने वाले प्रभाव को आंका जाए और यह भी पता लगाया जाए कि ये परिवार ग़रीबी के चंगुल से छुटकारा पाने में सफल हुए हैं या नहीं।

साफ पीने के पानी की सप्लाई सुनिश्चित होने से जहां एक ओर दूषित पानी के इस्तेमाल से होने वाले रोगों पर काबू पाने में बड़ी हद तक सफलता मिलती है वहीं दूसरी ओर जन-स्वास्थ्य की स्थिति सुधारने में भी कुल मिलाकर कामयाबी मिलती है। साफ-सफाई और स्वच्छता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भी यह ज़रूरी है। इस व्यवस्था से महिलाओं और युवतियों को भी राहत मिलेगी क्योंकि घर में पानी का बंदोबस्त करना और दूर-दूर जाकर साफ पानी भरकर लाने का पूरा ज़िम्मा एक लंबे समय से चला ही आ रहा है। इस झंझट से मुक्ति पाकर लड़कियों को समय मिलेगा और वे पढ़ने-लिखने के लिए स्कूल जा पाएंगी। फिर, वे अपनी पसंद का कोई व्यावसायिक कार्य अपना सकेंगी या किसी विशेष कार्य का प्रशिक्षण ले सकेंगी। परंतु जनसंख्या वृद्धि, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और तेज़ी से आगे बढ़ रही अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की पानी की बढ़ती मांग के कारण अनेक क्षेत्रों में पानी की कमी की समस्या बनी रहती है, खासकर जहां वर्ष के दौरान वर्षा कम रह जाती है। इसी वजह से जल सप्लाई प्रणालियां भी ठीक से काम नहीं कर पातीं। असल लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि पानी की सप्लाई की समस्या देश के सामाजिक-आर्थिक विकास की तीव्र गति में अवरोध न बन पाए।

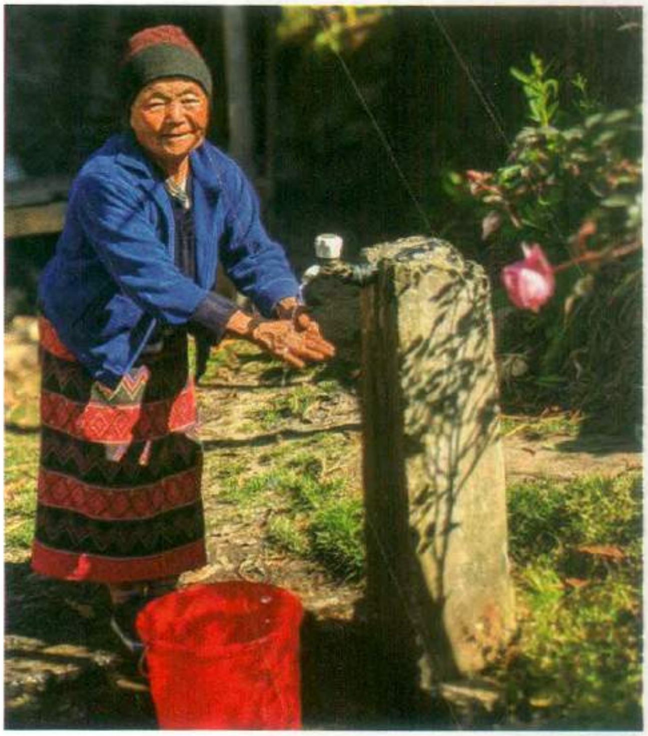

भरतलाल अभी भारत के लोकपाल कार्यालय में सचिव हैं और राष्ट्रीय जल जीवन मिशन में संस्थापक मिशन निदेशक रहे हैं। ईमेल: bharat.lal@gmail.com
स्फूर्ति कोलिपाका भारत में यूनिसेफ की कंसल्टेंट हैं।

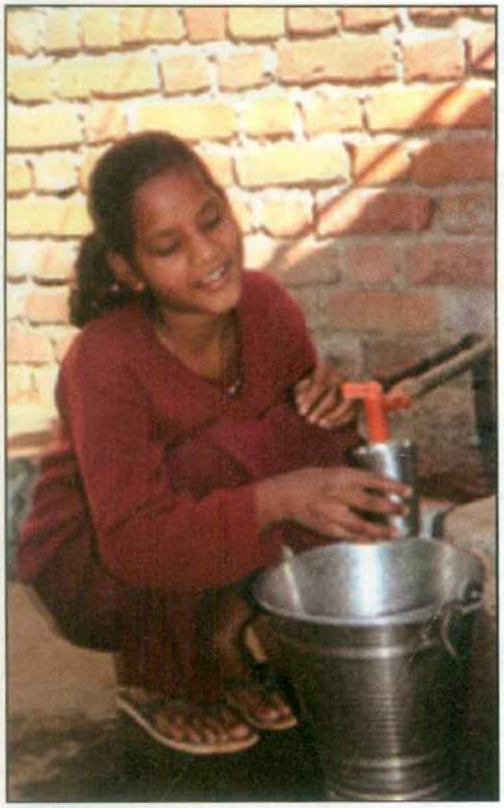

100 प्रतिशत कवरेज के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार योजना

2020	2021	2022	2023	2024
गोवा	तेलंगाना	बिहार	अरुणाचल प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश
	दमण दीव एवं दादरा नागर हवेली	गुजरात	छत्तीसगढ़	असम
	पुदुच्चेरी	हिमाचल प्रदेश	कर्नाटक	झारखंड
	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	जम्मू एवं कश्मीर	केरल	महाराष्ट्र
	हरियाणा	लद्दाख	मध्य प्रदेश	ओडिशा
		मणिपुर	मिज़ोरम	राजस्थान
		मेघालय	नगालैंड	उत्तर प्रदेश
		पंजाब	तमिलनाडु	प. बंगाल
		सिक्किम	त्रिपुरा	
		उत्तराखंड		
1 राज्य	3 राज्य एवं 3 संघशासित प्रदेश	7 राज्य एवं 2 संघशासित प्रदेश	9 राज्य	8 राज्य

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

चित्र 1 : 100 प्रतिशत कवरेज की राज्य/केंद्रशासित प्रदेशवार योजना

चुनौतियां

अगस्त, 2019 में जल जीवन मिशन की घोषणा के समय कुल 18 करोड़ 70 लाख ग्रामीण परिवारों में से मात्र 3 करोड़ 23 लाख (17 प्रतिशत) परिवारों में ही नल से पीने का पानी सप्लाई करने की व्यवस्था थी। लेकिन विगत 2 वर्षों में इन परिवारों की संख्या भी बढ़ी है और नीति तैयार करते समय इस मुद्दे को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस समय देश के 19.32 करोड़ परिवार अलग-अलग जलवायु वाले क्षेत्रों में रह रहे हैं। भारत में ठंडे रेगिस्तान से लेकर गर्म रेगिस्तान, सिंधुगांगेय मैदानों से लेकर मैदानी इलाक़ों तक और विशाल कछारी मुख्य भूभाग, 7,000 किलोमीटर से भी बड़ा तटवर्ती क्षेत्र और अनेक द्वीप समूह हैं। इनमें से प्रत्येक क्षेत्र की अपनी खास अनोखी चुनौतियां हैं। भारत देश की सभ्यता का इतिहास 5,000 वर्ष से भी ज़्यादा पुराना है जिसमें इन चुनौतियों से निपटने का परंपरागत ज्ञान, बुद्धिकौशल और कार्यविधियां शामिल हैं। लेकिन, जनसंख्या वृद्धि, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और तेज़ी से आगे बढ़ रही अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की पानी की बढ़ती मांग के कारण कई क्षेत्रों में पेयजल की कमी होती जा रही है जिससे महिलाओं और लड़कियों की समस्याएं बढ़ने लगी हैं क्योंकि घर में पानी की व्यवस्था का पूरा दायित्व इनका ही रहता है। गर्मियों में और सूखे की आशंका वाले तथा रेगिस्तानी इलाक़ों को महिलाएं अपनी बेटियों के साथ काफी दूर-दूर जाकर परिवार के लिए पीने का पानी लेकर आने की ज़िम्मेदारी संभालती हैं।

इसके साथ ही जहां पश्चिमी राजस्थान में प्रति वर्ष 100 मिलीमीटर वर्षा होती है और पूर्वोत्तर क्षेत्र के मावसिनरम में वार्षिक वर्षा 11,000 मिलीमीटर रहती है। भूमिगत जल के उपयोग के मामले में भारत का विश्व में सबसे पहला स्थान है और देश में हर किलोमीटर में भूजल दोहन के दस संसाधन बने हुए हैं जिससे साफ हो जाता है कि भूजल संसाधनों का क्षमता से कहीं अधिक दोहन किया जा रहा है। केंद्रीय भूजल बोर्ड की 2017 की रिपोर्ट के अनुसार क़रीब 50 प्रतिशत भूजल संसाधन गुणवत्ता या अपर्याप्त संख्या की समस्या से जूझ रहे हैं जिसका अर्थ है कि देश के 50 प्रतिशत भाग में स्थानीय तौर पर बनाए जल संसाधन लम्बे समय तक पानी की मांग

> **जल जीवन मिशन में लंबे समय तक पेयजल सप्लाई ऐसी बनाए रखने पर ध्यान दिया जा रहा है कि पानी की कमी से निपटने के वास्ते किसी भी गांव में टैंकर और रेलगाड़ियों से पानी मंगाने की ज़रूरत न पड़े और इसके लिए हैंडपंप भी न लगाने पड़ें। इसके लिए 'उपयोगिता आधारित सोच' अपनानी होगी और हर गांव में सूचना प्रौद्योगिकी की सुविधा पहुंचानी होगी ताकि स्थानीय समुदायों को सशक्त और समर्थ बनाया जा सके। ग्राम पंचायत अपनी उपसमिति ग्राम जल और स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी)/पानी समिति आदि को इन-विलेज (गांव के भीतर) जल सप्लाई प्रणाली की योजना बनाने, उसे क्रियान्वित करने, उसके प्रबंधन, संचालन और रखरखाव का ज़िम्मा संभालना होगा।**

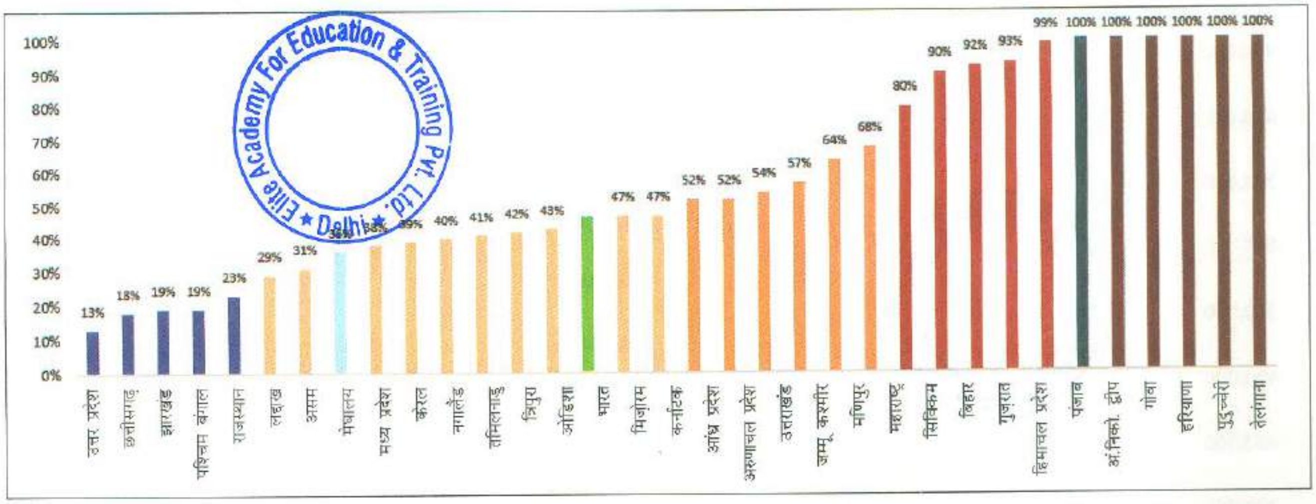

चित्र 2 : नल से पानी सप्लाई की राज्यवार स्थिति

पूरी नहीं कर पाएंगे। संकेत तो ऐसे भी हैं कि 2030 तक पानी की मांग उसकी उपलब्धता से दुगुनी हो जाएगी और ताज़ा पानी की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 2025 तक घटकर 1,293 घनमीटर रह जाएगी और वह एक प्रकार से पानी के अभाव या कहें सूखे जैसी स्थिति होगी।

इस प्रकार देश के शेष 83 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों तक और नए ग्रामीण परिवारों तक नल से स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 2019 में शुरू किए गए जल जीवन मिशन के अंतर्गत 5 वर्ष के भीतर लंबे समय तक पीने का साफ पानी मुहैया कराने की व्यवस्था करनी होगी और मौजूदा पेयजल व्यवस्था में भी बड़े सुधार करने होंगे जो वास्तव में बहुत बड़ी चुनौती है। इसका यह मतलब है कि पेयजल संसाधनों को मज़बूत बनाना होगा और दूषित पानी या अपजल को उपचारित करके फिर इस्तेमाल करने लायक बनाना होगा। यह काम बहुत बड़ा है क्योंकि हर वर्ष नल के नए कनेक्शन दिए जा रहे हैं जितने विगत 70 वर्ष में कुल मिलाकर उपलब्ध नहीं कराए गए।

केंद्र में समुदाय

जल जीवन मिशन में लंबे समय तक पेयजल सप्लाई ऐसी बनाए रखने पर ध्यान दिया जा रहा है कि पानी की कमी से निपटने के वास्ते किसी भी गांव में टैंकर और रेलगाड़ियों से पानी मंगाने की ज़रूरत न पड़े और इसके लिए हैंडपंप भी न लगाने पड़ें। इसके लिए 'उपयोगिता आधारित सोच' अपनानी होगी और हर गांव में सूचना प्रौद्योगिकी की सुविधा पहुंचानी होगी ताकि स्थानीय समुदायों को सशक्त और समर्थ बनाया जा सके। इस उद्देश्य में सफलता तभी मिलेगी जब हर घर तक लंबे समय तक पानी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी और पूरे प्रयास में पारदर्शिता अपनाई जाएगी। ग्राम पंचायत अपनी उपसमिति ग्राम जल और स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी)/पानी समिति आदि को इन-विलेज (गांव के भीतर) जल सप्लाई प्रणाली की योजना बनाने, उसे क्रियान्वित करने, उसके प्रबंधन, संचालन और रखरखाव का ज़िम्मा संभालना होगा। वीडब्ल्यूएससी में 10 से 15 सदस्य होते हैं और महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण रहता है तथा समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए भी आनुपातिक आरक्षण रखा जाता है। इस समिति को पंचायती राज अधिनियम के तहत अधिकार प्राप्त होते हैं ताकि यह अपने दायित्व को बखूबी निभा सके। फिलहाल लगभग 5 लाख वीडब्ल्यूएससी/पानी समितियां गठित की गई हैं और इन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। इससे स्पष्ट है कि ग्रामस्तर पर बहुत ही मज़बूत संस्थागत तंत्र बनाया गया है।

हर गांव को अलग इकाई माना जाता है ताकि वे पानी के

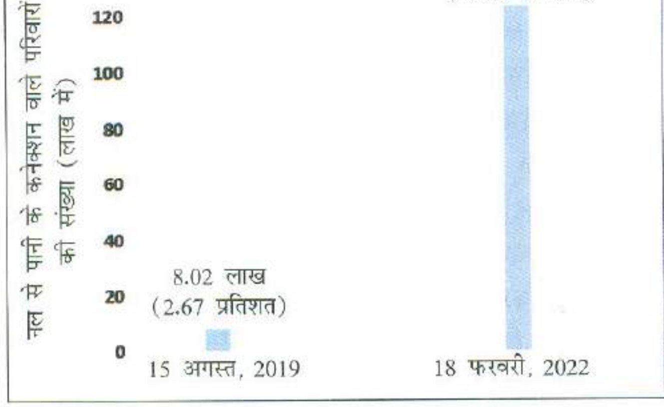

चित्र 3 : जेई/एईएस क्षेत्रों में प्रगति

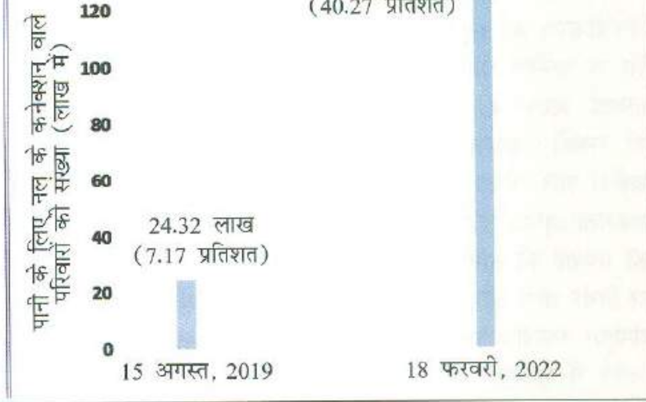

चित्र 4 : अपेक्षा वाले ज़िलों में प्रगति

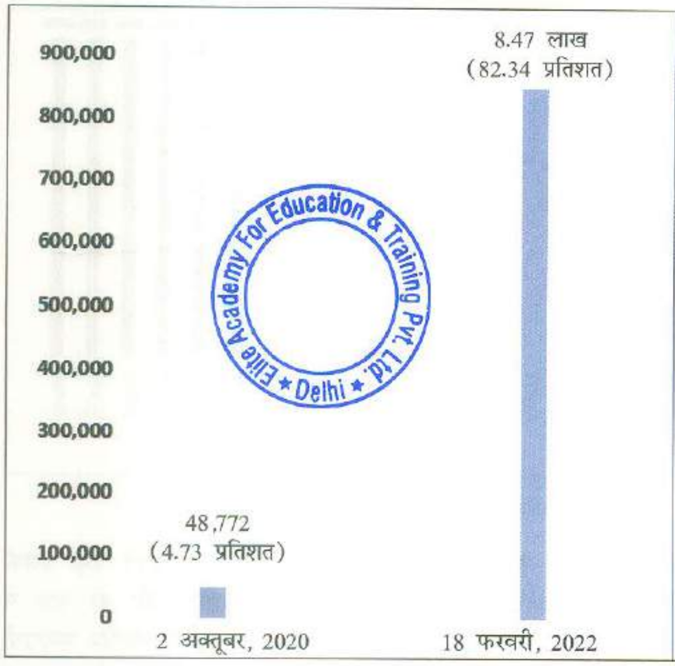

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

चित्र 5 : स्कूलों में प्रगति

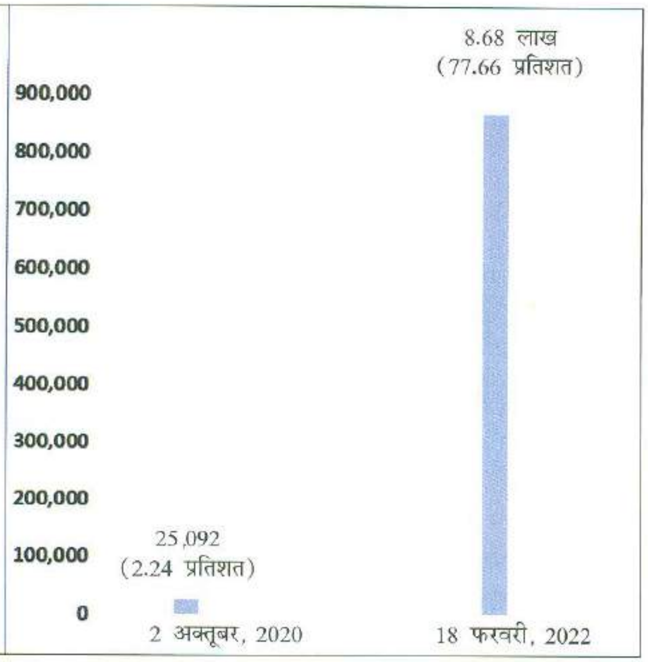

चित्र 6 : आंगनवाड़ी केंद्रों में प्रगति

मामले में सुरक्षित बन सकें और सभी गांवों के लिए पंचवर्षीय ग्राम कार्य योजना (वीएपी) तैयार की जा सके जिसका कार्यकाल 15वें वित्त आयोग के साथ ही 2021-22 से 2025-26 तक रहेगा। ग्राम कार्य योजना में स्थानीय समुदाय का सहयोग लिया जाएगा ओर चार मुख्य अंगों पर ध्यान दिया जाएगा, ये अंग हैं (i) स्थानीय पेयजल संसाधनों को मज़बूत करके उनकी क्षमता बढ़ाना; (ii) प्रत्येक घर और स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्रों, आश्रमशालाओं, स्वास्थ्य और वेलनेस केंद्रों (एचडब्ल्यूसी), सामुदायिक केंद्रों, ग्राम पंचायत भवनों आदि तक नल से पीने का पानी पहुंचाना; (iii) दूषित जल इकट्ठा करके उसे उपचारित करके फिर इस्तेमाल योग्य बनाना; और (iv) जल सप्लाई व्यवस्था की नियमित रूप से देखरेख और सारसंभाल करना।

पंचायतों को दीर्घावधि संचालन और रखरखाव का कार्य संभालने के लिए जल और स्वच्छता की मद में 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए 1.42 लाख करोड़ रुपये का बृहद अनुदान उपलब्ध कराया गया है जो 2020-21 के लिए दी गई 30,375 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता के अलावा होगा। स्थानीय ग्रामीण निकायों और पंचायतों के लिए यह निश्चित राशि उपलब्ध कराने से विकेंद्रीकरण को बहुत बल मिलेगा और वे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की निश्चित सप्लाई, बेहतर साफ-सफाई और स्वच्छता की पक्की व्यवस्था करने का बोझ सह सकेंगे। जल जीवन मिशन की दीर्घावधिक सफलता अर्थात् पाइपलाइनों के ज़रिये पानी की सप्लाई की सुनिश्चित व्यवस्था पंचायतों पर निर्भर रहेगी और उनकी सोच में बदलाव आएगा। स्थानीय ग्रामीण समुदाय को इस मिशन में शामिल करने, उसे तैयार करने, विकसित करने और सशक्त बनाने की समूची प्रक्रिया जल जीवन मिशन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है।

ग्राम पंचायत अपनी उपसमिति ग्राम जल और स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी)/पानी समिति आदि को इन-विलेज (गांव के भीतर) जल सप्लाई प्रणाली की योजना बनाने, उसे क्रियान्वित करने, उसके प्रबंधन, संचालन और रखरखाव का ज़िम्मा संभालना होगा।

ग्राम पंचायतें/वीडब्ल्यूएससी को इस धनराशि के उपयोग की उपयुक्त योजना तैयार करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि गांवों में जल सेवाओं की डिलीवरी सुनिश्चित हो सके और साथ ही इस प्रणाली को लंबे अर्से तक चलाते रखने के लिए पानी इस्तेमाल करने का शुल्क अदा करने की आदत भी बनती जाएगी।

जल जीवन मिशन विकेंद्रित, मांग पर आधारित और समुदाय द्वारा संचालित कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य स्थानीय समुदाय के लोगों में 'स्वामित्व की भावना' विकसित करना है। राज्य सरकारों/विभागों और उनके अधीनस्थ संगठनों के लिए हर घर तक पानी की सप्लाई का प्रबंध करना संभव नहीं होगा और तभी ग्राम पंचायतों और/या उनकी सहायक समितियों की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही गांवों में पेयजल की व्यवस्था संभालने का संवैधानिक दायित्व भी पंचायतों का ही है। राज्य सरकार और जल स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग (पीएचई विभाग) इस कार्य में पंचायतों की सहायता करते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था से इस क्षेत्र में दीर्घावधि स्थायित्व बना रहेगा और प्रत्येक गांव को पूर्णत: आत्मनिर्भर इकाई के रूप में विकसित करने की दिशा में बड़ी सफलता प्राप्त हो सकेगी। यही तो महात्मा गांधी के 'ग्राम स्वराज' का आत्मनिर्भर गांव बनाने का सिद्धांत भी है।

जल जीवन मिशन के तहत ग्राम समुदायों के मन में स्वामित्व की भावना विकसित करने के उद्देश्य से गांवों के भीतर ही पाइपलाइन के ज़रिए पीने का पानी उपलब्ध कराने का बुनियादी ढांचा तैयार करने के वास्ते पर्वतीय और वन क्षेत्रों के स्थानीय समुदायों को पूंजी लागत का 5

प्रतिशत तथा अन्य क्षेत्रों के ग्राम समुदायों को 10 प्रतिशत योगदान नक़द और/या श्रम अथवा अन्य रूप में करना होगा। योजना चालू हो जाने के बाद पूंजीगत व्यय का 10 प्रतिशत संबद्ध ग्राम पंचायत या वीडब्ल्यूएससी/पानी समिति को प्रोत्साहन रूप में दिया जाएगा जिससे आवर्ती कोष-रिवॉल्विंग फंड-स्थापित किया जाएगा और योजना के अंतर्गत मरम्मत और रखरखाव वगैरह के लिए इसे खर्च किया जाएगा।

इस तरह बॉटम-अप पहल अपनाने से संसाधनों, जल सप्लाई प्रणालियों और वित्तीय स्थायित्व की दीर्घकालिक व्यवस्था हो सकेगी।

क्रियान्वयन नीति

जल जीवन मिशन के लक्ष्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के उद्देश्य से एक सुविचारित नीति बनाकर लागू की गई है। जिन गांवों में पाइपलाइन की मदद से पानी सप्लाई की सुविधा है वहां सभी शेष घरों और स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्रों, ग्राम पंचायत भवनों आदि में भी पानी पहुंचाने के लिए नल-कनेक्शन लगाए जा रहे हैं। इसके लिए पुरानी फिटिंग्स को ठीक से सुधारने, उन्हें मज़बूत बनाने पर ज़ोर दिया जा रहा है और ज़रूरत होगी तो उन्हें जल जीवन मिशन के अनुकूल बनाया जाएगा।

जिन गांवों में भूजल और सतही जल अच्छी क्वालिटी का और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है वहां एकल ग्राम योजना-सिंगल विलेज स्कीम (एसवीएस) तैयार करके लागू की जा रही है क्योंकि स्थानीय लोग आसानी से इसका संचालन संभाल सकते हैं और इसका रखरखाव भी एकदम आसान होता है। जिन गांवों में पानी तो पर्याप्त मात्रा में है लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं है वहां पानी में से दूषित तत्व दूर करने के लिए उसे उपचारित किया जाता है और/या किसी भरोसेमंद संसाधन से सतही जल पर आधारित जल सप्लाई योजना चलाने की व्यवस्था की जाती है। पानी की कमी वाले, सूखे की आशंका वाले और रेगिस्तानी इलाक़ों में बड़ी मात्रा में बाहर से पानी पहुंचाने, उपचार संयंत्र और जल वितरण प्रणालियां बनाने पर विचार किया जा रहा है जिससे लंबे समय तक जल सुरक्षा बनी रहे और पानी पहुंचाने या पंप करने की संचालन लागत और रखरखाव का खर्च कम से कम रखा जा सके। दूरदराज वाली जनजातीय बस्तियों/पर्वतीय या वन क्षेत्रों में सौर ऊर्जा से संचालित और गुरुत्वाकर्षण से चलने वाली एकल जल सप्लाई प्रणालियां लगाने को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि इनके संचालन और रखरखाव पर खर्च कम आता है और इन्हें स्थानीय लोग आसानी से खुद ही चला और संभाल सकते हैं।

जल जीवन मिशन के लक्ष्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के उद्देश्य से एक सुविचारित नीति बनाकर लागू की गई है। जिन गांवों में पाइपलाइन की मदद से पानी सप्लाई की सुविधा है वहां सभी शेष घरों और स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्रों, ग्राम पंचायत भवनों आदि में भी पानी पहुंचाने के लिए नल-कनेक्शन लगाए जा रहे हैं। इसके लिए पुरानी फिटिंग्स को ठीक से सुधारने, उन्हें मज़बूत बनाने पर ज़ोर दिया जा रहा है और ज़रूरत होगी तो उन्हें जल जीवन मिशन के अनुकूल बनाया जाएगा। जिन गांवों में भूजल और सतही जल अच्छी क्वालिटी का और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है वहां एकल ग्राम योजना-सिंगल विलेज स्कीम (एसवीएस) तैयार करके लागू की जा रही है क्योंकि स्थानीय लोग आसानी से इसका संचालन संभाल सकते हैं और इसका रखरखाव भी एकदम आसान होता है।

कठिन क्षेत्रों में नल से पीने का पानी पहुंचाने की पक्की व्यवस्था की आवश्यकता को समझते हुए पेयजल की खराब क्वालिटी से जूझ रही बस्तियों, सूखे की आंशका वाले और रेगिस्तानी क्षेत्रों, जापानी एनसेफेलाटिस/एक्यूट एनसेफेलाइटिस सिंड्रोम और अपेक्षा रखने वाले क्षेत्रों, एससी/एसटी बहुत गांवों और सांसद आदर्श ग्राम योजना वाले गांवों को प्राथमिकता दी जा रही है। बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य और उनके कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से वर्ष 2020 में गांधी जयंती को विशेष अभियान शुरू करके स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों और आश्रमशालाओं में पीने का पानी, रसाई में खाना पकाने के लिए पानी, हाथ धोने का पानी और शौचालय में इस्तेमाल का पानी पहुंचाने की व्यवस्था की गई थी।

इस कार्य की व्यापकता को देखते हुए जल जीवन मिशन को पूरी तरह मिशन-भावना से चलाया जा रहा है जिसके लिए 'व्यवस्था में प्रबंधन बदलने' को अपनाया गया और समूचे देश में जल जीवन मिशन को बड़े अवसर के रूप में देखा गया क्योंकि मौजूदा धन राशि 2024 तक उपलब्ध रहेगी और प्रत्येक राज्य का यह कर्त्तव्य है कि नागरिकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराके उनके जीवन स्तर को सुधारने में मदद करें।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर राज्य/केंद्रशासित प्रदेश ने 'हर घर जल' अभियान में 100 प्रतिशत सफलता (कवरेज) प्राप्त करने के उद्देश्य से इन पहलुओं को शामिल करके 'वार्षिक कार्य योजनाएं' चलाईं।

परियोजना के नतीजे

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच सेवाओं और सुविधाओं की दृष्टि से मौजूद अंतर को दूर करने के प्रयास में विशेषकर अभाव वाले क्षेत्रों में 'तेज़ी से और बड़े पैमाने पर' योजना लागू करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि कोई भी वंचित न रह जाए। जहां शहरी इलाक़ों में आमतौर पर उम्मीद रखी जाती है कि पानी की सप्लाई चौबीसों घंटे बनी रहेगी वहीं अब ग्रामीण इलाक़ों से भी ऐसी ही अपेक्षा की जाने लगी है। अंतर सिर्फ इतना है कि ग्रामीण समुदाय के लिए आवेरहैड टैंक साझा होता है जबकि शहरी इलाक़ों में हर घर में अपना अलग ओवरहैड टैंक रहता है। फिर, लोगों को सीधे नल का पानी पीने की सुविधा मिलनी चाहिए ताकि जीवन सरल बनाने का लक्ष्य आगे बढ़ाया जा सके और सब घरों में पानी साफ करने के लिए प्योरिफायर वगैरह लगाने की ज़रूरत न पड़े। अनेक उन्नत देशों में यह सुविधा उपलब्ध हो चुकी है और भारत में इस दिशा में प्रयास ज़ोरों पर हैं।

कौशल विकास ज़रूरी

गांवों में कुशल मानवीय संसाधन जुटाने की सुनिश्चित व्यवस्था के लिए स्थानीय युवाओं को राजमिस्त्री, प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, मोटर मैकेनिक, फिटर, पंप ऑपरेटर आदि के रूप में तैयार करने का व्यापक कार्यक्रम चलाया जा रहा है ताकि वे संचालन और रखरखाव

के सभी कार्य स्वयं ही बखूबी कर सकें। साथ ही, हर गांव में पांच-पांच महिलाओं को फील्ड टेस्ट किट (एफटीके) इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग भी दी जाती है ताकि वे वहां सप्लाई किए जा रहे पानी की गुणवत्ता जांच सकें, स्वच्छता आंकने के सर्वेक्षण कर सकें और आंकड़ों को जलजीवन मिशन के पोर्टल पर अपलोड कर सकें। पाइप, मोटर, सीमेंट, इस्पात, वॉल्व वगैरह से जुड़े मैन्युफैक्चरिंग उद्योगों का भी तेज़ी से विस्तार हो रहा है। स्थानीय युवाओं को अपने ही गांव में रोज़गार पाने के अवसर भी बढ़ रहे हैं।

Elite Academy for Education & Training Pvt. Ltd. Delhi

भागीदारी और क्षमता निर्माण

जल जीवन मिशन के मूल मंत्र 'भागीदारी प्रक्रिया, बदलते जीवन के अनुरूप' 'हर घर जल' का सामूहिक लक्ष्य पूरा करने हेतु 185 संगठनों का सहयोग लिया जा रहा है जिनमें संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां, न्यास और फाउंडेशन शामिल हैं। इन संगठनों को क्षेत्र भागीदारों के तौर पर शामिल किया गया है ताकि वे इस समूचे अभियान की सफलता के लिए अपने संसाधन और प्रयास मुहैया कराते रहें। जन स्वास्थ्य इंजीनियरों की क्षमता का निर्माण करने, उन्हें नए कार्य के अनुरूप ढालने और प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से व्यापक कार्यक्रम चलाया गया है तथा देश के 104 जाने माने संस्थानों का इस कार्य में सहयोग लिया जा रहा है। ये संस्थान मुख्य संसाधन केंद्रों की भूमिका निभाएंगे। राज्य सरकारों ने ग्राम पंचायतों/ सीडब्ल्यूएससी/ पानी समितियों की मदद के लिए क़रीब 14 हज़ार स्थानीय स्वैच्छिक संगठनों, ग्राम संगठनों, सीबीओ, महिला स्वसहायता समूहों आदि को भी इस मिशन में शामिल किया है। इन प्रयासों से ही जल जीवन मिशन ने जन आंदोलन का रूप ले लिया है।

जन स्वास्थ्य इंजीनियरों को सीखने के अवसर प्रदान करके क्षमता निर्माण करने के वास्ते कोलकाता में राष्ट्रीय पेयजल, स्वच्छता और गुणवत्ता केंद्र (एनसीडीडब्ल्यूएसक्यू) की स्थापना जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग के शीर्ष संस्थान के रूप में की गई है। यह संस्थान 'हब एंड स्पोक' मॉडल यानी 'धुरी और तार' के मॉडल को अपनाएगा और मुख्य संसाधन केंद्र (केआरसी), दो विशिष्ट केंद्रों और पांच प्रोफेसर पीठों के साथ मिलकर काम करेगा जो देश के विभिन्न भागों में बनाए जाएंगे। ये सभी संस्थान मिलकर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, शिक्षा और शिक्षण कार्यक्रम चलाने के साथ ही शोध कार्य और नवाचार तथा आउटरीच और परामर्श सेवाएं भी उपलब्ध कराएंगे।

> **इस क्षेत्र में नवाचार प्रौद्योगिकी अपनाने की बहुत ज़रूरत है। विशेष रूप से सीवेज ट्रीटमेंट, मानव शौच को वहीं जलाकर उससे सौर ऊर्जा तैयार करने जैसी प्रौद्योगिकियां विकसित करना बेहद ज़रूरी है। इससे शहरी इलाक़ों में शौचालयों की फ्लश टंकियों में ताज़ा पानी की खपत रोकने में खास मदद मिलेगी। चारदिवारी में बने आवासों और नई बन रही कॉलोनियों में रहने वालों को तो ऐसी टेक्नोलॉजी की तुरंत आवश्यकता है। सेंसरचालित आईओटी प्रणालियों के जल सप्लाई को मापने और उसकी मॉनीटरिंग करने, आंकड़ों के समन्वयन के लिए डैश बोर्ड और पानी के नमूनों की जांच और विश्लेषण करने के लिए सेंसर चालित आईओटी प्रणालियों के प्रयोग से सेवाओं की डिलीवरी और शिकायतों के निवारण की पारदर्शी पक्की व्यवस्था सुनिश्चित हो जाएगी।**

पानी की गुणवत्ता का आकलन और उसकी निगरानी

जल जीवन मिशन के तहत पानी की गुणवत्ता पर नज़र रखने के लिए देश के विभिन्न गांवों की क़रीब 10 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है जिससे स्पष्ट हो जाता है कि पेयजल सप्लाई कार्यक्रम के व्यापक विस्तार पर कितना ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है। देशभर में प्रयोगशालाओं का मानकीकरण कर उन्हें अपग्रेड भी किया जा रहा है। पानी के नमूनों की जांच की सुविधा मामूली लागत पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 2000 से ज़्यादा जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाएं आम लोगों के लिए खोली गई हैं और लोग जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली (डब्ल्यूक्यूएमआईएस) पर नज़दीकी प्रयोगशाला खोज सकते हैं। घरों में और ग्राम-स्तर पर पेयजल गुणवत्ता की जांच के क्षेत्र में नवाचार खोजने की बड़ी चुनौती सामने आ रही है।

नवाचार और आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग

नई प्रौद्योगिकियां खोजने और नवाचार-आधारित समाधान ढूंढने के उद्देश्य से भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (पीएसए) की अध्यक्षता में तकनीकी समिति गठित की गई है जिसमें राज्यों के प्रतिनिधि, वैज्ञानिक और नवाचार विशेषज्ञ भी शामिल किए जाएंगे। पारदर्शिता, जवाबदेही, धन का प्रभावी उपयोग और सेवाओं की सुनिश्चित डिलीवरी की पक्की व्यवस्था करने की दिशा में भी अनेक उपाय किए गए हैं जिनसे डिजिटल प्रशासन को बढ़ावा मिलेगा। सार्वजनिक ऑनलाइन जेएमएम डैशबोर्ड पर राज्यवार/ केंद्रशासितप्रदेशवार/ज़िलावार और ग्रामवार प्रगति देखी जा सकेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में नलों से पानी की सप्लाई की स्थिति पर निगाह रखी जा सकेगी। दैनिक जल सप्लाई मापने और उस पर निगाह रखने के वास्ते 100 से ज़्यादा गांवों में आंकड़े ऑटोमेटिक तरीके से अपलोड करने के उद्देश्य से सेंसरचालित आईओटी पॉयलेट भी लगाए जा रहे हैं। एफटीके किट्स से और प्रयोगशालाओं द्वारा पानी की गुणवत्ता जांच की रिपोर्टों के आधार पर डब्ल्यूक्यूएमआईएस भी विकसित कर लिए गए हैं।

जल जीवन मिशन के लिए 3.6 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और इसका उद्देश्य केवल बुनियादी सुविधाओं का निर्माण नहीं है बल्कि मुख्य रूप से सुनिश्चित दीर्घावधि सेवा डिलीवरी की व्यवस्था करना है। अतः सॉफ्टवेयर हिस्सों पर ज़ोर देते हुए कुल आबंटित राशि का 2 से 5 प्रतिशत डब्ल्यूक्यूएमआईएस तथा प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, आईईसी, तीसरे पक्ष से निरीक्षण, आईएसए के सहयोग जैसी मदों पर खर्च के लिए रखा गया है।

विकास के लिए जल सुरक्षा

जल की उपलब्धता और उसके इस्तेमाल को समझें तो पता चलेगा कि कुल उपलब्ध ताज़ा पानी में से क़रीब 85 प्रतिशत तो

खेती में इस्तेमाल हो जाता है और 10 प्रतिशत की खपत उद्योगों में होती है और तब जाकर सिर्फ 5 प्रतिशत के क़रीब पानी पीने के लिए और घरेलू उपयोग के लिए बचता है। सारा पानी 10 से 40 दिन की वर्षा और हिमालय के ऊपरी इलाक़ों में होने वाले हिमपात से मिलता है और यही पानी ज़मीन की सतह पर या ज़मीन की सतह के नीचे भंडारित हो जाता है। पूरे साल इसी पानी से पेयजल की आवश्यकताएं पूरी की जाती हैं। इसलिए जिस तरह अनाज को बाद के इस्तेमाल के हिसाब से सुरक्षित भंडारों में रखा जाता है ठीक उसी प्रकार से 5 प्रतिशत पानी को भरपूर सावधानी से भंडारण करके रखना चाहिए। इसकी बर्बादी हर तरीक़े से रोकी जानी चाहिए और पानी बहुत सोच-समझकर इस्तेमाल करना चाहिए तथा यह भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि जल संसाधनों में प्रदूषण न पहुंचे। पर्यावरण संरक्षण और मानवजनित पहलुओं से जुड़े मुद्दों के कारण पानी की बढ़ती मांग पूरी करने के लिए नए बांधों का निर्माण करना भी अब बेहद मुश्किल होता जा रहा है।

ऐसे में जल सुरक्षा प्राप्त करने के लिए बस वर्षा के पानी का संरक्षण, जल प्रवाह माध्यमों (एक्विफर) को फिर से चालू करना, जलाशयों और कुंओं को और गहरे करना ही विकल्प रह गए हैं। साथ ही, पानी का उपयुक्त सुरक्षित भंडारण करना और बहुत सोच-समझकर ही पानी का इस्तेमाल करना नितांत आवश्यक है। रिसकर ज़मीन के नीचे जाने वाले पानी को भी साफ रखकर पूरी किफ़ायत से इस्तेमाल करना होगा क्योंकि देश के 743 ज़िलों में से 256 में तो पहले ही पानी की बेहद कमी हो चुकी है। इसके लिए पानी का बजट बनाकर पूरी सूझबूझ से उसे इस्तेमाल करना होगा। पानी के इस्तेमाल का ढंग भी बदलना होगा। ऐसी फसलें अपनानी होंगी जो कम पानी से तैयार हो जाएं और सिंचाई के लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर विधियां अपनाकर पानी बचाना होगा। इस प्रकार कृषि में इस्तेमाल किए जाने वाले पानी को बचाकर पीने के और घरेलू इस्तेमाल के लिए काम में लाया जा सकेगा। इससे जल सप्लाई प्रणालियां भी अधिक समय तक काम करती रह सकेंगी।

इसलिए 2019 में जल संसाधन और जल सप्लाई मंत्रालयों का विलय करके नए जलशक्ति मंत्रालय का गठन किया गया ताकि जल क्षेत्र के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाकर सघन प्रयास किए जा सकें। साथ ही, पानी को सभी की चिंता बनाने और जल संरक्षण अर्थात् पानी बचाने को सबसे बड़ी प्राथमिकता देने की पहल के तौर पर जल शक्ति अभियान शुरू किया गया। पानी के संसाधन बनाने में तेज़ी लाने के लिए मिशन मोड में यह अभियान चलाया गया और पानी की बचत का महत्व जन-जन को समझाने के लिए ज़ोरदार प्रचार-अभियान भी शुरू किया गया।

जल संसाधनों को लंबे अर्से तक जीवित रखने के लिए जल सुरक्षा, जल संरक्षण और पानी के इस्तेमाल में किफ़ायत जैसे कार्यक्रम गांवों में प्राथमिकता के आधार पर चलाए गए। मनरेगा, अटल बिहारी योजना, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसे कार्यक्रमों से ग्राम स्तर पर ही संसाधनों को सशक्त और सक्षम बनाने का मौक़ा मिलेगा।

देश में जलाशयों और कुंओं आदि की सुरक्षा की दृष्टि से खुले में शौच की समस्या पर ध्यान दिया गया जिससे लोगों के व्यवहार में भी बड़ा बदलाव आया और हाईजीन तथा साफ-सफाई की स्थिति में भी सुधार हुआ। इसी प्रकार ठोस और तरल कचरे के प्रबंधन और प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

उपलब्धि

मिशन पूरे ज़ोर से प्रयास कर रहा है और इन प्रयासों के फलस्वरूप ही देश के क़रीब 9 करोड़ (46 प्रतिशत) ग्रामीण परिवारों तक नल से पीने का साफ पानी पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। 101 जिलों के 1.40 लाख गांवों के हर परिवार को सीधे नल से पीने का साफ पानी प्राप्त हो रहा है। तीन राज्यों- गोवा, हरियाणा और तेलंगाना तथा तीन केंद्रशासित प्रदेशों- अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह, दमण और दीव तथा दादरा और नागर हवेली और पुदुच्चेरी में 'हर घर जल' योजना लागू हो चुकी है और वहां सभी घरों को सीधे नलों से ही पीने का साफ पानी मिल रहा है। जलजीवन मिशन के तहत इतनी तीव्र गति और बड़े व्यापक पैमाने पर काम चल रहा है और ग्रामीण इलाक़ों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लक्ष्य पर बराबर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

भारत अपनी प्रभावी वॉश (डब्ल्यूएएसएच) नीतियों के फलस्वरूप ही वैश्विक मंच पर शानदार उदाहरण बनकर उभरा है क्योंकि ये नीतियां इतने व्यापक पैमाने पर लागू की जा रही हैं और इनसे लोगों के व्यवहार में बदलाव भी आया है। अब भारत निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है कि वह अन्य देशों और खासकर विश्व के ग़रीब देशों को अपनी जानकारी और अनुभव दे सके।

आगे का मार्ग

जल जीवन मिशन का आगे का प्रयास नियामक संस्थाओं, प्रमाणीकरण की व्यवस्था और इंजीनियरों तथा नवाचार विशेषज्ञों के लिए नई स्थायी प्रौद्योगिकियां खोजने का काम सिखाना रहेगा। इस क्षेत्र में नवाचार प्रौद्योगिकी अपनाने की बहुत ज़रूरत है। विशेष रूप से सीवेज ट्रीटमेंट, मानव शौच को वहीं जलाकर उससे सौर ऊर्जा तैयार करने जैसी प्रौद्योगिकियां विकसित करना बेहद ज़रूरी है। इससे शहरी इलाक़ों में शौचालयों की फ्लश टंकियों में ताजा पानी की खपत रोकने में खास मदद मिलेगी। चारदिवारी में बने आवासों और नई बन रही कॉलोनियों में रहने वालों को तो ऐसी टेक्नोलॉजी की तुरंत आवश्यकता है। सेंसरचालित आईओटी प्रणालियों के जल सप्लाई को मापने और उसकी मॉनीटरिंग करने, आंकड़ों के समन्वयन के लिए डैश बोर्ड और पानी के नमूनों की जांच और विश्लेषण करने के लिए सेंसर चालित आईओटी प्रणालियों के प्रयोग से सेवाओं की डिलीवरी और शिकायतों के निवारण की पारदर्शी पक्की व्यवस्था सुनिश्चित हो जाएगी।

इस मिशन का उद्देश्य स्वास्थ्य और जल सप्लाई के आंकड़ों को समन्वित करके बीमारियों पर निगरानी रखना है। नई प्रौद्योगिकी अपनाने, शीघ्र और अद्यतन सूचना उपलब्ध कराने से नए भारत की आकांक्षाएं पूरी करने में कामयाबी मिलेगी। वास्तविक उद्देश्य तो ऐसी जन सुविधाएं बनाना है जिसमें लंबे समय तक सेवाएं मिलती रहें और आशा है कि अन्य संबद्ध क्षेत्र भी इस दृष्टिकोण को अपनाने पर सहमत होंगे। भारत अब ऐसे भविष्य की दिशा में अग्रसर है जहां शौचालय गांवों में जल-सप्लाई और कृषि क्षेत्रों के लिए सेवा केंद्र की भूमिका निभाएंगे। साथ ही, देश आर्थिक समृद्धि में सर्वांगीण विकास करने की ओर भी तेज़ी से बढ़ रहा है। ■

(लेख में व्यक्त विचार व्यक्तिगत हैं।)

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

डिजिटल पहचान

डॉ सौरभ गर्ग

ऑनलाइन सत्यापन की विशिष्ट डिजिटल पहचान 'आधार' भारत में डिजिटल क्रांति की मुख्य नींव रही है। इस सार्वजनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर (बुनियादी ढांचे) ने एक दशक के समय में ही सरकार द्वारा चलाए जा रहे कल्याण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में ज़बरदस्त क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। प्रत्येक नागरिक के लिए 12 अंकों वाली विशिष्ट पहचान (आईडी) संख्या पर आधारित इस प्रणाली से वित्तीय समावेशन, कल्याणकारी सेवाओं तक पहुंच, कर अनुपालन, खुदरा भुगतान और सरकारी सब्सिडी के प्रबंधन आदि में महत्वपूर्ण सुधार आया है। आधार इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्लॉकचेन्स, आईटीओ जैसी नई प्रौद्योगिकियों के समन्वयन से देश के मौजूदा और भावी क़ानूनों की सीमाओं का पालन करते हुए भी बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। फ़िनटेक अर्थात् आर्थिक-तकनीकी सेवाओं के विशाल पैमाने पर विस्तार की प्रक्रिया में संभवतः यह 'आधार' व्यवस्था अकेली सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है।

भारत सरकार ने जब 2009 में आधार परियोजना शुरू की थी तो आवश्यक प्रौद्योगिकीय बुनियादी ढांचा बनाना और देश के दूर-दूर तक के क्षेत्रों में रह रहे 130 करोड़ लोगों तक पहुंच पाना एक बहुत कठिन चुनौती लग रहा था क्योंकि विशिष्ट आधार संख्या निर्धारित करने में किसी भी तरह की पुनरावृत्ति नहीं होने देना नितांत अनिवार्य शर्त थी।

2014 में यह परियोजना जनधन पहल के साथ जोड़ दी गई जो देश में बड़ी संख्या में बैंकिंग सुविधाओं से वंचित लोगों तक ये सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। जनधन योजना के तहत खोले गए खातों को मोबाइल नंबरों और आधार नंबरों से जोड़कर जनधन-आधार-मोबाइल यानी जेएएम का त्रिकोणीय प्रावधान प्रारंभ किया गया। इस समय देश में 80 प्रतिशत लोगों का बैंक खाता है जबकि यह कार्यक्रम शुरू होने के समय सिर्फ 40 प्रतिशत लोगों के ही बैंक खाते थे। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान

लेखक यूआईडीएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। ईमेल: ceo@uidai.gov.in

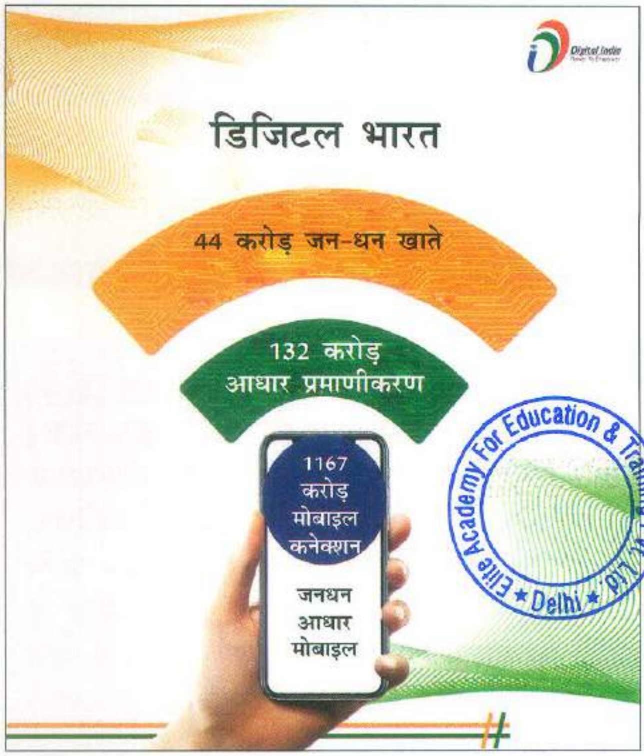

Elite Academy For Education & Training Pvt Ltd ★ Delhi ★

निगम (एनपीसीआई) द्वारा विकसित कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आधार भुगतान सेतु (एपीबी) अब देश की सामाजिक सुरक्षा और नक़दी हस्तांतरण कार्यक्रम में तेज़ी लाने वाला सबसे प्रमुख माध्यम है। इस समय केंद्र सरकार 314 कार्यक्रमों/योजनाओं के लाभार्थियों के खातों में सीधे राशि भेजने के लिए एपीबी-चालित व्यवस्था अपना रही है। राज्य सरकारों के 450 अन्य कार्यक्रमों के तहत लाभार्थियों को सीधे खाते में पैसा भेजने में डिजिटल व्यवस्था अपनाई जा रही है। मैककिंसे ग्लोबल इंस्टीट्यूट ने मार्च, 2014 में जारी रिपोर्ट 'डिजिटल इंडिया' में कहा था कि ''भारत में तेज़ी से डिजिटीकरण लागू किए जाने की प्रक्रिया को तेज़ करने में सार्वजनिक क्षेत्र की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आधार व्यवस्था का व्यापक विस्तार करने में 'आधार' ने बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान किया है।''

वित्तीय सेवाओं में विस्तार लाने की क्षमता

आधार अपनी विशेष खूबियों के कारण पहचान का बेहतर माध्यम (दस्तावेज़) बनकर उभरा है।

- 'आधार में अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी)' का पूरी तरह पालन किया जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक का कहना है कि यदि बैंक खाता खोलते समय प्रस्तुत किए जाने वाले आधिकारिक रूप से मान्य दस्तावेज़ (कार्ड) में आवश्यक व्यक्तिगत विवरण और निवास का पता अंकित है तो फिर कोई अन्य सबूत पेश करने की ज़रूरत नहीं है। आधार में ये दोनों विवरण शामिल हैं और तभी यह (छोटे खाते खोलने के लिए) अपने आप में पर्याप्त वैध दस्तावेज़ हैं।
- इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी (ई-केवाईसी): आधार प्लेटफॉर्म ई-केवाईसी सेवा उपलब्ध कराता है। देशवासियों की सहमति से उनका भौगोलिक विवरण और फोटो डिजिटल माध्यम से सेवा प्रदाता के साथ शेयर किया जाता है। इस विधि से ग्राहक अधिग्रहण (उपलब्धता) प्रक्रिया बेहद सरल हो जाती है।
- आधार सत्यापन का अकेला पर्याप्त प्रमाण है - आधार के ज़रिए सत्यापन करने की सरलता को देख-समझकर बैंक, बीमा कंपनियां, शेयर दलाली में लगी कंपनियां और सरकारी प्रतिभूतियां भी नए ग्राहकों को आकर्षित करने में इस प्रक्रिया को अपनाने में लगी हैं जिससे देशवासियों को डिजिटल सेवाओं के लाभ प्राप्त करने में मदद मिल रही है। नागरिक इस योजना में शामिल होने के बाद सत्यापन के लिए अपना आधार नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं और जितनी बार चाहें इसे अपनी पहचान के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। आधार उपलब्ध कराने के बाद नागरिकों को ये सेवाएं, लाभ और सब्सिडी पाने के वास्ते पहचान के लिए हर बार कोई अन्य प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं पड़ती।

भारत का डिजिटल उपभोक्ता आधार विश्व में दूसरा सबसे बड़ा है और सभी वर्गों के लोग प्रौद्योगिकी से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ महसूस कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था के मुख्य पहलुओं तथा निजी क्षेत्र में नवाचार और निवेश के लिए इंटरनेट एक्सेस (पहुंच) और प्रयोग बढ़ने से ही भारत में डिजिटल प्रक्रिया अपनाने की गति इतनी तेज़ करने में सफलता प्राप्त हुई है। सरकार ने इस प्रक्रिया को बढ़ावा देने और इसमें तेज़ी लाने के उद्देश्य से मज़बूत राष्ट्रीय डिजिटल आधार-सार्वजनिक प्लेटफॉर्म और इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित किया है और इसके लिए अनेक डिजिटल एप्लीकेशंस और सेवाएं शुरू की हैं।

भारत में वित्तीय डिजिटल व्यवस्था की नींव को मज़बूत बनाने में एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) और भारत इंटरफेस फॉर मनी (भीम)/भारत क्विक रेस्पांस (क्यूआर) कोड, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट ऐक्सेस और रिट्रीवल के लिए डिजिलॉकर, ग्राहकों की पहचान की डिजिटल पुष्टि करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक 'नो योर कस्टमर' (ई-केवाईसी) व्यवस्था, ई-हस्ताक्षर, एपीबी, आधार एनेबल्ड भुगतान प्रणाली (एईपीएस) और भारत बिल पेमेंट सिस्टम (बीबीपीएस)- जैसे विभिन्न एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस-एपीआई सैट की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भविष्य में भी डिजिटल माध्यम से पहचान पुष्टि प्रणालियों की व्यापक रेंज़ विकसित होती रहेंगी जिनमें नागरिकों की निजता पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। भारत सरकार ने 2014 में प्रधानमंत्री जन-धन योजना आरंभ करके राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन अभियान को सुचारू ढंग से आगे बढ़ाया और इस योजना के अंतर्गत आधार कार्ड से पहचान की पुष्टि करके लाखों लोगों के बैंक खाते खोले गए। 26 जनवरी, 2022 तक 44 करोड़ 58 लाख जनधन बैंक खाते खोले जा चुके थे। अब भारतीयों के जीवन में डिजिटल समाधान

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा विकसित कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आधार भुगतान सेतु (एपीबी) अब देश की सामाजिक सुरक्षा और नक़दी हस्तांतरण कार्यक्रमों में तेज़ी लाने वाला सबसे प्रमुख माध्यम है।

बहुत अहम हिस्सा बनते जा रहे हैं।

वैश्विक बायोमेट्रिक पहचान कार्यक्रम 'आधार' के संदर्भ में प्रयोग किया जाने वाला शब्द 'इंडिया स्टैक' और इससे संबद्ध खुले एपीआई का पूरा सैट भारत में डिजिटल नींव को मज़बूत करने और देश के डिजिटल विकास में ज़बरदस्त भूमिका निभा रहे हैं। मूल सिद्धांतों के आधार पर यह सिद्ध हो गया है कि डिजिटल सेवाओं से बड़ा लाभ यह है कि स्वयं मौजूद हुए बिना और कहीं से भी उपस्थिति का प्रमाण देने की इस व्यवस्था में कोई कागज़ी कार्रवाई नहीं करनी पड़ती या फिर डिजिटल रिकॉर्ड पर आधारित होने के कारण नक़दी लेनदेन की ज़रूरत नहीं पड़ती और इस प्रकार सही मायनों में वैश्विक डिजिटल भुगतान किए जा सकते हैं और डिजिटल पहुंच प्राप्त की जा सकती है; या 'सहमति के आधार पर' या डाटा प्रमाणीकरण के लिए खाताधारक तक सुरक्षित पहुंच प्राप्त की जा सकती है। वैश्विक प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं के विकास से निजी क्षेत्र का निवेश बहुत तेज़ी से बढ़ा है और नवाचार भी व्यापक रूप से अपनाए जा रहे हैं जिससे भारत में डिजिटल उपभोक्ता क्षेत्र का ज़बरदस्त विस्तार हुआ है।

वैश्विक बायोमेट्रिक पहचान कार्यक्रम आधार के संदर्भ में प्रयोग किया जाने वाला शब्द 'इंडिया स्टैक' और इससे संबद्ध खुले एपीआई के पूरे सैट ने भारत में डिजिटल कार्यक्रम की नींव को मज़बूत करने और देश के डिजिटल विकास में ज़बरदस्त भूमिका निभाई है।

फ़िनटेक यानी आर्थिक-तकनीकी नवाचार क्षेत्र का बहुत तेज़ी से विस्तार हुआ है। एक सर्वेक्षण के अनुसार फ़िनटेक आंदोलन में भारत को विश्व में दूसरे स्थान पर रखा गया है और बताया गया है कि देश के 76 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने माना है कि वे वित्तीय सेवाओं के लिए कम से कम एक गैर-परंपरागत फर्म चला रहे हैं। सरकार ने नीति प्रयोगशाला में, नियामक सैंडबॉक्सों, इनक्यूबेशन सेंटरों और फ़िनटेक तथा आईओटी आधारित नई एप्लीकेशंस के द्वारा निजी क्षेत्र में नवाचार के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराया है। निजी क्षेत्र में नवाचार प्रक्रिया को सक्रिय करना डिजिटल भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत महत्वपूर्ण है।

इस फ़िनटेक लहर का लाभ लेने के लिए बैंक फ़िनटेक स्टार्टअप कंपनियों को सहायता और सहयोग दे रहे हैं। भारत के डिफ्रेंशियल बैंकों (भुगतान और छोटे वित्त बैंकों) ने भी उन वित्तीय सेवाओं के समूचे समूह में बड़े डिजिटल नवाचार अपनाए हैं जो बैंकिंग नियामक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं तथा इस उद्देश्य के लिए वित्तीय क्षेत्र में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अपनाने का संभावित प्रारूप तैयार किया जा चुका है।

आधार-प्रणाली वाली माइक्रो एटीएम व्यवस्था अच्छी तरह प्रयोगा की जा रही है और इस प्रणाली में कई अन्य एप्लीकेशन विकसित की जा सकती हैं। यूआईडीएआई भी नागरिकों को बीमा और निवेश की अन्य नई सेवाएं उपलब्ध कराने के तरीक़े खोजने में लगा है।

यूपीआई के माध्यम से लेनदेन की संख्या बढ़कर इस वर्ष जनवरी में 460 करोड़ को पार कर चुकी थी। भुगतान करने, शॉपिंग में और ई-कॉमर्स उद्योगों की दृष्टि से यह बढ़ोतरी बहुत ज्यादा है। यह भी एकदम स्पष्ट हो गया है कि इस समूची प्रक्रिया में डिजिटल पहचान व्यवस्था का भी बहुत बड़ा योगदान है। इंडिया स्टैक और इसके इस्तेमाल से जुड़े टेक्नोलॉजी विकास इस क्षेत्र में ज़बरदस्त सफलता प्राप्त करने में सहायक रहे हैं। टेक्नोलॉजी में निरंतर विकास होता रहना चाहिए। आधार का बुनियादी ढांचा भी इससे अलग नहीं है और कई प्रकार से इसका भी विकास हो रहा है। देशवासियों को सीधे उनके खातों में भुगतान पहुंचने की व्यवस्था से यह अच्छी तरह सिद्ध हो चुका है।

डिजिटल पहचान के तौर पर आधार से हम टेक्नोलॉजी के हिसाब से कई और लाभ प्राप्त करने की आशा रखते हैं। यूआईडीएआई टीम इस चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार है। एआई/एमएल और अनुसंधान तथा विकास में लगी टीमें मौजूदा चुनौती से निपटने में बहुत सही काम कर रही हैं। नए आधार कार्ड में एक आधुनिकतम और पूर्णतः सुरक्षित क्यूआर कोड है जिसमें फोटो भी लगा है। क्यूआरकोड जैसे आधार की पुष्टि के ऑफलाइन प्रमाणन जैसे तरीकों से विभिन्न उद्देश्यों के लिए लोगों

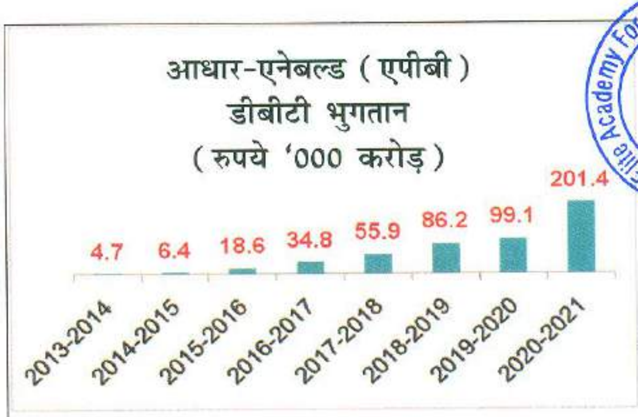

850 करोड़ लेनदेन और 5.75 लाख करोड़ रु नक़द लाभ
120 करोड़ खाते आधार के माध्यम से खोले
75 करोड़ आधार से जुड़े विशिष्ट खाते

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

1200 करोड़ एईपीएस लेनदेन
40 करोड़ सफल लेनदेन प्रतिमाह
50 लाख माइक्रो एटीएम : 35 लाख लेनदेन प्रति माह

की पहचान की पुष्टि के आसान तरीक़े भी उपलब्ध होते हैं।

हमारा मानना है कि ब्लॉकचेन्स, आईओटी जैसी नई प्रौद्योगिकियों के साथ तालमेल करके आधार इंफ्रास्ट्रक्चर देश के मौजूदा और भावी क़ानूनी सीमा के दायरे में रहकर भी सभी उपयोगी सुविधाएं उपलब्ध करा सकता है। फिर भी, यह समझना-जानना बहुत ज़रूरी है कि इस डाटा को लोगों के लाभ के लिए और किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। फ़िनटेक सेवाओं के व्यापक विस्तार में आधार प्रणाली भारत में सबसे विश्वस्त अकेली व्यवस्था है।

एईपीएस के माध्यम से नक़दी निकासी, बैलेंस चैक करने जैसी बैंकिंग सेवाएं लोगों को घर बैठे मिल रही हैं। यह व्यवस्था गांव-देहात के लोगों के लिए और खासकर वैश्विक महामारी के दौर में बड़ा वरदान साबित हुई है। चूंकि 'फ़िनटेक' इस समय वित्तीय क्षेत्र में बहुत बड़ा अहम बन चुका है तो ऐसे में इसके अनुरूप पहचान प्रणाली विकसित करना भी न केवल मददगार है बल्कि आवश्यक हो गया है।

अभी तो यह डिजिटल क्रांति की शुरुआत है और 2022 में तथा आगे चलकर भी बहुत सी नई संभावनाएं हैं। चेहरे की पहचान की पुष्टि और जीवित होने/न होने के प्रमाण जैसे पहलू वीडियो केवाईसी की असल ताक़त या कहें कि रीढ़ हैं और इन सुविधाओं को अब अधिकांश फ़िनटेक/बीएफएसआई उद्योग ग्राहकों की पहचान का सबसे सरल और प्रामाणिक तरीक़ा मानने लगे हैं।

अभी तो यह डिजिटल क्रांति की शुरुआत है और 2022 में तथा आगे चलकर भी बहुत सी नई संभावनाएं हैं। चेहरे की पहचान की पुष्टि और जीवित होने/न होने के प्रमाण जैसे पहलू वीडियो केवाईसी की असल ताक़त या कहें कि रीढ़ हैं और इन सुविधाओं को अब अधिकांश फ़िनटेक/बीएफएसआई उद्योग ग्राहकों की पहचान का सबसे सरल और प्रमाणिक तरीक़ा मानने लगे हैं। यूआईडीएआई भी इसे पहचान फेस की चौथी व्यवस्था के तौर पर लागू करने पर विचार कर रहा है। फिलहाल, यूआईडीएआई ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड), फिंगरप्रिंट अर्थात् उंगलियों के निशान और आइरिस (आंख की पुतली) के माध्यम से ग्राहकों की पहचान की पुष्टि करता है।

माना जा रहा है कि 2022 में अधिकांश फ़िनटेक/बीएफएसआई उद्योग इन डिजिटल पहचान सेवाओं को अपना लेंगे जिससे वे ग्राहकों को कम खर्च पर और तुरंत सेवाएं उपलब्ध करा सकेंगे।

यूआईडीएआई कई अन्य टेक्नोलॉजिकल मोर्चों पर भी काम कर रहा है और देश में नई और तीव्र गति वाली अर्थव्यवस्था विकसित करने की दिशा में औद्योगिक भगीदारों के साथ कदम मिलाकर नए परिवर्तनों के अनुरूप ढलने की चुनौती से निपट सकेगा। ■

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

वित्तीय प्रौद्योगिकी क्रांति

देबजानी घोष

भारत में वित्तीय प्रौद्योगिकी (फ़िनटेक) का पिछले दशक में बेहद तेज़ी से विकास हुआ है। एक समय भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह नक़दी पर निर्भर थी। लेकिन डिजिटल सेवाओं की आसानी और कार्यकुशलता ने उसे बदल दिया है। देश प्रौद्यो-दशक (टेकेड) में तेज़ी से प्रवेश कर रहा है। समावेशी प्रौद्योगिकियां, नवोन्मेष का वातावरण तथा मानव केंद्रित और प्रगतिशील नीतियां विश्व के लिये भारत की वित्तीय प्रौद्योगिकी क्रांति को स्थापित करेंगी।

हम भारत के प्रौद्यो-दशक (टेकेड) में प्रवेश कर रहे हैं जिसमें प्रगति तथा लाभ और उद्देश्य के बीच संतुलन बनाने के लिये प्रौद्योगिकी अपरिहार्य हो जायेगी। मौजूदा समय में भारत खुद को डिजिटल अर्थव्यवस्था में प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष के लिये वैश्विक केंद्र के तौर पर स्थापित कर रहा है। हमारे देश में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की तादाद 83.4 करोड़ और यूपीआई के ज़रिये मासिक लेन-देन की संख्या 461.7 करोड़ तक पहुंच गयी है। इस तरह भारत की वित्तीय प्रौद्योगिकी क्रांति ज्यादातर देशों को पीछे छोड़ती हुई जनसाधारण के स्तर तक पहुंच चुकी है।

भारत में 2003 से अब तक डिजिटल भुगतानों में दस गुना वृद्धि हुई है। इससे 2025 तक 26 लाख नये रोज़गार पैदा होने और आर्थिक मूल्य में 2.8 लाख करोड़ रुपये के इज़ाफ़े की उम्मीद है।[1] हमारी अर्थव्यवस्था पारंपरिक तौर पर नक़दी संचालित रही है। लेकिन उसने मुख्य तौर पर ई-व्यवसाय और स्मार्टफ़ोन की पैठ की लहर से पैदा वित्तीय प्रौद्योगिकी के अवसर को सहजता से अपना लिया है। वित्तीय सेवाओं के इस क्रांतिकारी विकास को एक एकीकृत परिवेश से लगातार सहायता मिल रही है। इस एकीकृत परिवेश में सरकारी एजेंसियों, वित्तीय और अनुसंधान संस्थाओं तथा प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों जैसे सभी भागीदार विचार विमर्श के जरिये बाज़ार की छिपी हुई संभावनाओं को व्यावसायिक और आर्थिक विकास में तब्दील कर रहे हैं।

अच्छी प्रौद्योगिकियां अपरिहार्य होती हैं। भारत की विशाल डिजिटल अवसंरचना ने देश में प्रौद्योगिकी को अपनाये जाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म और ओपन सोर्स आर्किटेक्चर डिजिटल इंडिया की बुनियाद बन गये हैं। इस क्षेत्र में सरकार की नीतियां और नियम समावेशन और नवोन्मेष के सिद्धांत पर आधारित हैं। वित्तीय प्रौद्योगिकी तंत्र का विकास वर्षों के प्रयास का परिणाम है। जन-धन योजना (विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल), ई-रुपी (नक़दी रहित भुगतान के लिये), इंडियास्टैक (मुक्त एपीआई आधारित सार्वजनिक डिजिटल अवसंरचना) और वित्तीय साक्षरता की अनेक पहलकदमियां इस प्रयास में शामिल हैं। जुलाई, 2021 में भीम-यूपीआई के माध्यम से 3.2 अरब से ज्यादा लेन-देन हुए। इससे भारत में डिजिटल भुगतानों की ज़बरदस्त पैठ का पता चलता है।[2] पिछले साल ऑनलाइन टोल

लेखिका सॉफ्टवेयर और सेवा कंपनियों के राष्ट्रीय संघ नैसकॉम की चेयरपर्सन हैं। ईमेल: debjani@nasscom.in

संग्रह के लिये फास्टैग को अनिवार्य बना दिया गया। इसके ज़रिये अब तक 19.2 करोड़ भुगतान हो चुके हैं। इसी तरह उमंग ऐप के माध्यम से 1.7 अरब लेन-देन हो चुके हैं। यह ऐप अनेक सरकारी सेवाओं के लिये एकीकृत प्लेटफॉर्म मुहैया कराता है।

भारत को ऐसे देश के रूप में जाना जाता था जहां एक विशाल आबादी तक बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं की पहुंच नहीं है। लिहाजा, देश में डिजिटल आच्छादन में तेज़ वृद्धि ने विश्व का ध्यान अपनी ओर खींचा है। हमारी डिजिटल लेन-देन की अवसंरचना सुरक्षा के उच्च स्तर तथा तकनीकी गड़बड़ियों और धोखाधड़ी की अपेक्षाकृत कम घटनाओं के लिये खास तौर से जानी जाती है। अनेक देशों ने भारत की डिजिटल अवसंरचना से सीखने में दिलचस्पी दिखायी है। पिन या ओटीपी के ज़रिये अतिरिक्त प्रमाणन को भारतीय नवोन्मेष के तौर पर विश्व भर में मान्यता मिली है। इस नवोन्मेष से धोखाधड़ी की घटनाओं में अपेक्षाकृत कमी आयी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण- इंटरनेशनल फाइनांशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी (आईएफएससीए) के एक कार्यक्रम में कहा था कि भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी तंत्र के विकास का आगामी चरण आय, निवेश, बीमा और संस्थागत ऋण के चार स्तंभों से आयेगा। देश भर में वित्तीय समावेशन का लक्ष्य इन स्तंभों को जोड़ेगा। इससे उद्योग की सफलता और 50 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के भारत के लक्ष्य को हासिल करने का मार्ग प्रशस्त होगा।

कोविड की वैश्विक महामारी से पहले भारत में वित्तीय प्रौद्योगिकी

उद्योग के लक्ष्य और उसके कामकाज के तौर-तरीकों के बारे में जानने का सबसे अच्छा ढंग यह है कि हम उस यात्रा और उन उत्प्रेरकों पर गौर करें जिनकी बदौलत मौजूदा मुकाम तक पहुंचे हैं।

2010 से पहले के समय को हम डिजिटल भुगतान 1.0 कह सकते हैं। नक़द की जगह ई-लेन-देन को अपनाया जाना इस दौर की खासियत था। डिजिटल भुगतान 1.0 में कार्ड और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) भुगतान के सबसे लोकप्रिय तरीके बने। आरटीजीएस को 2003-04 में शुरू किया गया था और उस साल इससे 100 लेन-देन हुए। इस दौरान खुदरा ई-भुगतानों की संख्या 21.5 करोड़ रही। वर्ष 2010 तक सभी डिजिटल भुगतानों में दो गुना से ज्यादा वृद्धि हुई जिसकी मुख्य वजह व्यावसायिक लेन-देन था।[1] यह निस्संदेह स्थिर रफ्तार से विकास का दौर था जिसकी उम्मीद किसी भी क्षेत्र से की जा सकती है। लेकिन डिजिटल भुगतान का इस्तेमाल प्रीमियम खुदरा और व्यवसाय-से-व्यवसाय तक सीमित था। व्यक्तिगत ग्राहकों में जानकारी के अभाव के अलावा मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट की पैठ भी अपने शुरुआती चरणों में थी।

2011 के बाद 3जी और 4जी मोबाइल प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल व्यापक तौर पर होने लगा। इसके परिणामस्वरूप व्यक्तिगत ग्राहकों का ध्यान डिजिटल भुगतानों की ओर गया और मोबाइल बैंकिंग में इजाफा हुआ। डिजिटल भुगतान 2.0 का यह दौर 2016 तक चला। इस दौर के बीच में यानी 2015 तक अकेले डिजिटल वॉलेट के जरिये 3.3 करोड़ लेन-देन हुए। मोबाइल लेन-देन में 2016 तक कुल मिला कर दस गुना वृद्धि दर्ज की गयी। भारतीय उपभोक्ताओं ने इस दौर में बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा में प्रौद्योगिकीय नवोन्मेष के प्रति गहरी दिलचस्पी दिखायी। अतिरिक्त विशेषताओं वाले क्रेडिट और डेबिट कार्डों, नये मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशनों तथा फ्रंट, बैक और मिडिल कार्यालयों के लिये डिजिटल परिवर्तनों ने इस बदलाव में सहायता की।

> **भारत की विशाल डिजिटल अवसंरचना ने देश में प्रौद्योगिकी को अपनाये जाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म और ओपन सोर्स आर्किटेक्चर डिजिटल इंडिया की बुनियाद बन गये हैं। इस क्षेत्र में सरकार की नीतियां और नियम समावेशन और नवोन्मेष के सिद्धांत पर आधारित हैं।**

2016 में नोटबंदी के साथ ही भारत में 86 प्रतिशत नक़दी चलन से बाहर कर दी गयी। इस व्यवधान ने डिजिटल लेन-देन उद्योग के विकास को मज़बूती प्रदान की। इससे डिजिटल भुगतान 3.0 की शुरुआत हुई जिसे 'नेटवर्क प्रभाव' युग भी कहा जा सकता है। प्रौद्योगिकी तंत्र का उन्नयन इस युग की विशेषता रहा जिसने तेज़ विकास के आगामी चरण को बल दिया। इस युग में भारत ने वित्तीय प्रौद्योगिकी समाधानों का निर्यात शुरू किया, शहरों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट का इस्तेमाल ज्यादा होने लगा और व्यक्ति से व्यापारी को डिजिटल

भुगतान की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गयी। इसके साथ ही वित्तीय प्रौद्योगिकी ने मोबाइल वाणिज्य के युग में प्रवेश कर लिया।

कोविड 19 और डिजिटल भुगतान

2020 डिजिटल परिवर्तन और उपभोक्ता व्यवहार के लिहाज से युगांतरकारी साबित हुआ। कोविड 19 से आयी बाधा मानवता के लिये वैश्विक मंदी के बाद के सबसे बड़े संकटों में से एक रही। आवश्यकता से आविष्कार के एक नये दौर की शुरुआत हुई। व्यवसाय में आभासी और स्पर्श रहित तौरतरीकों ने प्रमुख स्थान बना लिया। सभी व्यवसायों को लॉकडाउन से निबटने के लिये डिजिटल एप्लीकेशनों या सेवाओं की शुरुआत करनी पड़ी।

भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी तंत्र के विकास का आगामी चरण आय, निवेश, बीमा और संस्थागत ऋण के चार स्तंभों से आयेगा। देश भर में वित्तीय समावेशन का लक्ष्य इन स्तंभों को जोड़ेगा। इससे उद्योग की सफलता और 50 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के भारत के लक्ष्य को हासिल करने का मार्ग प्रशस्त होगा।

भारत के पास बड़े पैमाने पर डिजिटल भुगतानों के लिये समुचित अवसंरचना पहले से ही मौजूद थी। नवंबर, 2020 में 411 करोड़ लेन-देन डिजिटल माध्यमों से हुए। अर्थव्यवस्था में गिरावट के बावजूद वित्तीय प्रौद्योगिकी भुगतानों में निवेश 2020 की पहली छमाही में दोगुना हो गया। बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा से जुड़ी पारंपरिक संस्थाओं ने भी वित्तीय प्रौद्योगिकी की अपनी पहलकदमियां तेज़ कर दी हैं। वे अपनी डिजिटल सेवाओं की शुरुआत के लिये खुद ही या सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर-सॉफ्टवेयर ऐज ए सर्विस (एसएएएस) प्रदाताओं के साथ भागीदारी में उदीयमान प्रौद्योगिकियों में निवेश कर रही हैं। दिसंबर, 2021 तक भारत के 17 से ज्यादा वित्तीय प्रौद्योगिकी स्टार्टअप यूनीकॉर्न का दर्ज़ा हासिल कर चुके थे। इस क्षेत्र में कुल वित्त पोषण लगभग 27.6 अरब अमेरिकी डॉलर का रहा। भारत में 2020 में 25.5 अरब रियल टाइम भुगतान दर्ज़ किये गये। अमेरिका, ब्रिटेन और चीन को एक साथ मिला दें तो भी रियल टाइम ऑनलाइन लेन-देन के मामले में भारत उनसे आगे है।

विकास के अगले चरण, डिजिटल भुगतान 4.0 में किफायती समाधानों के साथ जनसाधारण तक पहुंच पर ध्यान केंद्रित किया जायेगा। भारत में डिजिटल भुगतान 2025 तक 54800 करोड़ तक पहुंच जाने की संभावना है। इसमें 2020 से पांच वर्षों में 16 गुना इज़ाफ़ा होगा। डिजिटल वाणिज्य, व्यक्तिगत समाधानों, डिजिटल सम्मिलन तथा नियामक नवोन्मेष के विकास से इसमें मदद मिलेगी।

नेटवर्क प्रभाव

तीसरे चरण में हमें नेटवर्क प्रभाव देखने को मिला। यह डिजिटल भुगतान और वित्तीय प्रौद्योगिकी की ओर सही समय पर ध्यान और निवेश आकर्षित करने में काफी मददगार साबित हुआ है। चौथे चरण या कोविड के बाद के युग में डिजिटल भुगतानों की संख्या और पहुंच में ज़बरदस्त इज़ाफा होगा। पीडब्ल्यूसी और पीसीआई की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में वैश्विक डिजिटल भुगतान क्षेत्र 120 खरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का होगा जिसमें भारत की हिस्सेदारी 2.2 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। इस विकास से भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा और इसके 2025 तक 10 खरब अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंच जाने की संभावना है। इसके अलावा 2025 तक उपयोगकर्ताओं के सभी वर्गों में वित्तीय समावेशन लगभग 95 प्रतिशत तक पहुंच जायेगा। ई-वाणिज्य में पांच गुना वृद्धि होगी और एमएसएमई डिजिटलीकरण से सकल घरेलू उत्पाद में 25 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का इजाफा होगा।

डिजिटल भुगतान 4.0 की संभावनाएं

इन सब के बीच सतत विकास सुनिश्चित करने के लिये कुछेक क्षेत्रों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। डाटा सुरक्षा और धोखाधड़ी प्रबंधन के क्षेत्र में नीतिगत समर्थन अनिवार्य है। ब्लॉकचेन, जियो-फेंसिंग और जियो-टैगिंग जैसी नयी प्रौद्योगिकियों का उपयोग तथा क्यूआर-कोड-आधारित घोटालों को रोकने के लिये एक फ्रेमवर्क को लागू करना सुरक्षित और स्थिर डिजिटल वित्तीय तंत्र सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। धोखाधड़ी और साइबर अपराधों को रोकने के लिये ग्राहक जागरूकता का विकास महत्वपूर्ण है। जनसाधारण में डिजिटल भुगतानों की लोकप्रियता के साथ ही व्यवसायियों और ग्राहकों के लिये केवाईसी नीति को सरल बनाना भी ज़रूरी है। इसके अलावा हमें भुगतान अवसंरचना बनाना तथा तीसरे दर्जे और उससे नीचे के शहरों में ऑफलाइन भुगतानों का समावेशन भी जारी रखना होगा।

नवोन्मेष खुद को अलग-थलग रख कर नहीं हो सकता। इसलिये राष्ट्रीय भुगतान अवसंरचनाओं को जोड़ने के लिये अन्य देशों के साथ सहयोग भी ज़रूरी है।[3] भारत और सिंगापुर ने इस दिशा में क़दम उठाया है। उनकी भुगतान प्रणालियों, यूपीआई और पे-नाऊ को जुलाई, 2022 तक जोड़ दिया जायेगा। इससे उपयोगकर्ता भारत और सिंगापुर के बीच तुरंत और किफायती ढंग से धन का सीधे हस्तांतरण कर सकेंगे। कुछ बुनियादी क़ानूनों और विनियमों के बीच सामंजस्य स्थापित करना भी सही मायनों में वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था के निर्माण में सहायक होगा।

नवोन्मेष खुद को अलग-थलग रख कर नहीं हो सकता। इसलिये राष्ट्रीय भुगतान अवसंरचनाओं को जोड़ने के लिये अन्य देशों के साथ सहयोग भी ज़रूरी है। भारत और सिंगापुर ने इस दिशा में क़दम उठाया है। उनकी भुगतान प्रणालियों, यूपीआई और पे-नाऊ को जुलाई, 2022 तक जोड़ दिया जायेगा।

सरकारी पहलकदमियां तथा भारत के मज़बूत स्टार्टअप और नवोन्मेष तंत्र ने देश की वित्तीय प्रौद्योगिकी के विकास के लिये मज़बूत बुनियाद तैयार की है। सिर्फ दो दशकों में भारत के वित्तीय प्रौद्योगिकी तंत्र का विकास असाधारण रहा है। भविष्य के लिये इसका परिदृश्य भी संभावनाओं से भरा है। हमारे अब तक के सफ़र में एकीकृत तंत्र की सतत कोशिशों ने सफलता का मार्ग प्रशस्त किया है।

पिछले साढ़े सात दशकों में भारत ने एक मज़बूत डिजिटल अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में ज़बरदस्त छलांग लगायी है। इस प्रौद्यो-दशक में भारत को डिजिटल क्षेत्र में अपनी अनुकूल स्थिति का इस्तेमाल शासन के ज्यादा-से-ज्यादा डाटा संचालित ढांचे की ओर बढ़ने के लिये करना चाहिये। इसके परिणामस्वरूप ज्यादा समावेशी, संवहनीय और प्रभाव आधारित नवोन्मेष को बल मिलेगा। हमारे देश का भविष्य इस बात से परिभाषित होगा कि हम डिजिटल समाधानों को किस तरह एकीकृत कर पाते हैं। बड़े पैमाने पर डिजिटल प्रतिभा के निर्माण तथा लाभ और उद्देश्य के बीच संतुलन से हम सही मायनों में इस प्रौद्यो-दशक में प्रवेश कर सकेंगे। ■

संदर्भ

1. https://nasscom.in/knowledge-center/publications/india-digital-payments-40-2025-outlook
2. https://nasscom.in/knowledge-center/publications/digital-india-digital-public-goods-platformisation-play
3. https://www.mas.gov.sg/news/media-releases/2021/singapores-paynow-and-indias-upi-to-link-in-2022

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

कृपया ध्यान दें

पत्रिकाओं की सदस्यता के संबंध में सूचना

कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थितियों के कारण साधारण डाक से भेजी गई हमारी पत्रिकाओं की डिलिवरी न हो पाने से संबंधित शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। हमारे माननीय उपभोक्ताओं को योजना, कुरुक्षेत्र, बाल भारती और आजकल पत्रिका की समय पर डिलिवरी सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि नए उपभोक्ताओं को साधारण डाक से पत्रिकाओं का प्रेषण तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए। यह केवल नए उपभोक्ताओं के लिए लागू होगा तथा मौजूदा उपभोक्ताओं को उनकी सदस्यता दरों के अनुसार पत्रिकाएं भेजी जाती रहेंगी।

हमारी पत्रिकाओं के लिए नई सदस्यता दरें जिनमें रजिस्टर्ड डाक से पत्रिका भेजने का शुल्क भी शामिल है, निम्नलिखित हैं-

सदस्यता प्लान	योजना, कुरुक्षेत्र तथा आजकल (सभी भाषाएं)	बाल भारती
1 वर्ष	रु. 434	रु. 364
2 वर्ष	रु. 838	रु. 708
3 वर्ष	रु. 1222	रु. 1032

वर्तमान परिस्थितियों में यह एक अस्थायी व्यवस्था है क्योंकि डाक विभाग साधारण डाक के वितरण में कठिनाइयों का सामना कर रहा है। अतः जैसे ही देश में सामान्य स्थितियां बहाल हो जाएंगी पत्रिकाओं को पुनः साधारण डाक से भेजना आरंभ कर दिया जाएगा।

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

वित्तीय क्षेत्र में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस

बालेन्दु शर्मा दाधीच

आज से दो साल पहले ही भारत ऑनलाइन लेनदेन के मामले में दुनिया में पहले नंबर पर आ गया था। चीन, दक्षिण कोरिया, इंग्लैंड, जापान और अमेरिका हमसे पीछे थे। यह तो तब था जब उस साल भारत में डिजिटल लेनदेन साढ़े 25 अरब डॉलर पर था। आज तब से एक दर्जन गुना ज्यादा तरक़्क़ी हो चुकी है और सिलसिला लगातार जारी है।

भारत में वित्तीय प्रौद्योगिकी (फ़िनटेक) की लोकप्रियता असंदिग्ध है जहां पिछले वित्त वर्ष में डिजिटल प्रणालियों के ज़रिए 22.5 लाख करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ था। सन् 2026 में इसके बढ़कर 75 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाने की उम्मीद है। सरकार की कोशिशों और कोविड की त्रासदी के मद्देनज़र डिजिटल भुगतान और वित्तीय प्रौद्योगिकी ने भारत में जिस किस्म की अपार लोकप्रियता हासिल की है उसने दुनिया के बड़े से बड़े अर्थशास्त्रियों और तकनीकविदों को चौंकाया है। एसीआई वर्ल्डवाइड नाम की कंपनी की रिपोर्ट कहती है कि आज से दो साल पहले ही भारत ऑनलाइन लेनदेन के मामले में दुनिया में पहले नंबर पर आ गया था। चीन, दक्षिण कोरिया, इंग्लैंड, जापान और अमेरिका हमसे पीछे थे। यह तो तब था जब उस साल भारत में डिजिटल लेनदेन साढ़े 25 अरब डॉलर पर था। आज तब से एक दर्जन गुना ज्यादा तरक़्क़ी हो चुकी है और सिलसिला लगातार जारी है।

वित्तीय प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की कामयाबी के कुछ और भी पहलू हैं, जैसे बैंकों द्वारा तेज़ी से डिजिटल प्रौद्योगिकी को अपनाया जाना और डिजिटल भुगतान प्रणाली के एक व्यापक सिस्टम का स्थापित हो जाना। यह सिस्टम एकीकृत भुगतान प्रणाली (यूपीआई) से लेकर दर्जनों डिजिटल भुगतान एप्लीकेशनों और रूपे जैसे कार्डों से लेकर माइक्रोबैंकिंग तक को अपने में समेटे हुए हैं। ये प्रणालियां तेज़ी से परिपक्व हो गई हैं और आज हम इस स्थिति में आ गये हैं कि चैट के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एप्लीकेशन तक में एपीआई का प्रयोग करते हुए पैसे के लेनदेन की सुविधा उपलब्ध है, जिसे वित्तीय क्षेत्र में अगली बड़ी क्रांति माना जा रहा है। देश में ऐसा तकनीकी सिस्टम बन चुका है जिसे दूसरे तकनीकी सिस्टमों में समाहित किया जा सकता है या उनके साथ जोड़ा जा सकता है। इन सबके अलावा एक अन्य क्षेत्र ब्लॉकचेन तकनीकों का खुल रहा है जिसके भीतर अलग तरह की संभावनाएं निहित हैं।

इतनी तरक्की होने पर दो सवाल स्वाभाविक रूप से खड़े होते हैं। पहला यह कि आगे क्या? और दूसरा यह कि इसके भीतर चुनौतियां कैसी उभर रही हैं। पहले सवाल का मतलब यह कि भारत में जब सन् 2019 से 2021 के बीच वित्तीय लेनदेन में दस गुना बढ़ोतरी हो गई तो क्या यह सिलसिला यूं ही आगे भी चलता रहेगा? और अगर हां, तो कब तक? इसका जवाब यह है कि भारत में इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की काफी गुंजाइश बाकी है और यह दौर अगले पांच साल तक काफी तेज़ रफ्तार से बढ़ता रह सकता है। दूसरे सवाल का जवाब यह है कि डिजिटल तकनीकों के आने से जहां धन, संसाधनों, श्रम, प्रक्रियाओं आदि के मामले में अद्‌भुत बचत हुई है और समय के मामले में बेहद तेज़ी आई है वहीं सुरक्षा तथा निजता संबंधी चुनौतियां भी आ खड़ी हुई हैं। जालसाजी, धोखाधड़ी, पहचान की चोरी और ऐसे ही दर्जनों दूसरे संकट आ खड़े हुए हैं जिनका नुकसान आम आदमी के साथ-साथ हमारे वित्तीय तंत्र को भी भुगतना पड़ रहा है। हालांकि लाभ की तुलना में नुकसान का स्तर आंशिक ही है लेकिन वित्तीय क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है, जिसमें असुरक्षा की ज़रा भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए।

सवाल उठता है कि इन प्रणालियों को अभेद्य बनाए रखने

लेखक जाने-माने तकनीक विशेषज्ञ हैं। ईमेल: balendudadhich@gmail.com

के लिए क्या करना होगा? आज की बहुत सारी चुनौतियां ऐसी हैं जिन्हें पहले नहीं देखा गया। किसी एक देश में मौजूद अपराधी दूसरे देश में अपराध को अंजाम देकर इंटरनेटीय ब्रह्मांड में न जाने कहां गायब हो जाए, कहा नहीं जा सकता। एक छोटा सा एसएमएस किसी शख्स के बैंक खाते को खाली करने का जरिया बन जाए, यह भी हम देखते आए हैं। इनके समाधान में इंसान की भूमिका तो है लेकिन सिर्फ इंसान की क्षमताओं के आधार पर परिणाम नहीं आ सकते। प्रौद्योगिकी से उभरने वाली चुनौतियों का समाधान भी उसी की तरह तेज़ रफ्तार होना चाहिए और यह समाधान भी प्रौद्योगिकी की मदद से ही हासिल हो सकता है। वित्तीय तंत्र में जगह-जगह पर डिजिटल सुरक्षा की प्रणालियां तो आज भी मौजूद हैं और उपभोक्ता भी पहले से ज्यादा सजग हो चुका है लेकिन नए ज़माने की चुनौतियां मौजूदा सुरक्षा तंत्र की क्षमताओं को लगातार चुनौती दे रही हैं। शायद हमें आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, क्वान्टम कंप्यूटिंग और ब्लॉकचेन की शरण में जाने की आवश्यकता है।

लेकिन ऐसा भी नहीं कि इन नई तकनीकों के प्रयोग की गुंजाइश सिर्फ डेटा की सुरक्षा को दुरुस्त बनाए रखने और कार्यक्षमता बढ़ाने तक सीमित हो। बैंकों के पारंपरिक कामकाज को बेहतर ढंग से संचालित करने में भी इनकी भूमिका हो सकती है। आज आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस और डेटा विश्लेषिकी (एनालिटिक्स) की बदौलत सूचनाओं का बहुत सटीक विश्लेषण करते हुए यह भविष्यवाणी करना भी संभव है कि डूबते खाते को कैसे नियंत्रित किया जाए, कर्ज़ों के लिए सही पात्रों का चयन कैसे किया जाए और पुनर्निवेश के लिए बेहतर संभावनाएं कहां मिलेंगी। इन सबके अतिरिक्त ग्राहकों को बेहतर सेवाएं देने और उनके साथ निजी स्तर पर संपर्क बनाए रखने जैसी प्रक्रियाएं भी प्रौद्योगिकी की बदौलत आसान और संभव हो गई हैं। पहले इनके लिए हम मानवीय श्रम पर निर्भर थे और इसीलिए अधिक मानव संसाधनों की तैनाती के बावजूद नतीजे उतने अच्छे नहीं आ पाते थे जितने कि आज कम मानव संसाधनों से ही संभव हो गए हैं।

केवाईसी (नो योर कस्टमर) से जुड़ी प्रक्रियाएं पहले से ज्यादा आसान होने के बाद भी ज्यादा असरदार हो चली हैं। मोबाइल और आधार के प्रयोग से मौके पर ही सही खाताधारक की पहचान को प्रमाणित करना संभव हो गया है।

वित्तीय क्षेत्र में प्रौद्योगिकी की भूमिका लगातार गहन होती जा रही है। आज जन धन योजना के ज़रिए करोड़ों नए लोग बैंकिंग प्रणाली का हिस्सा बने हैं। इनके अलावा भी औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्र में वित्तीय सेवाएं बहुत बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच रही हैं। आधार कार्ड और मोबाइल कनेक्शनों के आने के बाद बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र की अनेक प्रक्रियाएं आसान हो गई हैं जिसका परिणाम वित्तीय क्षेत्र में उपभोक्ताओं की बढ़ती संख्या के रूप में दिखाई दे रहा है। पहले जहां डीमैट, बैंक ऋण और निवेश आदि के खाते खुलवाने में कुछ दिन या कुछ हफ्ते लगा करते थे वह अब कुछ घंटों में भी होने लगा है। हालांकि यह बैंक विशेष की तत्परता पर निर्भर करता है लेकिन इन प्रक्रियाओं में चार-पांच गुना तेज़ी तो आई ही है। केवाईसी (नो युअर कस्टमर) से जुड़ी प्रक्रियाएं पहले से ज्यादा आसान होने के बाद भी ज्यादा असरदार हो चली हैं। मोबाइल और आधार के प्रयोग से मौके पर ही सही खाताधारक की पहचान को प्रमाणित करना संभव हो गया है। भारत में इंटरनेट और मोबाइल तकनीकों का व्यापक प्रसार हुआ है जिसने इन सबके लिए सही माहौल तथा पृष्ठभूमि का निर्माण करने में मदद की है। सरकार ने भी दूरदृष्टि दिखाई है और उद्योगों ने भी कई तरह की नई पहलें की हैं। आज जिस वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) का हम सामान्य ढंग से इस्तेमाल करने लगे हैं, उसे अनेक विशेषज्ञ दुनिया को भारतीय वित्तीय क्षेत्र की देन मानकर चलते हैं, जो व्यक्ति की पहचान के वैलिडेशन (प्रमाणन) का सस्ता, सुंदर, प्रभावी और टिकाऊ तरीका बन चुका है।

तमाम बदलावों का असर वित्तीय डिजिटलाइजेशन में भी दिखाई दे रहा है। साठ फीसदी से ज्यादा लेनदेन एकीकृत भुगतान प्रणाली (यूपीआई) के दायरे में आ गए हैं और ढाई सौ से ज्यादा बैंक यूपीआई के सदस्य हैं। धन के लेनदेन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मोबाइल एप्लीकेशनों की बाढ़ आ गई है। पेटीएम, फ़ोन पे, मोबीक्विक, गूगल पे, भारत पे, पाइन लैब्स, रेजर पे और क्रेड जैसे दर्जनों एप्लीकेशन हमारे सामने हैं। देखते ही देखते इनमें से कुछ का दायरा अनेक बैंकों से भी ज्यादा बड़ा हो गया है। अब तो भारतीय रिजर्व बैंक ने सामान्य मोबाइल फ़ोन पर बिना इंटरनेट के भी धन के लेनदेन की व्यवस्था शुरू कर दी है जो सारे घटनाक्रम की व्यापकता और समग्रता की तरफ संकेत करता है। एक अध्ययन के मुताबिक सन 2026 तक स्थितियां और भी बदल जाएंगी जब भारत में होने वाले कुल वित्तीय लेन-देन का 44 प्रतिशत हिस्सा पेमेन्ट गेटवे और एग्रीगेटरों के ज़रिए आएगा जबकि 34 फीसदी भुगतान क्यूआर कोड के ज़रिए किए जाएंगे। इतना ही नहीं, 22 प्रतिशत भुगतान पीओएस (पेमेन्ट ऑफ सेल्स) मशीनों (हाथ में रखी जाने वाली) के ज़रिए हो रहे होंगे।

इन दिनों वित्तीय प्रौद्योगिकी में एक नया क्षेत्र भी लोकप्रिय हो रहा है जिसे 'अभी खरीदो बाद में भुगतान करो' (बाइ नाउ, पे लेटर) (बीएनपीएल) का नाम दिया गया है। ये छोटी धनराशि के कर्ज़ हैं जिन के लिए नगण्य या बहुत कम ब्याज लिया जाता है। शायद आपने बजाज फाइनेंस या ऐसी ही दूसरी कंपनियों के उन ऑफर्स को देखा होगा जब आप कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेने के लिए जाते हैं तो आपको बिना ब्याज के उन उपकरणों के लिए फ़ाइनेंस की पेशकश की जाती है। छोटे-छोटे भुगतान (जैसे सिनेमा के टिकट या भोजन के बिल) आदि के लिए भी इस तरह के छोटे कर्ज़ दिए जाने लगे हैं जिन्हें कुछ दिन, हफ्तों या महीनों में चुकाया जाता है। सिम्पल, जेस्टमनी, लेजीपे, कैपिटल फ्लोट और मोबिक्विक जिप जैसी छोटी कंपनियां इस कारोबार में लगी हैं। धनी ऐप के तहत आधार कार्ड और मोबाइल नंबर के आधार पर छोटे कर्ज़ दे दिए जाते हैं। रेडसियर नामक संस्था का अनुमान है कि भारत में बीएनपीएल श्रेणी में एक से डेढ़ करोड़ लोग पहले ही छोटे-छोटे कर्ज़ों का फायदा उठा चुके हैं। अनुमान है कि अगले

पांच साल में ऑनलाइन बिक्री का दस फीसदी हिस्सा इस तरह के लेनदेन पर आधारित होगा।

इन बदलावों की रोशनी में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, साइबर सुरक्षा और क्वान्टम कंप्यूटिंग जैसी तकनीकों को ड्राइविंग सीट संभालने की ज़रूरत है ताकि आधुनिक दौर के अवसरों और चुनौतियों दोनों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। ग्राहकों के बर्ताव तथा गतिविधियों पर नज़र रखने तथा उनका विश्लेषण करने वाली तकनीकों में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की अहम भूमिका है। आपने संभवत: बिग डेटा नामक अवधारणा के बारे में सुना होगा जिसका अर्थ यह है कि आज डिजिटल माध्यमों पर लोगों की गतिविधियों के आधार पर अपरिमित आकार में सूचनाएं पैदा हो रही हैं। उनका सही ढंग से विश्लेषण किया जाए तो आर्थिक, राजनैतिक, सुरक्षात्मक तथा ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में बेहतरीन परिणाम पाने के लिए उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। यह बात वित्तीय क्षेत्र पर भी लागू होती है जहां ऐसे डेटा का विश्लेषण करके बैंक न सिर्फ अपने कारोबार को बढ़ा सकते हैं बल्कि वे अच्छे और सुरक्षित ग्राहकों तक पहुंच सकते हैं। डेटा विश्लेषण के क्षेत्र में प्रीडिक्टिव एनालिसिस का अक्सर जिक्र होता है जिसके तहत यह भविष्यवाणी की जा सकती है कि किन लोगों को कर्ज़ की ज़रूरत हो सकती है, कौन से लोग दूसरे स्थान से लिए गए कर्ज़ को ट्रांसफर करवाना चाहते होंगे और कौन से लोग आने वाले वर्षों में इस तरह की ज़रूरत से गुज़रेंगे। इसी तरह यह भी कि किन लोगों की परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं और उन्हें कर्ज़ देना घाटे का सौदा सिद्ध हो सकता है।

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. Delhi

इन दिनों वित्तीय प्रौद्योगिकी में एक नया क्षेत्र भी लोकप्रिय हो रहा है जिसे 'अभी खरीदो बाद में भुगतान करो' (बाइ नाउ, पे लेटर) (बीएनपीएल) का नाम दिया गया है।

धोखाधड़ी की रोकथाम में भी इन तकनीकों का उत्कृष्ट इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि एक तो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस में एक ही तरह के पैटर्न (ढर्रे) को पहचानने की क्षमता है और दूसरे वह उनके समाधान के लिए कौन से तरीके कारगर सिद्ध हो सकते हैं उनकी ओर भी संकेत कर सकती है। अगर धोखाधड़ी से जुड़े किसी पैटर्न को आगे कभी किसी अपराधी द्वारा दोहराया जाता है तो यह प्रौद्योगिकी सुरक्षा तंत्र को सचेत कर सकती है और भुगतान प्रणालियों को रोक सकती है। याद रहे, सन 2020 में ऑनलाइन धोखाधड़ियों के ज़रिए विभिन्न कंपनियों को क़रीब 56 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचाया गया है। यह रक़म भारतीय मुद्रा में 42 लाख करोड़ रुपये के क़रीब बैठती है। आजकल रैंसमवेयर जैसे खतरे आ खड़ा हुए हैं जो वित्तीय क्षेत्र को पंगु बनाने की क्षमता रखते हैं। बैंकों, वित्तीय संस्थानों और कंपनियों के साथ-साथ सरकारें भी इस चुनौती से पूरी तरह सुरक्षित नहीं हैं। ऐसे में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस और डेटा विश्लेषिकी हमारी सुरक्षा समाधान प्रणालियों की रीढ़ बनकर सामने आ सकते हैं। आने वाले दिनों में इन कामों में क्वान्टम कंप्यूटरों की अहम भूमिका हो सकती है।

धनशोधन जैसे अपराधों को अंजाम देने वाले अपराधी बहुत शातिर माने जाते हैं और तकनीकी दृष्टि से भी बेहद सक्षम हैं। उनकी गतिविधियों को पहचानने में पारंपरिक तौरतरीके और मौजूदा तकनीकें कमज़ोर साबित हो रही हैं। नतीजा? कृत्रिम बुद्धिमत्ता। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस ऐसे लोगों की संदेहास्पद गतिविधियों को 'सूंघ' सकती है। यही बात पहचान की चोरी, क्रेडिट कार्डों के दुरुपयोग आदि पर लागू होती है। मिसाल के तौर पर किसी के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल एक ही समय पर अनेक स्थानों पर किया गया हो या फिर ऐसी जगह से जहां संबंधित व्यक्ति के मौजूद होने की संभावना न के बराबर हो तो सिर्फ तकनीक ही है जो तुरंत ऐसे अपराधों की ओर इशारा कर सकती है।

ग्राहकों को सेवाएं उपलब्ध कराने में आजकल आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस से लैस चैट बॉट की भूमिका बढ़ रही है। ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो पहले से मौजूद डेटा तथा ग्राहक द्वारा पूछे जाने वाले सवालों का ठीक उसी समय पर विश्लेषण करके उनके जवाब देने में सक्षम हैं। आपने संभवत: कुछ वेबसाइटों पर एक बॉक्स देखा होगा जिसमें लिखा होता है- मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? अनेक बैंकों की वेबसाइटों पर भी ऐसे बॉक्स दिखाई देंगे। यही चैट बॉट हैं जिन्हें आप बिना शक्ल के रोबोट के रूप में समझ सकते हैं। जब आप उनसे बात करना शुरू करते हैं तो वे दनादन उत्तर देने लगते हैं और आपकी निजी सूचनाओं को भी एक्सेस करने में सक्षम है। जब आपके सवाल उनकी मशीनी क्षमताओं से आगे निकल जाते हैं तब वे आपको किसी इंसान के पास ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन इससे पहले की सारी प्रक्रिया मशीनी अंदाज में संपन्न हो जाती है और वह भी इतनी कुशलता से कि आपको पता ही नहीं चल पाता कि आपकी बात किसी इंसान से नहीं हो रही है। ये चैट बॉट एक ही समय पर हजारों-लाखों उपभोक्ताओं के साथ चर्चा करने में सक्षम हैं और उनकी जिज्ञासाओं, सवालों तथा सामान्य दुविधाओं का समाधान कर सकते हैं। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस पर आधारित इन क्षमताओं का लाभ बैंकों को भी होता है तो ग्राहकों को भी। साथ ही साथ कार्यकुशलता बढ़ती है और बैंक ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों तक पहुंच पाते हैं।

कुल मिलाकर, आने वाले वर्षों में जिन पांच प्रमुख क्षेत्रों में हमें प्रौद्योगिकी की बदौलत लगातार बदलाव और इनोवेशन देखने को मिलेगा, उनमें से पहला क्षेत्र है- वित्तीय क्षेत्र के कामकाज को और भी अधिक तेज़-रफ्तार, सुरक्षित और सुसंगठित बनाना। दूसरा क्षेत्र है- नई संभावनाओं की तलाश, पहचान और उन्हें अवसरों में बदलना। तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र ग्राहकों के साथ संपर्क का है जहां बची-खुची दीवारें और सीमाएं भी आने वाले दिनों में खत्म हो जाएंगी। चौथा बड़ा क्षेत्र है- वित्तीय प्रक्रियाओं को लोगों की पृष्ठभूमि और बर्ताव के साथ जोड़कर देखने की क्षमता जो इस क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन ला सकती है। अंतिम और पांचवां क्षेत्र साइबर सुरक्षा का है, जो यह सुनिश्चित करेगा कि वित्तीय क्षेत्र का दायरा, लेनदेन का परिमाण और विविधताओं के अपरिमित स्तर पर बढ़ जाने के बावजूद हमारा वित्तीय ढांचा महफूज बना रहे। ■

ग्रामीण भारत में बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

ओसामा मंज़र
मेघा कठेरिया
डॉ सैयद एस काज़ी

जैम (जन धन-आधार-मोबाइल) त्रयी और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं ने ग्रामीण भारत के वित्तीय समावेशन में क्रांति ला दी। डिजिटल प्रोत्साहन ने ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय एवं बैंकिंग सेवाओं की सुलभता को नई तेज़ी दी। 2016 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली को सुचारु बनाने के लिए यूपीआई शुरू किया। एनपीसीआई के आंकड़ों के अनुसार 2021 में यूपीआई से 6.39 लाख करोड़ रुपये के लेनदेन हुए।[1] किंतु ग्रामीण भारत में इंटरनेट की केवल 28 प्रतिशत पैठ होने के कारण ये लेनदेन मोटे तौर पर शहरी भारत की कहानी ही बताते हैं।[1] फिर भी डिजिटल भुगतान और बैंकिंग में ग्रामीण भारत की बढ़ती हिस्सेदारी को अनदेखा नहीं किया जा सकता।

इंटरनेट और मोबाइल की बढ़ती पैठ के कारण ग्रामीण भारत में वित्तीय मकसद से डिजिटल उपयोग लगातार बदल रहा है। यह भारतनेट की चरणबद्ध सफलता से जुड़ा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी कार्यक्रम है और भारत की वित्त मंत्री के अनुसार जिसके तहत जून 2021 में 13,000 टेराबाइट डेटा का इस्तेमाल किया गया।[2] ग्रामीण भारत अब शहरी भारत के उलट अलग-थलग नहीं रह गया है और तेज़ी से इंटरनेट की रफ़्तार पकड़ रहा है। डिजिटल वित्तीय सेवाओं में वृद्धि ग्रामीण डिजिटल नागरिक के ऐतिहासिक उभार का प्रमाण है।

ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था मोटे तौर पर नक़द से चलती है। ग्रामीण भारत में रोज़गार तथा आय में विविधता बढ़ रही है, जिससे मुख्य रूप से खेती पर आधारित होने की इसकी छवि बदल रही है। कृषि आय में अब दो-तिहाई योगदान गैर कृषि क्षेत्र का है।[3] पिछले कुछ वर्षों में बैंकिंग करेस्पॉन्डेंटों ने ग्रामीण क्षेत्रों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने में केंद्रीय भूमिका निभाई है। वे बैंक के एजेंट होते हैं, जो बैंकिंग सेवाओं को वहां तक ले जाते हैं, जहां ईंट-गारे से बनी बैंक शाखाएं नहीं पहुंच पातीं। बैंकों ने आधार तथा फोन नंबर जोड़ने की मुहिम को भी गति दी है। डिजिटल साधनों का इस्तेमाल कर बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट ग्रामीण नागरिकों को डिजिटल वित्तीय तंत्र का प्रयोग करने लायक बनाते हैं और उसके बारे में बताते हैं।

इसे भांपकर 2017 से ही डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन (डीईएफ) ज़मीनी स्तर पर डिजिटल वित्तीय साक्षरता एवं भागीदारी बढ़ाने के लिए बैंकिंग करेस्पॉन्डेंटों के साथ काम कर रहा है। हमने ग्रामीण भारत में डिजिटल वित्तीय साक्षरता का अनुभव समझने के लिए ऐसे 20 करेस्पॉन्डेंटों से बात की। हमने ग्रामीण भारत में उपलब्धता और आपूर्ति के नज़रिये से बात की क्योंकि डिजिटल वित्तीय विकास के ये ही दो प्रमुख स्तंभ हैं। डीईएफ ने

ओसामा मंज़र डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन के संस्थापक एवं निदेशक हैं और नेशनल ई-गवर्नेंस डिविजन में डिजिटल सेवा सलाहकार समिति के सदस्य हैं।
ईमेल: osama@defindia.net
मेघा और डॉ काज़ी काउंसिल फॉर सोशल एंड डिजिटल डेवलपमेंट (सीएसडीडी) से संबद्ध हैं।

पूरे भारत में 2000 से अधिक डिजिटल संसाधन केंद्र बनाए हैं, जिन्हें सूचनाप्रेन्यूर चलाते हैं और अपने समुदाय के लिए 'बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट' का काम भी करते हैं।

लाभः समय, दूरी और धन की बचत

राजस्थान में काम करने वाली एक महिला बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट ने कहा, ''डिजिटल सेवाओं के फ़ायदे के बगैर हमारी ज़िंदगी अधूरी ही रहतीं।'' हमारे सभी बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट या सूचनाप्रेन्यूर इस बात पर एकमत थे कि आम ग्रामीण नागरिकों के लिए डिजिटल बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के बहुत फ़ायदे हैं। डिजिटल बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता ने ग्रामीण नागरिकों के बीच डिजिटल वित्तीय और बैंकिंग सेवाओं के व्यापक उपयोग को बढ़ावा दिया है। महामारी और लॉकडाउन के दौरान तो इसमें और भी इज़ाफ़ा हुआ क्योंकि उस समय दूर जाना लगभग असंभव था।

डिजिटल भुगतान और बैंकिंग सेवाओं से सुविधा और लेनदेन में सुगमता की बात सभी बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट ने कही। यह अहम बात है क्योंकि किसी ज़िले में कई गांवों के लिए बैंक की एक ही शाखा होती है और ज़्यादातर गांवों से दूर होती है। जिस अर्थव्यवस्था में एक-एक पाई मायने रखती हो, वहां बैंक से रक़म लेने के लिए भी रक़म ख़र्च करनी पड़ती है। राजस्थान में एक बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट ने कहा, ''एक तरफ का बस टिकट 20 रुपये का होता है या 50-60 रुपये का पेट्रोल खर्च होता है। उसके बाद हमें 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है।'' इसी तरह रिश्तेदारों से उधार लिया जा सकता है, जिसमें आने-जाने का खर्च नहीं लगता।

एटीएम तक दूर-दूर हैं। विश्व बैंक के अनुसार भारत के ग्रामीण इलाक़ों में देश के केवल 20 प्रतिशत एटीएम हैं।[4] उसका अनुमान था कि प्रति 10 गांवों पर एक एटीएम है। लगभग सभी बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट बताते हैं कि वे एटीएम से रक़म निकालते हैं मगर कुछ कभीकभार ही ऐसा होने की बात भी करते हैं। वे ज़्यादातर ऑनलाइन लेनदेन पर भरोसा करते हैं। राजस्थान में एक बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट कभी एटीएम से रक़म नहीं निकालता क्योंकि यह उसके गांव से 20 किलोमीटर दूर है। एईपीएस यानी आधार से चलने वाली भुगतान प्रणाली ने उस जैसे लोगों के लिए अपने सभी वित्तीय लेनदेन संभालना आसान बना दिया है।

पिछले कुछ वर्षों में बैंकिंग करेस्पॉन्डेंटों ने ग्रामीण क्षेत्रों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने में केंद्रीय भूमिका निभाई है। वे बैंक के एजेंट होते हैं, जो बैंकिंग सेवाओं को वहां तक ले जाते हैं, जहां ईंट-गारे से बनी बैंक शाखाएं नहीं पहुंच पातीं।

नक़द नहीं तो चोरी नहीं

ग्रामीण भारत में चोरी का बहुत डर होता है। पैसे घर में रखे हों या बाज़ार जाते समय अपने पास हों, चोरी का डर हर जगह होता है। हरियाणा में एक बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट ने कहा, ''बैंक से मोटा नक़द निकालकर घर लौटते समय रास्ते में चोरी होने का डर सबसे ज्यादा होता है।''

मध्य प्रदेश में एक बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट ने बताया कि वह तो अपना डेबिट कार्ड भी लेकर नहीं चलता। उसने कहा, ''अगर किसी दोस्त ने मेरा पिन देख लिया और मेरे कार्ड का ग़लत इस्तेमाल कर लिया तो? अगर कार्ड खो गया या चोरी हो गया तो?'' उसके लिए एटीएम और डेबिट कार्ड जैसे डिजिटल उपकरण के भौतिक स्वरूप की सुरक्षा भी बोझ है। एसबीआई ऐप की बाहरी सुरक्षा और सुविधा उसे निश्चिंत करती है क्योंकि उसके ज़रिये वह बहुत ज़रूरत पड़ने पर एसबीआई के एटीएम से रक़म भी निकाल सकता है। ऐप में ख़ुद पिन बनाना होता है और निकासी के समय ओटीपी आता है, जिससे सुरक्षित तरीक़े से खाते से रक़म निकाली जाती है।

उपलब्धता की सुविधाः चौबीसों घंटे धन

मध्य प्रदेश में एक बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट ने कहा, ''अगर बैंक की छुट्टी हो और आप अपना पैसा नहीं निकाल सकते हों तो? पहले बहुत कम लोगों के पास डेबिट कार्ड होते थे। आपका पैसा बैंक में फंस जाता था।'' एक बैंक कई लोगों के लिए होते हैं। साथ ही बैंक की छुट्टी भी होती है। हरियाणा में एक बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट ने कहा, ''पेंशन निकालने आए बुज़ुर्गों की लंबी कतारें थीं। जिस दिन पेंशन जमा होती है, वे उसी दिन आते हैं। बैंक सबका काम एक ही दिन में नहीं कर पाता, इसलिए निकासी में देर हो जाती है।''

डिजिटल उपलब्धता से लोगों को किसी भी वक्त और कहीं भी अपनी रक़म मिल जाती है। एक बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट ने कहा कि डिजिटल भुगतान से रोज़गारी की चिंता किए बिना एकदम सही रक़म देना आसान हो जाता है। विभिन्न राज्यों में कई बैंकिंग करेस्पॉन्डेंटों ने बताया कि कोई पैसे लाना भूल जाए या अचानक ख़रीदारी

...रनी पड़े तो बाज़ार में आराम से सामान ख़रीदा जा सकता है।

बजट बनाना हुआ आसान

हरियाणा में एक बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट ने कहा, 'फ़ोन में सारे लेनदेन देखना और अपने खर्चों का बजट बनाना आसान हो जाता है।' नेट बैंकिंग से बैंक स्टेटमेंट आसानी से मिल जाता है। खातों से जुड़े डिजिटल भुगतान एप्स से खाते में मौजूद रक़म आसानी से देखी जा सकती है। फ़ोन से हरेक परिवार के लिए निजी वित्तीय प्रबंधन आसान हो जाता है और डिजिटल वित्तीय नागरिकता मज़बूत होती है।

खातों से जुड़े डिजिटल भुगतान एप्स से खाते में मौजूद रक़म आसानी से देखी जा सकती है। फ़ोन से हरेक परिवार के लिए निजी वित्तीय प्रबंधन आसान हो जाता है और डिजिटल वित्तीय नागरिकता मज़बूत होती है।

बाधाएं लांघना: सभी के लिए वित्त की उपलब्धता

बढ़ती जागरूकता और डिजिटल वित्तीय साक्षरता शिविरों ने डिजिटल वित्तीय प्रणालियों की सुगमता बढ़ा दी है। कई राज्यों में बैंकिंग करेस्पॉन्डेंटों ने बताया गांव में लगभग सभी पुरुष या तो स्वयं या बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट की मदद से डिजिटल वित्तीय सेवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। शिक्षा के बढ़ते स्तर ने अपना व्यापार चला रही, नौकरी कर रही अथवा स्नातक कर चुकी कई युवा महिलाओं को ऑनलाइन वित्तीय लेनदेन करना सिखा दिया है। महिलाओं समेत कई बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट ख़ास तौर पर अपने गांव की महिलाओं को शिक्षित और प्रशिक्षित करते हैं ताकि वे डिजिटल एवं वित्तीय रूप से सशक्त हो सकें।

वित्तीय सेवाओं की डिजिटल सुलभता ने उम्र की बाधा भी खत्म कर दी है। कई युवा उत्साह से डिजिटल तरीकों का इस्तेमाल करते हैं और बुजुर्ग भी दूर स्थित बैंकों के चक्कर लगाए बग़ैर आराम से अपनी पेंशन पा सकते हैं। अब उन्हें लंबे पेचीदा फॉर्म भरने की ज़रूरत भी नहीं है। मध्य प्रदेश में एक बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट ने कहा, "बुजुर्ग और आदिवासी महिलाएं मदद मांगने हमारे पास आती हैं।" उसी राज्य में एक अन्य बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट उन बुजुर्गों और महिलाओं की मदद के लिए उनके घर जाता है, जो अपने घर से निकल नहीं सकते। धन निकालने के लिए फिंगरप्रिंट मशीन ने बुजुर्गों और कम साक्षरता स्तर वाले लोगों के लिए भी धन प्राप्त करना आसान कर दिया है।

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

कारोबार और उद्यमियों को ताकत

मध्य प्रदेश से एक बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट ने बताया, "कोविड लॉकडाउन के समय से ही लगभग सभी दुकानदारों ने क्यूआर कोड रख लिए हैं।" डिजिटल भुगतान ख़रीदारी की सुविधा को बढ़ावा देता है और उद्यमी को भी डिफॉल्ट (जानबूझकर पैसा नहीं देना) के बगैर आसानी से भुगतान मिल जाता है। ज्यादातर कारोबारी अपने वेंडरों (माल की आपूर्ति करने वालों) को बड़ी रक़म भेजने, नक़द निकालने या रक़म जमा करने के लिए बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट के पास पहुंचते हैं। कुछ ने स्वयं ही डिजिटल बैंकिंग का इस्तेमाल सीख लिया है और अब बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट के पास नहीं जाते। किराने की दुकान चलाने वाली, डेयरी या दर्ज़ी की दुकान चलाने वाली कई महिला उद्यमी अपना धंधा बढ़ाने के लिए डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल करती हैं।

चुनौतियां डिजिटल भारत शुरू करते समय इंटरनेट और सर्वर कनेक्टिविटी नीति निर्माताओं के लिए सबसे बड़ी चिंता थीं। पूरे देश में इंटरनेट और मोबाइल की पैठ सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए। बहुत कुछ बदल चुका है किंतु अभी लंबा रास्ता तय करना है। कुछ बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट ने कहा कि उन्हें कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। दूसरी ओर कुछ ने कहा कि उन्हें कभीकभार नेटवर्क और सर्वर की दिक्कत होती है। कुछ अन्य करेस्पॉन्डेंट ने बताया कि डिजिटल सफ़र की शुरुआत की तुलना में अब नेटवर्क कनेक्टिविटी सुधरी है।

मध्य प्रदेश में एक गांव में उस समय बहुत भ्रम फैल गया, जब उनके खातों में ऑनलाइन दिख रही रक़म और ब्रांच से मिलने वाली रक़म की जानकारी अलग-अलग थी। इसका कारण यह था कि बैंक का सर्वर डाउन था। पंद्रह दिन तक यही चलता रहा और उपयोगकर्ताओं का भरोसा ख़त्म हो गया। उपयोगकर्ताओं का भरोसा उस समय भी खत्म हो जाता है, जब नेटवर्क और सर्वर की दिक्क़तों के कारण ऑनलाइन लेनदेन के दौरान

उनका पैसा बीच में ही अटक जाता है। उपयोगकर्ताओं के मन में धोखाधड़ी का डर, डिजिटल प्रणाली के प्रति अविश्वास और इंटरनेट की समझ कम होने से स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। राजस्थान में एक बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट ने कहा, ''समय बीतने के साथ और अनुभव से हमें पता है कि रक़म अधिकतम 7 दिनों में खाते में लौट आएगी। इसलिए अब हम व्यक्ति को पूरे भरोसे के साथ आश्वस्त कर देते हैं।''

शिकायत निवारण व्यवस्था

आम तौर पर व्यक्ति शिकायत लेकर सबसे पहले बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट के पास ही जाता है। बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट और उपयोगकर्ता अपनी शिकायतें दर्ज़ कराने के लिए बैंक के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करते हैं। कई बैंक अधिकारियों के पास भी पहुंचे हैं। राजस्थान में एक महिला बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट को अपना पैसा ऑनलाइन शिकायत दर्ज़ कराने के बाद मिला क्योंकि बैंक अधिकारी कोई जवाब ही नहीं दे रहे थे। वरिष्ठ अधिकारियों की कार्रवाई पर शाखा अधिकारी ने उसे फ़ोन कर आवेदन पर हस्ताक्षर के लिए आने को कहा और इस बात पर आश्चर्य प्रकट किया कि उसने ऑनलाइन शिकायत दर्ज़ कराई है। एक अन्य बैंक करेस्पॉन्डेंट बैक जाने से बचता है क्योंकि बैंक अधिकारी अभद्र हैं। विकलांगता के शिकार एक व्यक्ति को लगा कि रक़म भेजने के उसके आवेदन को ज्यादा बारीकी से जांचा गया क्योंकि अधिकारियों को लगा कि उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, जबकि उन्हें पता था कि वह बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट है। लेकिन ज़्यादातर बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट ने दिक्क़त नहीं होने की बात कही और उन्हें समस्याएं दूर करने के लि बैंक जाना भी नहीं पड़ा।

शिक्षा के बढ़ते स्तर ने अपना व्यापार चला रही, नौकरी कर रही अथवा स्नातक कर चुकी कई युवा महिलाओं को ऑनलाइन वित्तीय लेनदेन करना सिखा दिया है। महिलाओं समेत कई बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट ख़ास तौर पर अपने गांव की महिलाओं को शिक्षित और प्रशिक्षित करते हैं ताकि वे डिजिटल एवं वित्तीय रूप से सशक्त हो सकें।

धोखे के शिकार: भरोसे और साक्षरता की कमी

डिजिटल भुगतान का प्रयोग बढ़ने के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले भी बढ़े हैं। अपराधी स्वयं को बैंक अधिकारी बताकर भोले भाले लोगों, आम तौर पर निरक्षर उपयोगकर्ताओं से गोपनीय जानकारी हासिल कर लेते हैं। अपने शिकार के खाते से वे बड़ी रक़म निकाल लेते हैं या खाता ख़ाली ही कर देते हैं। अधिकतर लोग प्रौद्योगिकी पर संदेह करते हैं और ऐसी घटनाएं उनका भरोसा और भी कम कर देती हैं।

महिलाओं में डिजिटल वित्तीय सेवाओं का प्रयोग

जब हमने पूछा कि गांव में कितनी महिलाएं इन सेवाओं का उपयोग करती हैं तो आम तौर पर जवाब मिला, ''बहुत कम महिलाएं इसका इस्तेमाल करती हैं।'' हमें ताज्जुब हुआ कि किसी गांव में केवल 1 प्रतिशत तो किसी में 45 प्रतिशत तक महिलाएं ही फ़ोन इस्तेमाल करती हैं। डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल करने वालों में अधिकतर शिक्षित एवं स्नातक और कामकाजी महिलाएं ही थीं, जिससे पता चलता है कि लड़कियों में शिक्षा की दर बढ़ रही है।

Elite Academy for Education & Training Pvt. Ltd. *Delhi*

मध्य प्रदेश में एक बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट ने बताया, ''45 साल से अधिक उम्र वाली बहुत कम महिलाएं फ़ोन इस्तेमाल करती हैं।'' उसने कहा कि जिन महिलाओं के बैंक खाते हैं, उनके भी पति का फ़ोन नंबर ही खाते के साथ रजिस्टर है और पति ही उनके खाते

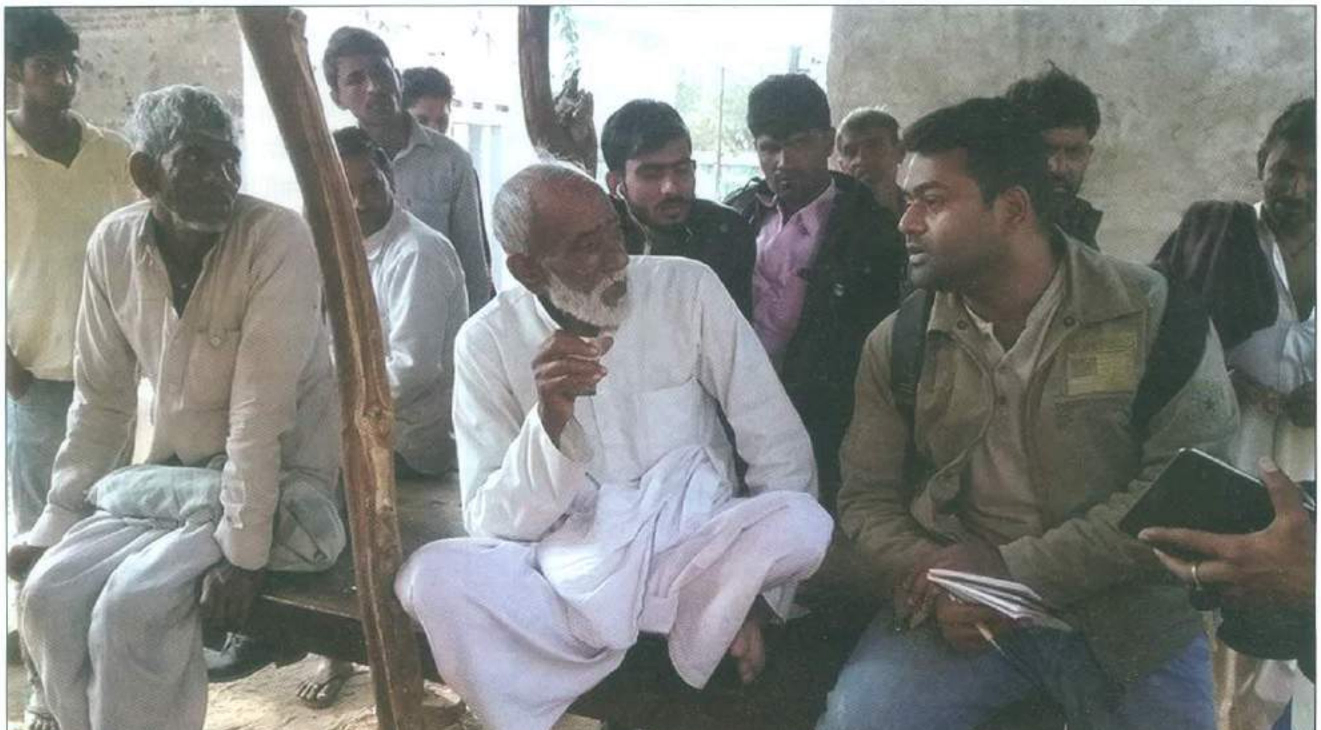

चलाते हैं। कुछ जगहों पर शिक्षित युवा लड़कियां फ़ोन रिचार्ज कराने या भुगतान करने के लिए इसका सीमित इस्तेमाल करती हैं। इससे महिलाओं के बैंक खाते खोलने और उनकी वित्तीय भागीदारी बढ़ाने तथा उन्हें वित्तीय आज़ादी दिलाने की सरकार की कोशिशों को ठेस लगती है।

मध्य प्रदेश से एक अन्य बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट ने कहा, ''उन्हें दिलचस्पी ही नहीं है। मैंने उन्हें इसकी अहमियत समझाने की कोशिश की है मगर वे समझतीं ही नहीं। उनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं हैं।'' जिनके पास फ़ोन हैं, वे कीपैड वाले हैं। राजस्थान में एक बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट ने कहा, ''एंड्रॉयड फ़ोन ज़्यादातर घर के मर्द, पति और बेटों के पास ही हैं और वे ही डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं।''

कई बैंकिंग करेस्पॉन्डेंटों के लिए काम करना मुश्किल होता है। कुछ कमाई बरकरार रखने के लिए दूसरे काम भी करने लगे हैं या इसी से जुड़ी दूसरी सेवाओं में शामिल हो गए हैं। राजस्थान में एक बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट कहती है, ''मेरी दुकान मेरे घर में है और गांव से बाहर की तरफ़ है। मेरे पास कम ग्राहक आते हैं। मैं गांव में दुकान खोलना चाहती हूं मगर उसके लिए मुझे धन और बुनियादी ढांचा चाहिए।''

पुरुषों को वित्तीय तथा घर के अधिकार देने वाले पितृसत्तात्मक नियम डिजिटल बुनियादी ढांचे और सेवाओं तक महिलाओं की पहुंच में बाधा बनते हैं। हमने बताया है कि कुछ बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट उन महिलाओं के घर जाते हैं, जो अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकतीं। इससे डिजिटल वित्तीय सेवाएं कुछ हद तक तो उपलब्ध होती हैं किंतु अन्य उपयोगकर्ताओं को मिलने वाली डिजिटल आज़ादी उन्हें नहीं मिल पाती।

राजस्थान में एक बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट कहती है, ''मैं पर्दा करती हूं। पुरुष मुझसे सीधे बात करने में असहज रहते हैं। वे या तो अपनी पत्नियों को लाते हैं या मैं बुज़ुर्ग महिलाओं अथवा बच्चों की मदद से उनसे बात करती हूं।'' उसे कम काम मिलता है क्योंकि बहुत कम पुरुष उसके पास काम के लिए आते हैं।

बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट की आजीविका

कई बैंकिंग करेस्पॉन्डेंटों के लिए काम करना मुश्किल होता है। कुछ कमाई बरकरार रखने के लिए दूसरे काम भी करने लगे हैं या इसी से जुड़ी दूसरी सेवाओं में शामिल हो गए हैं। राजस्थान में एक बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट कहती है, ''मेरी दुकान मेरे घर में है और गांव से बाहर की तरफ़ है। मेरे पास कम ग्राहक आते हैं। मैं गांव में दुकान खोलना चाहती हूं मगर उसके लिए मुझे धन और बुनियादी ढांचा चाहिए।'' दूसरे बैंकिंग करेस्पॉन्डेंटों को काम करना मुश्किल लगता है क्योंकि वे काम के लिए ज़रूरी लैपटॉप, स्कैनर आदि नहीं ख़रीद सकते।

कभी-कभी ग्राहक बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट के निजी खाते में रक़म जमा कर देते हैं, जो उनकी ओर से पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर करता है। ''चूंकि मैं उस बैंक का बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट नहीं हूं, जहां मेरा अपना खाता है, इसलिए बैंक मुझसे शुल्क वसूलता है और मैं ग्राहक से वह भरने के लिए कहता हूं।'' कुछ बैंकिंग करेस्पॉन्डेंटों ने बताया कि दूसरे बैंकों के बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट आने से और लोगों में डिजिटल कामकाज खुद ही करने की जानकारी बढ़ने से भी उनके काम पर असर पड़ा है।

राजस्थान में एक बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट को नई योजनाएं या बदलाव भ्रामक लगते हैं और वह बैंकों से नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की ज़रूरत बताता है। अद्यतन जानकारी से लोगों का भरोसा बनाए रखने में मदद मिलेगी। कुछ बिजनेस करेस्पॉन्डेंट कहते हैं कि अन्य इंटरमीडियरी ग्राहकों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं, पूरी जानकारी नहीं देते अथवा धोखाधड़ी करते हैं। मध्य प्रदेश में एक बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट कहता है, ''भरोसा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए हम निकाली गई रक़म और बची हुई रक़म बताने वाली पर्चियां देते हैं, जिन पर ग्राहक दस्तख़त करते हैं। हम अपना रिकॉर्ड भी रखते हैं।''

'फ़िजिटल' बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं में नवाचार

समय-समय पर बैंक, सरकारों और निजी संस्थाओं ने वित्तीय समावेशन के दो स्तंभों – उपलब्धता एवं आपूर्ति पर काम करने का प्रयास किया है। हाल ही में वित्त मंत्री ने इंडियन बैंक्स एसोसिएशन से ग्रामीण भारत में बैंकिंग सेवाओं की पैठ बढ़ाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इसके लिए बैंकों को तय करना चाहिए कि कहां उनकी शाखाएं होनी चाहिए और कहां डिजिटल सेवाएं दी जा सकती हैं।[5] विश्व आर्थिक मंच मानता है कि फ़िजिकल एवं डिजिटल तरीकों के बीच संतुलन बिठाने वाली फ़िजिटल रणनीति नए दौर में एकदम ज़रूरी बन रही है।[6] इस लिहाज़ से नए उत्पाद तैयार करना और उत्पादों एवं सेवाओं की सरलीकृत आपूर्ति के लिए नियम आसान करना इस समय की ज़रूरत है। बैंक और निजी कंपनियां भरोसा बढ़ाने तथा डिजिटल साक्षरता की समस्याएं ख़त्म करने के लिए बैंकिंग करेस्पॉन्डेंटों और उपयोगकर्ताओं हेतु जागरूकता एवं प्रशिक्षण में निवेश कर सकते हैं। ऑफलाइन बैंकिंग के ज़रूरी पहलुओं को बरकरार रखते हुए ऑफलाइन से ऑनलाइन की दिशा में ले जाने वाले एकजुट प्रयास की ज़रूरत है। फ़िजिकल और डिजिटल को एक दूसरे का पूरक बनाने वाला मॉडल ही डिजिटल तथा वित्तीय रूप से सशक्त 'भारत' का रास्ता है। ■

संदर्भ

1. https://economictimes.indiatimes.com/small-biz/money/addressing-the-need-gaps-how-indias-fintechs-can-make-deeper-inroads-in-rural-india/articleshow/88084255.cms?from=mdr
2. https://www.business-standard.com/article/current-affairs/internet-connectivity-in-rural-india-growing-at-fast-pace-sitharaman-122021101204_1.html
3. https://www.weforum.org/agenda/2020/01/help-india-rural-population-go-digital/
4. https://www.deccanherald.com/business/business-news/micro-atms-driving-digital-economy-in-rural-india-1081143.html
5. https://economictimes.indiatimes.com/small-biz/money/addressing-the-need-gaps-how-indias-fintechs-can-make-deeper-inroads-in-rural-india/articleshow/88084255.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cpps
6. https://www.weforum.org/agenda/2020/06/phygital-strategy-isolation-economy/

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

समावेशी बुनियादी ढांचा

सचिन चतुर्वेदी

भारतीय अर्थव्यवस्था, हाल के दिनों में, समावेशी विकास पर केंद्रित रही है। इसमें सामाजिक क्षेत्र, रोज़गार सृजन, कम कार्बन उत्सर्जन और प्रौद्योगिकी नवाचार पर ज़ोर दिया गया है। हालांकि वार्षिक बजट में पिछले कुछ वर्षों में इन मुद्दों को व्यापक रूप से संबोधित किया गया है, कोई भी इस तथ्य को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता है कि पूरी दुनिया में और भारत में भी कमज़ोरियों में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ-साथ जीवन और आजीविका के लिए अप्रत्याशित अनुपात में चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं।

नई आर्थिक नीति में नई रिवायत के आधार पर निम्नलिखित पांच विशेषताओं को उजागर किया गया है, जो न केवल इस वर्ष के बजट में, बल्कि पिछले दो वर्षों के बजट से भी स्पष्ट होता है। ये पांच प्रमुख विशेषताएं हैं- मात्रात्मक परिणामों पर गुणवत्तापूर्ण सामाजिक क्षेत्र विकास प्रदान करना; व्यापक आजीविका सृजन में सहायता के लिए पात्रता से उद्यमिता दृष्टिकोण की ओर बढ़ना; विकास का स्थानीयकरण; आर्थिक विकास में कम कार्बन उत्सर्जन के उपाय और डिजिटल तथा तकनीकी समाधानों का लाभ उठाना। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में वार्षिक बजट में इन मुद्दों को व्यापक रूप से संबोधित किया गया है, कोई भी इस तथ्य को नज़रअंदाज नहीं कर सकता है कि पूरी दुनिया में और भारत में भी कमज़ोरियों में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ-साथ जीवन और आजीविका के लिए चुनौतियां अप्रत्याशित अनुपात में बढ़ी हैं। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में गुणवत्तापूर्ण आर्थिक विकास प्राप्त करने, उद्यमिता को बढ़ावा देने और प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने के लिए सरकार ने लगातार प्रयास किए हैं जिससे तेज़ी से स्थिति में सुधार हुआ है लेकिन, अब भी बहुत सी ऐसी चिंताएं हैं जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है। इसके लिए 2020 में महामारी के झटके से उबरने के लिए घोषित राहत उपायों को सख्ती से आगे बढ़ाने के लिए लघुकालिक और दीर्घकालिक शमन कार्यनीतियां ज़रूरी हैं।

पिछले कुछ वर्षों में सामाजिक बुनियादी ढांचे के विकास पर सरकार का सक्रियता से ध्यान देना इस तथ्य में परिलक्षित होता है कि ग्रामीण सड़कों, आवास, पेयजल, संधारणीय शहरीकरण तथा परिवहन और स्वास्थ्य देखभाल के लिए बुनियादी ढांचागत क्षेत्रों में प्रमुख केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए कुल बजट आवंटन में वृद्धि हुई है। सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं (तालिका 1) के लिए यह 2019-20 (वास्तविक) के लगभग 19 प्रतिशत (वास्तविक) से बढ़कर लगभग 33 प्रतिशत (बीई) तक हो गया है और समावेशी सुधार में सहायता के लिए व्यापक परिप्रेक्ष्य का सुझाव दिया गया है।

आर्थिक अवसरों का विस्तार

बुनियादी सुविधाओं को मज़बूत करने के लिए, विशेषकर विकास को सक्षम करने और नौकरी के अवसर प्रदान करने के लिए सामान्य रूप से दूरसंचार क्षेत्र और विशेष रूप से 5जी प्रौद्योगिकी के लिए प्रावधान शामिल हैं। इसके अलावा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भूस्थानिक सिस्टम तथा ड्रोन, सेमीकंडक्टर तथा इसके पारिस्थितिक तंत्र, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, जीनोमिक्स तथा फ़ार्मास्यूटिकल्स, हरित ऊर्जा और प्रदूषणरहित परिवहन व्यवस्था क्षेत्र में विकास के लिए अवसर हैं, जिनमें बड़े पैमाने पर सतत विकास में सहायता करने और देश के आधुनिकीकरण की अपार संभावनाएं हैं। साथ ही, ये

लेखक विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली (आरआईएस), नई दिल्ली में महानिदेशक हैं। ईमेल: dgoffice@ris-org-in

तालिका 1 : केंद्र प्रायोजित योजनाओं- बुनियादी ढांचा संबंधी योजनाओं के लिए बजट आवंटन (करोड़ रु. में)

केंद्र प्रायोजित योजनाए	2019-20 (वास्तविक)	2020-21 (वास्तविक)	2021-22 (संशोधित)	2022-23 (बजट अनुमान)
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	14017.48	13687.50	14000.00	19000.00
प्रधानमंत्री आवास योजना	24963.65	40259.84	47389.84	48000.00
जल जीवन मिशन राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन	10030.42	10998.22	45011.00	60000.00
प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन				4176.84
शहरी कायाकल्प मिशन: अमृत और स्मार्ट सिटीज मिशन	9598.68	9753.61	13900.00	14100.00
उप-कुल	*58610.23 (18.9)*	*74699.17 (19.5)*	*120300.84 (29)*	*145276.84 (32.8)*
कुल योग	**309552.68**	**383975.69**	**415350.81**	**442781.19**

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★Delhi★

स्रोत: भारत सरकार के विभिन्न वर्षों के केंद्रीय बजट से लेखक का संकलन।

युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर प्रदान करते हैं, और भारतीय उद्योग को अधिक कुशल तथा प्रतिस्पर्धी बनाते हैं। इस संबंध में, सरकार ने सहायक नीतियों, कम कड़े विनियमों, घरेलू क्षमता निर्माण के कार्यों और अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने का भी वादा किया है। अनुसंधान एवं विकास के लिए शिक्षाविदों, उद्योग और सार्वजनिक संस्थानों के बीच सहयोग के प्रयासों के अलावा, सरकारी सहायता सुनिश्चित की गई है।

चूंकि आवास ढांचागत विकास का एक अभिन्न अंग है, इसलिए आशा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र ग्रामीण और शहरी दोनों लाभार्थियों के लिए 2022-23 में 80 लाख मकानों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इस संबंध में केंद्र सरकार शहरी क्षेत्रों में मध्यम वर्ग और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए सभी भूमि और निर्माण से संबंधित स्वीकृतियों के लिए आवश्यक समय में कमी करने और किफायती आवास को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करेगी। मध्यस्थता की लागत में कमी के साथ-साथ पूंजी सुलभ कराने के लिए वित्तीय क्षेत्र के नियामकों को शामिल किया जाएगा।

प्रधानमंत्री गति शक्ति और पूर्वोत्तर की ज़रूरतों पर आधारित सामाजिक विकास परियोजनाओं की भावना के अनुरूप, क्षेत्र के विकास को गति देते हुए, एक नई योजना-पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल, को पूर्वोत्तर परिषद के माध्यम से लागू किया जाएगा ताकि बुनियादी ढांचे के लिए वित्त प्रदान किया जा सके। चूंकि विरल आबादी वाले सीमावर्ती गांव, सीमित संपर्क और बुनियादी ढांचे के कारण अक्सर विकास लाभ से छूट जाते हैं, इसलिए पूर्वोत्तर सीमा पर ऐसे गांवों को नए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत कवर किया जाएगा। इनमें ग्रामीण बुनियादी ढांचे का निर्माण, आवास, पर्यटन केंद्र, सड़क संपर्क, विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा का प्रावधान, दूरदर्शन और शैक्षिक चैनलों की सीधे घर तक पहुंच और आजीविका सृजन के लिए सहायता जैसे उपाय शामिल हैं।

शहरी विकास के लिए, शहरी क्षेत्र की नीतियों, क्षमता निर्माण, नियोजन, कार्यान्वयन और संचालन के बारे में सुझाव देने के लिए प्रतिष्ठित शहरी योजनाकारों, शहरी अर्थशास्त्रियों और संस्थानों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। शहरी क्षमता निर्माण के लिए राज्यों को सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही, भवन उप-नियमों, नगर नियोजन योजनाओं (टीपीएस) और पारगमन अनुकूलन विकास (टीओडी) के आधुनिकीकरण को लागू किया जाएगा। बड़े पैमाने पर पारगमन परियोजनाओं और अमृत

लाभ

- स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं से, व्यक्तियों का स्वास्थ्य विवरण तैयार करना
- क्लिनिकल निर्णय में सुधार
- गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की समान सुलभता में सुधार
- टेलिमेडिसिन जैसी प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को बढ़ावा
- स्वास्थ्य सेवाओं की नैशनल पोर्टेबिलिटी
- स्वास्थ्य देखभाल तंत्र में रोज़गार सृजन

योजना के लिए केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता राज्यों द्वारा नगर नियोजन योजनाओं और पारगमन अनुकूलन विकास की सुविधा के लिए कार्य योजनाओं के निर्माण और उनके कार्यान्वयन के लिए दी जाएगी। शहरी नियोजन तथा डिज़ाइन को मज़बूत करना और इन क्षेत्रों में प्रमाणित प्रशिक्षण देने के लिए, विभिन्न क्षेत्रों में पांच मौजूदा शैक्षणिक संस्थानों को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया जाएगा और प्रत्येक को 250 करोड़ रुपये की बंदोबस्ती निधि भी प्रदान की जाएगी। एआईसीटीई को शहरी नियोजन पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार करने का काम सौंपा जाएगा।

केंद्रीय बजट में पूंजीगत व्यय के लिए परिव्यय में एक बार फिर से बढ़ोतरी की गई है। इसे वर्ष 2021-22 के 5.54 लाख करोड़ रुपये से 35.4 प्रतिशत बढ़ाकर 2022-23 में 7.50 लाख करोड़ रुपये किया जा रहा है। यह 2019-20 के व्यय के 2.2 गुणा से अधिक और सकल घरेलू उत्पाद का 2.9 प्रतिशत होगा। राज्यों को सहायता अनुदान के माध्यम से पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण के साथ किए गए इस निवेश के साथ, केंद्र सरकार का 'प्रभावी पूंजीगत व्यय' 2022-23 में 10.68 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 4.1 प्रतिशत होगा।

आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, भूस्थानिक सिस्टम तथा ड्रोन, सेमीकंडक्टर तथा इसके पारिस्थितिक तंत्र, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, जीनोमिक्स तथा फ़ार्मास्यूटिकल्स, हरित ऊर्जा और प्रदूषणरहित परिवहन व्यवस्था क्षेत्र में विकास के लिए अवसर हैं, जिनमें बड़े पैमाने पर सतत विकास में सहायता करने और देश के आधुनिकीकरण की अपार संभावनाएं हैं।

कौशल विकास

शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत 'उच्च शिक्षा संस्थानों में स्टार्टअप इंडिया पहल के लिए बजटीय आवंटन को 2021-22 में 30 करोड़ रुपये से 100 प्रतिशत बढ़ाकर 60 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा, कौशल विकास और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के विषय पर आधारित स्टार्टअप्स को विभिन्न अनुप्रयोगों के माध्यम से और ड्रोन सेवा के रूप में 'ड्रोन शक्ति' की सुविधा के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सभी राज्यों में चुनिंदा आईटीआई में कौशल विकास के लिए ज़रूरी पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में, महत्वपूर्ण कौशल सोच को बढ़ावा देने के लिए, रचनात्मकता को स्थान देने के लिए, 2022-23 में विज्ञान और गणित में 750 वर्चुअल प्रयोगशालाएं, और 75 कौशल ई-प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। एक और महत्वपूर्ण क़दम यह उठाया जा रहा है कि देश भर के विद्यार्थियों को विश्व स्तर की गुणवत्ता वाली सार्वभौमिक शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना सुनिश्चित करने के लिए एक डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। इसमें विभिन्न भारतीय भाषाओं और आईसीटी प्रारूपों में शिक्षा प्रदान की जाएगी।

इसके अलावा, यह भी परिकल्पना की गई है कि गिफ्ट सिटी में विश्व स्तरीय विदेशी विश्वविद्यालयों और संस्थानों को वित्तीय सेवाओं और प्रौद्योगिकी के लिए उच्च स्तर के मानव संसाधनों की उपलब्धता की सुविधा के लिए वित्तीय प्रबंधन, फ़िनटेक, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में घरेलू नियमों से मुक्त पाठ्यक्रम प्रदान करने की अनुमति दी जाएगी।

निरंतर कौशल के अवसरों की संधारणीयता और रोज़गार क्षमता को बढ़ावा देने के लिए कौशल कार्यक्रमों और उद्योग के साथ साझेदारी का पुनर्अनुकूलन किया जा रहा है। राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क को गतिशील उद्योग की ज़रूरतों के साथ जोड़ा जाएगा। कौशल और आजीविका के लिए डिजिटल इकोसिस्टम-देश-स्टैक ई-पोर्टल शुरू किया जाएगा। इसका उद्देश्य नागरिकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल, पुनर्कौशल या कौशल

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

तालिका 2 : बजट 2022-23 में स्वास्थ्य और आरोग्य (करोड़ रुपये)

	वास्तविक 2018-19	वास्तविक 2019-20	वास्तविक 2020-21	संशोधित अनुमान 2021-22	बजट अनुमान 2022-23	2021-22 की तुलना में 2022-23 ब. अनु. में प्रतिशत बदलाव
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग						
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	52954	62397	77569	82921	83000	0.10
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	1728	1934	3125	3080	3201	3.93
आयुष मंत्रालय	1554	1784	2126.46	2664.42	3050	14.47
उप कुल	***56236***	***66115***	***82820.46***	***88665.42***	***89251***	***0.66***
कोविड टीकाकरण		-	-	39000	5000	-87.18
जल और स्वच्छता विभाग	18412	18264	15967.3	51037	67221	31.71
जल जीवन मिशन	5484.15	10030	10998.22	45011	60000	33.30
कुल	**80132.15**	**94409**	**109786**	**223713.4**	**221472**	

स्रोत: भारत सरकार के विभिन्न वर्षों के केंद्रीय बजट से लेखक का संकलन।

विकास से सशक्त बनाना है। यह प्रासंगिक नौकरियों और उद्यमशीलता के अवसरों को खोजने के लिए एपीआई-आधारित विश्वसनीय कौशल प्रमाण-पत्र, भुगतान और डिस्कवरी लेयर भी प्रदान करेगा।

महामारी के कारण स्कूलों के बंद होने से, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति, और अन्य कमज़ोर वर्गों के ज्यादातर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे, लगभग दो साल तक स्कूल नहीं जा पाए थे और शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए थे। इसलिए, पूरक शिक्षण प्रदान करने और इसके लिए एक लचीला तंत्र बनाने की भी परिकल्पना की गई है। इस संबंध में, सभी राज्यों को क्षेत्रीय भाषाओं में पहली से बारहवीं कक्षा के लिए पूरक शिक्षा प्रदान करने के वास्ते सक्षम करने के लिए पीएम ईविद्या कार्यक्रम के वन क्लास वन टीवी चैनल को 12 से बढ़ाकर 200 कर दिया जाएगा।

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक प्लेटफार्म शुरू किया जाएगा। इसमें स्वास्थ्य-सेवा प्रदाताओं और स्वास्थ्य सुविधाओं की डिजिटल रजिस्ट्रियां, विशिष्ट स्वास्थ्य पहचान, सहमति ढांचा और स्वास्थ्य सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच शामिल होगी।

गुणवत्ता के विकास के लिए प्रतिस्पर्धी तंत्र के निर्माण के लिए डिजिटल शिक्षकों के माध्यम से इंटरनेट, मोबाइल फोन, टीवी और रेडियो के ज़रिए उपलब्ध कराने के लिए सभी भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाली ई-सामग्री विकसित करने की भी योजना है। विद्यार्थियों को शिक्षण के डिजिटल उपकरणों से लैस करने और बेहतर सीखने के परिणामों की सुविधा के लिए शिक्षकों द्वारा ई-कंटेंट स्थापित करने की भी योजना है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में नवाचार

कोविड-19 के मद्देनज़र और स्वास्थ्य और संबंधित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने के लिए, सरकार ने इन क्षेत्रों के लिए आवश्यक बढ़ाई गई सहायता जारी रखी है, जैसा कि तालिका-2 में दिया गया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक प्लेटफार्म शुरू किया जाएगा। इसमें स्वास्थ्य-सेवा प्रदाताओं और स्वास्थ्य सुविधाओं की डिजिटल रजिस्ट्रियां, विशिष्ट स्वास्थ्य पहचान, सहमति ढांचा और स्वास्थ्य सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच शामिल होगी।

कोविड-19 स्वास्थ्य संकट ने सभी उम्र के लोगों की मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा दिया है। इसे देखते हुए गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य तक बेहतर पहुंच प्रदान करने, परामर्श तथा देखभाल सेवाएं उपलब्ध कराने, उत्कृष्टता के 23 टेली-मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों के नेटवर्क के साथ एक 'राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम' की योजना बनाई जा रही है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निमहंस) नोडल केंद्र होगा और अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान-बेंगलुरु (आईआईआईटीबी) प्रौद्योगिकी सहायता प्रदान करेगा।

यह भी रेखांकित करने की आवश्यकता है कि भारत हमेशा सामूहिक आत्मनिर्भरता के लिए खड़ा रहा है। इसलिए, आत्मनिर्भर भारत का विकास अनुभव निश्चित रूप से सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक सहयोग बढ़ाने में आदर्श बदलाव लाने में सहायता कर सकता है। ■

Elite Academy for Education & Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद्र

नई दिल्ली	पुस्तक दीर्घा, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड	110003	011-24367260
नवी मुंबई	701, सी- विंग, सातवीं मंजिल, केंद्रीय सदन, बेलापुर	400614	022-27570686
कोलकाता	8, एसप्लानेड ईस्ट	700069	033-22488030
चेन्नई	'ए' विंग, राजाजी भवन, बसंत नगर	600090	044-24917673
तिरुअनंतपुरम	प्रेस रोड, नयी गवर्नमेंट प्रेस के निकट	695001	0471-2330650
हैदराबाद	कमरा सं 204, दूसरा तल, सीजीओ टावर, कवाड़ीगुड़ा, सिकंदराबाद	500080	040-27535383
बेंगलुरु	फर्स्ट फ्लोर, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला	560034	080-25537244
पटना	बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ	800004	0612-2675823
लखनऊ	हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, क्षेत्र-एच, अलीगंज	226024	0522-2325455
अहमदाबाद	4-सी, नेप्चून टॉवर, चौथी मंजिल, नेहरू ब्रिज कॉर्नर, आश्रम रोड	380009	079-26588669
गुवाहाटी	असम खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड, भूतल, एमआरडी रोड, चांदमारी	781003	0361.2668237

क्या आप जानते हैं?

अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी में स्टार्टअप

अंतरिक्ष क्षेत्र में सभी प्रकार की गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दूरगामी प्रभाव वाले सुधार लाए गए हैं।

अंतरिक्ष विभाग की स्वायत्त एजेंसी के रूप में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्रमाणीकरण केंद्र (आईएन-एसपीएसीई) का गठन किया गया है जो अंतरिक्ष गतिविधियों के संचालन को देखेगा और अंतरिक्ष विभाग के स्वामित्व वाली सुविधाओं को गैर सरकारी-निजी संस्थाओं (एनजीपीई) द्वारा संचालित कराने की व्यवस्था को भी देखेगा तथा भारत में इन एनजीपीई की अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए अनुमति, नियमन, संवर्धन, सहयोग और निगरानी की व्यवस्था भी करेगा।

रक्षा मंत्रालय ने रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्रों में नए स्टार्टअप लगाने को बढ़ावा देने की दिशा में उपाय किए हैं। प्रौद्योगिकी विकास कोष (टीडीएफ) योजना रक्षा मंत्रालय का ही कार्यक्रम है जिसे डीआरडीओ मेक-इन-इंडिया पहल के तहत चला रहा है। इस योजना को सितम्बर, 2016 में माननीय रक्षा मंत्री की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। सरकार ने विभिन्न रक्षा प्रौद्योगिकियां विकसित करने के उद्देश्य से उद्योगों और खासकर एमएसएमई और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए टीडीएफ योजना मंजूर की थी। यह योजना अनुदान-सहायता के आधार पर चलाई जा रही है। इस समय टीडीएफ योजना के तहत 3310.58 लाख रुपये की लागत वाली कुल छह परियोजनाओं के ठेके छह स्टार्टअप कंपनियों को दिए गए हैं जिनमें से एक परियोजना दो स्टार्टअप कंपनियों को दी गई है। डीआरडीओ के अनुसार हाइपरसोनिक वाहनों के बारे में सूचना संवेदनशील श्रेणी की है।

अटल नवाचार मिशन (एआईएम) देशभर में नए उद्यमियों और नवाचारों को समर्थन और बढ़ावा देता है और हाल के वर्षों में इस मिशन ने अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी से जुड़ी अनेक चुनौतियों और पहलों को मदद दी है।

- अटल टिंकरिंग लैब (एटीएल) योजना के तहत अटल नवाचार मिशन ने इसरो और सीबीएसई के सहयोग से सितंबर, 2021 में एटीएल स्पेस चैलेंज शुरू किया। यह एटीएल स्पेस चैलेंज देशभर के सभी स्कूली विद्यार्थियों के लिए खुला था और इसमें मोटे तौर पर चार चुनौती-विषय थे:- अंतरिक्ष की खोज, अंतरिक्ष में पहुंच, अंतरिक्ष में बसना और लाभ के लिए अंतरिक्ष। छह सप्ताह के समय में विद्यार्थियों को गाइड करके उन्हें प्रेरित करने के उद्देश्य से यू-ट्यूब के ज़रिए कुल आठ वर्चुअल लाइव सेशन कराए गए थे। चुनौती पूरी होने पर 2500 से ज्यादा प्रविष्टियां आईं और 6500 विद्यार्थी इसमें शामिल हुए। चोटी की 75 टीमों की घोषणा जनवरी, 2022 में की गई थी।
- अटल इनक्यूबेशन केंद्र (एआईसी) योजना के तहत एआईएम ने देशभर में अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी और संबद्ध उद्योगों में 15 से ज्यादा स्टार्टअप्स को सहायता दी। स्टार्टअप्स का मुख्य फोकस यूएवी, ड्रोन और निगरानी चौकसी उपकरण, एयरोटैक, एयर टैक्सी, अंतरिक्ष मलबे का पता लगाना और उस पर निगाह रखने की सेवाएं तथा अंतरिक्ष शिक्षा आदि अनेक विषयों पर है।
- एएनआईसी योजना के तहत इसरो के सहयोग से अटल नवाचार मिशन के एएनआईसी-अराइज़ कार्यक्रम ने नीचे बताए चार फोकस क्षेत्रों में चुनौती कार्य शुरू किए हैं।
  - क. प्रोपलशन - हरित नोदक, बिजली से प्रोपेल करना, उन्नत एयर ब्रीदिंग;
  - ख. मशीन के प्रयोग से भू-स्थैतिक (जियो-स्पैशियल) सूचना/कृत्रिम मेधा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन से सीखने पर आधारित है;
  - ग. रोबोटिक्स का इस्तेमाल, सशक्त वास्तविकता/वर्चुअल वास्तविकता (एआर/वीआर) तकनीकें।

एप्लीकेशन विकसित करने के आह्वान के साथ ये समस्या वक्तव्य स्टार्टअप्स एमएसएमई के लिए सार्वजनिक किए गए थे। तीन दौर की तकनीकी और वित्तीय समीक्षा के बाद छह स्टार्टअप्स को अनुदान सहायता के रूप में 12 महीने की अवधि में 50 लाख रुपये तक की मदद के लिए चुना गया है। ■

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

भविष्य है नवाचारों का

ऋषभ कृष्ण सक्सेना

वित्त और प्रौद्योगिकी के गठजोड़ को फ़ाइनैंशियल टेक्नोलॉजी यानी फ़िनटेक कहा जाता है और पिछले एक दशक में यह सबसे तेज़ी से वृद्धि करने वाले और नवाचार को सबसे अधिक बढ़ावा देने वाले उद्योगों में शुमार है। दुनिया भर में फ़िनटेक उद्योग अर्थव्यवस्था का काम करने का तरीका बदल रहा है। लगातार नए उत्पाद और नई प्रणालियों के साथ कारोबार के नए-नए रास्ते इससे खुल रहे हैं। नक़दरहित भुगतान से लेकर क्राउड फंडिंग और वर्चुअल करेंसी तक बहुत कुछ फ़िनटेक की ही देन है। पूरी दुनिया में 2010 से ही इस पर ज़ोर दिया जा रहा है और भारत में 2014 यानी श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने फ़िनटेक को बहुत बढ़ावा दिया है। प्रौद्योगिकी को आर्थिक और सामाजिक प्रगति का बड़ा हथियार मानने वाली सरकार ने स्टार्टअप इंडिया जैसे कार्यक्रमों के ज़रिये नवाचार को बहुत प्रोत्साहित किया है

अब शायद यह गुज़रे ज़माने की बात हो गयी जब किसी के खाते में रक़म जमा करने के लिए बैंक जाकर कतारों में लगना पड़ता था। नंबर नहीं आया तो अगले दिन फिर कतार। खरीदारी करते समय रेज़गारी के लिए जूझना पड़ता था और अचानक कुछ खरीदने का मन हो जाए तो देखना पड़ता था कि घर से पर्याप्त पैसे लेकर चले हैं या नहीं। इतना ही नहीं, बैंक में खाता खुलवाना किसी उपलब्धि से कम नहीं होता था, जिसके लिए तमाम कागज़ात लेकर बैंक में इंतज़ार करना पड़ता था और केवाईसी के नाम पर गाहे-बगाहे कागज़ात के साथ दोबारा बुला लिया जाता था। यह कहानी शहरों की थी। गांवों का हाल तो और बुरा था, जहां बैंक की शाखा मीलों दूर होने के कारण महीने में एकाध बार वहां चक्कर लगता था और उसमें भी काम नहीं बना तो अगले चक्कर की तारीख ही नहीं पता होती थी।

मगर अब इनमें से ज़्यादातर काम अब घर बैठे ही हो जाते हैं। आधी रात को भी रक़म भेजनी हो तो बस फोन पर यूनिफाइड पेमेंट सर्विस (यूपीआई) का इस्तेमाल करें या बैंक की एप्लिकेशन खोलें, चुटकियों में रक़म सामने वाले के खाते में पहुंच जाती है। कुछ खरीदने का मन है मगर जेब में पैसे नहीं हैं तो क्या हुआ? फोन निकालिए और क्यूआर कोड स्कैन कर वॉलेट या यूपीआई के ज़रिये भुगतान कर दीजिए। अब तो खाता खुलवाने के लिए भी बैंक नहीं जाना पड़ता। बस स्मार्टफ़ोन पर अपना ब्योरा भरिए, कागज़ात अपलोड कीजिए, वीडियो कॉल पर केवाईसी पूरा कराइए और कुछ ही घंटों में आपका खाता चालू हो जाएगा।

यह कमाल है फ़िनटेक का

वित्त और प्रौद्योगिकी के गठजोड़ को फ़ाइनैंशियल टेक्नोलॉजी यानी फ़िनटेक कहा जाता है और पिछले एक दशक में यह सबसे तेज़ी से वृद्धि करने वाले और नवाचार को सबसे अधिक बढ़ावा देने वाले उद्योगों में शुमार है। दुनिया भर में फ़िनटेक उद्योग अर्थव्यवस्था का काम करने का तरीका बदल रहा है। लगातार नए उत्पाद और नई प्रणालियों के साथ कारोबार के नए-नए रास्ते इससे खुल रहे हैं। नक़दरहित भुगतान से लेकर क्राउड फंडिंग और वर्चुअल करेंसी तक बहुत कुछ फ़िनटेक की ही देन है। पूरी दुनिया में 2010 से ही इस पर ज़ोर दिया जा रहा है और भारत में 2014 के बाद से यानी श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने फ़िनटेक को बहुत बढ़ावा दिया है। प्रौद्योगिकी को आर्थिक और सामाजिक प्रगति का बड़ा हथियार मानने वाली सरकार ने स्टार्टअप इंडिया जैसे कार्यक्रमों के ज़रिये नवाचार को बहुत प्रोत्साहित किया है, जिसका फ़ायदा देसी फ़िनटेक उद्योग को भी मिला है। मोदी सरकार द्वारा प्रारंभ की गई जनधन, आधार और मोबाइल (जैम) की त्रयी की सफलता का सबसे बड़ा लाभ फ़िनटेक

लेखक वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं। ईमेल: rishabhakrishna@gmail.com

यूपीआई के इस्तेमाल में बेहद तेज़ी

पहले नोटबंदी और उसके बाद कोविड लॉकडाउन के दौरान यूपीआई का इस्तेमाल बेहद तेजी से बढ़ा। अब अर्थव्यवस्था पूरी तरह खुल गई है मगर यूपीआई में सहूलियत के कारण इसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। फ़ोन पर सुरक्षित तरीके से महज एक टैब छूकर रक़म किसी के खाते में भेजने का मौक़ा मिले तो इसका फायदा क्यों न उठाया जाए। यही वजह है कि वित्त वर्ष 2021-22 के पहले 11 महीनों में यूपीआई से लेनदेन 76 लाख करोड़ रुपये से ऊपर पहुंच चुका है, जबकि वित्त वर्ष 2020-21 में कुल 41 लाख करोड़ रुपये का लेनदेन ही हुआ था। उम्मीद जताई जा रही है कि आंकड़ा जल्द ही 100 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच जाएगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक बता रहा है कि फरवरी महीने में ही 453 करोड़ लेनदेन हुए, जिनके जरिये 8.26 लाख करोड़ रुपये की आवाजाही हुई। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के मुताबिक फरवरी तक 4,049 करोड़ से अधिक लेनदेन कर लिए गए थे। जिस रफ्तार से यूपीआई आगे बढ़ रहा है, उसे देखकर एनपीसीआई को अगले 3 से 5 साल में रोजाना 100 करोड़ लेनदेन का आंकड़ा छूने की उम्मीद है।

यूपीआई की पैठ किस कदर बढ़ रही है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2021-22 में यूपीआई से होने वाले 50 फीसदी लेनदेन 200 रुपये से भी कम के थे। इससे पता चलता है कि मामूली सामान की खरीदारी के लिए भी अब यूपीआई का इस्तेमाल हो रहा है और गांव-देहात में भी यह बढ़ता जा रहा है।

यूपीआई की शुरुआत 2016 में हुई थी और नोटबंदी के दौरान इस्तेमाल बढ़ने के बावजूद हर महीने 100 करोड़ लेनदेन की उपलब्धि अक्टूबर 2019 में हासिल हो सकी। मगर साल भर के भीतर हर महीने 200 करोड़ लेनदेन का आंकड़ा यूपीआई ने हासिल कर लिया। 200 करोड़ से 300 करोड़ लेनदेन प्रतिमाह पहुंचने में 10 महीने और 300 करोड़ से 400 करोड़ लेनदेन प्रतिमाह होने में केवल तीन महीने लगे।

उद्योग को ही मिला। सरकार ने समाज कल्याण की योजनाओं में दिए जाने वाले धन के ऑनलाइन अंतरण की व्यवस्था शुरू कर फ़िनटेक की क्रांति को और भी रफ़्तार दी है। इससे न केवल पारदर्शिता आई बल्कि शत-प्रतिशत धनराशि लाभार्थियों को ही मिली।

इसी से फ़िनटेक हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल हो गया है। आपके वित्तीय कामकाज में जब भी प्रौद्योगिकी मदद करती है तब आप फ़िनटेक का फ़ायदा उठा रहे होते हैं। अगर आपने किसी भी सामान या सेवा की कीमत फ़ोन या किसी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के ज़रिये अदा की है, अपने बैंक खाते का ब्योरा ऑनलाइन जांचा है या रक़म अथवा शेयर एक खाते से दूसरे खाते में भेजे हैं तो अनजाने में ही आप अरबों डॉलर के फ़िनटेक उद्योग का हिस्सा बन चुके हैं। आइए आपको बताते हैं कि इस उद्योग की कौन सी ईजाद सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं और सबसे अधिक काम की भी हैं।

क्यूआर कोड: डिजिटल भुगतान व्यवस्था की सबसे बड़ी और अनूठी ईजाद क्यूआर कोड यानी क्विक रेस्पॉन्स कोड है। कभी सामान की पहचान के लिए बनाए गए ये कोड अब किसी भी लेनदेन का फायदा पाने वाले व्यक्ति की पहचान का काम करते हैं। आपने भी सब्ज़ी वाले से लेकर सुपरमार्केट या बड़े रिटेल स्टोरों तक काउंटरों पर ये कोड देखे होंगे। 2016 में हुई नोटबंदी और बाद में कोविड-19 महामारी के दौरान लगे लॉकडाउन में सबसे ज्यादा इज़ाफा इसी के इस्तेमाल में हुआ और सबसे ज्यादा राहत भी इसी ने दी। जब बैंक बंद होने के कारण नक़दी मिलनी मुश्किल थी उस समय लगभग सभी तरह की खरीदारी इसी की मदद से की गई। ये न तो डेबिट-क्रेडिट कार्ड की तरह जटिल होते हैं और न ही इनके लिए अलग से कोई कौशल चाहिए। बस, आपके पास कैमरे वाला स्मार्टफ़ोन होना चाहिए, बाकी सब आसान हो जाएगा। यही वजह है कि अब छोटे बाज़ार में कमोबेश हरेक दुकान पर आपको क्यूआर कोड दिख जाते हैं। छोटे शहरों और कस्बों में भी इनका इस्तेमाल बढ़ रहा है। भारतीय रिज़र्व बैंक की 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट बताती है कि दुकानों पर भारत क्यूआर कोड की संख्या 76 प्रतिशत बढ़कर मार्च 2021 के अंत में 35.70 लाख हो गई।

फ़िनटेक स्टार्टअप हमारी आपकी ज़िंदगी को सहूलियत भरा ही नहीं बना रहे हैं बल्कि रोज़गार भी दे रहे हैं। स्विगी, ज़ोमैटो हों या ओला, उबर अथवा ई-कॉमर्स कंपनियां हों, पर्दे के पीछे काम करने वालों की भर्तियां बढ़ी हैं और डिलिवरी के लिए बड़े पैमाने पर लोगों को काम दिया गया है। डिजिटल बैंकिंग ने भी देहाती इलाक़ों में रोज़गार के बड़े साधन दिए हैं, जिनमें बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट भी शामिल हैं। इनमें संभावनाएं देखकर निवेश भी खूब आ रहा है।

एनएफसी कार्ड: ख़रीदारी के लिए क्रेडिट या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल तो अच्छा लगता है मगर दो बातों का डर सभी को सताता है- कार्ड गुम हो जाने का और पिन किसी को पता लग जाने का। नियर फील्ड कम्युनिकेशन (एनएफसी) ने यह डर भी काफी हद तक खत्म कर दिया है। एनएफसी तकनीक वाले कार्डों को मशीन पर स्वाइप नहीं करना पड़ता, इसलिए पिन डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। इन कार्ड को स्वाइप मशीन के पास ले जाने भर से रक़म का लेनदेन हो जाता है। महामारी के दौरान लोगों ने खास तौर पर ऐसे कार्डों को हाथोहाथ लिया क्योंकि इन्हें किसी और को सौंपने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ग्राहक खुद उसे मशीन के पास ले जाता है और कुछ ही सेकंड में बगैर पिन के भुगतान हो जाता है। रिज़र्व बैंक के निर्देशों के मुताबिक इसमें अब बगैर पिन के 5,000 रुपये तक का भुगतान किया जा सकता है।

चौबीसों घंटे रक़म भेजना: एक समय था, जब किसी के खाते में रक़म भेजने के लिए सुबह-सुबह बैंक जाना पड़ता था। कोई अचानक पैसे मांग ले तो बैंक खुलने का इंतज़ार करना पड़ता था। प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म भरना हो तो बैंक जाकर ड्राफ्ट बनवाइए,

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. Delhi

चालान बनवाइए और बैंक का कामकाजी समय खत्म होते ही सब ठप हो जाता था। मगर अब आपके पास आईएमपीएस (इमीडिएट पेमेंट सर्विस), एनईएफटी (नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड्स ट्रांसफर) और आरटीजीएस (रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट) जैसे खाते में तुरंत रक़म भेजने के साधन हैं, जो चौबीस घंटे काम करते हैं। आपके पास कंप्यूटर नहीं है मगर स्मार्टफ़ोन है तो बैंक की ऐप डाउनलोड कर लीजिए और किसी भी समय रक़म भेज दीजिए। इस सुविधा के कारण ही ऑनलाइन लेनदेन में तेज़ी भी आ रही है। रिज़र्व बैंक की मई 2021 में जारी वित्त वर्ष 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट बताती है कि उस साल आरटीजीएस के ज़रिये लेनदेन में 5.7 प्रतिशत और एनईएफटी के ज़रिये लेनदेन में 12.7 प्रतिशत की तेज़ी आई। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के इस्तेमाल में भी 19-20 प्रतिशत इज़ाफा हुआ।

> **फ़िनटेक की आगे की कहानी इन निवेशकों पर भी निर्भर करेगी। बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में बदलाव लाने की इच्छा वाले निवेशक देख रहे हैं कि ग्राहक किस तरह प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक सहारा लेते जा रहे हैं। इसकी छोटी सी बानगी इसी बात से ली जा सकती है कि कम शिक्षित लोग भी बीमा पॉलिसी खरीदने या क्रेडिट कार्ड चुनने से पहले फ़ोन या कंप्यूटर पर तमाम विकल्प तलाशते हैं और नापतोल के बाद ही फ़ैसला करते हैं।**

यूपीआई: यूपीआई भी चौबीसों घंटे रक़म भेजने वाली सुविधा ही है और बाकी तरीक़ों के मुकाबले नया तरीका है। मगर इस्तेमाल के मामले में यह एनईएफटी, आईएमपीएस से मीलों आगे निकल चुका है। वर्ष 2016 में शुरू हुए यूपीआई के तहत अब हर महीने 8 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की रक़म का लेनदेन हो रहा है। इसकी बड़ी वजह यह है कि पी2पी फंड ट्रांसफर यानी एक व्यक्ति के खाते से सीधे दूसरे व्यक्ति के खाते में रक़म भेजना यूपीआई के कारण बेहद आसान हो गया है और लोग जमकर इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। इसके लिए केवल स्मार्टफ़ोन की ज़रूरत है और अब तो रिज़र्व बैंक ने फीचर फ़ोन के लिए भी यूपीआई शुरू कर दिया है। पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे और एमेज़ॉन पे यूपीआई की सुविधा देने वाली सबसे लोकप्रिय ऐप में गिनी जाती हैं। यूपीआई की बढ़ती लोकप्रियता के कारण ही तमाम बड़ी कंपनियां अपनी सेवाओं के लिए उसके ज़रिये भुगतान लेने को तैयार हैं।

वीडियो केवाईसी: बैंक, बीमा और वित्तीय सेवा क्षेत्र के लिए वीडियो केवाईसी किसी वरदान से कम नहीं है। कोविड महामारी के दौरान तो बैंक खाते खोलने और दूसरी बैंकिंग सेवाओं में यही काम आया। कोटक महिंद्रा बैंक और एचडीएफसी बैंक आदि बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। महामारी से पहले तक बैंक खाते खोलने के लिए बैंक जाना पड़ता था, फॉर्म भर कर दस्तावेज़ों की सत्यापित छायाप्रति जमा करनी पड़ती थीं। यह झंझट भरा काम था और पूरा होने में 3 से 5 दिन लग जाते थे। महामारी के दौरान जब लोग भीड़ में जाने से कतराने लगे तब वित्तीय कंपनियों ने इस जोखिम रहित तरीके को जमकर आज़माया। इसमें वीडियो कॉल पर ग्राहक से बात की जाती है, वह अपने दस्तावेज़ अपलोड कर देता है और चुटकियों में खाते खुल जाते हैं। इसका इस्तेमाल बैंक खाते ही नहीं, ट्रेडिंग खाते, डीमैट खाते, बीमा पॉलिसी और कई दूसरी सेवाओं के लिए किया जा सकता है। क्रेडिट कार्ड और कंज़्यमूर ड्यूरेबल उपकरणों की खरीद के लिए कर्ज़ लेने में भी इसका जमकर इस्तेमाल हो रहा है। इसमें कंपनियों का कागज़ और कर्मचारियों का खर्च बचता है तथा ग्राहकों का भी समय और पैसा बच जाता है। यही वजह है कि अब गांव-देहात में भी बैंक और ग़ैर बैंकिंग वित्तीय

Academy For Education & Techni... ★ Delhi ★

स्मार्टफ़ोन के बगैर भी चलेगा यूपीआई

भारत में यूपीआई का इस्तेमाल तो जमकर किया जाता है मगर देश का एक बड़ा वर्ग अभी तक इससे महरूम ही है। उसकी वजह थी यूपीआई के लिए स्मार्टफ़ोन ज़रूरी होना। बेहद ग़रीब तबका या ग्रामीण नागरिक स्मार्टफ़ोन नहीं होने के कारण इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। लेकिन मार्च में भारतीय रिज़र्व बैंक ने फीचर फ़ोन पर भी यूपीआई शुरू कर दिया, जिससे इस सुविधा की पैठ ज़बरदस्त तरीके से बढ़ेगी। यह मामूली बात नहीं है क्योंकि देश में अब भी क़रीब 40 करोड़ कनेक्शन फीचर फ़ोन यानी सामान्य फ़ोन पर चल रहे हैं, जिनमें इंटरनेट की सुविधा नहीं होती। इनमें ज्यादातर आर्थिक रूप से कमज़ोर तबके के लोग आते हैं। अभी तक उन्हें यूएसएसडी के जरिये यूपीआई चलाना होता था, जिसमें बहुत झंझट होते थे और इसीलिए इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता था। किंतु अब उनके लिए भी यूपीआई123पे नाम की सुविधा शुरू की गई है, जिसमें स्मार्टफ़ोन पर चलने वाले यूपीआई जैसी सरल है। इस पर पी2पी भुगतान, बिजली बिल आदि का भुगतान, फास्टैग रिचार्ज, मोबाइल बिल भुगतान और डीटीएच तथा मोबाइल रिचार्ज आदि किया जा सकता है। साथ ही बैंक खाते को फ़ोन नंबर से जोड़ने के बाद यूपीआई पिन सेट किया जा सकता है और किसी भी समय खाते में शेष राशि की जानकारी हासिल की जा सकती है।

इसे इस्तेमाल करना भी आसान है। सबसे पहले फीचर फ़ोन पर आईवीआर नंबर 08045163666 डायल करना होगा। उसके बाद आईवीआर मेन्यू पर अपनी पसंदीदा भाषा चुनकर वह बैंक चुनना होगा, जिसमें उपयोगकर्ता का खाता है। फिर दिए जा रहे निर्देशों का पालन करते हुए उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर डालना होगा, जिसे रक़म भेजनी है। इसके बाद भेजी जा रही रक़म डालनी होगी, अपना यूपीआई पिन डालना होगा और पैसा दूसरे खाते में पहुंच जाएगा।

बिल का भुगतान करना हो, रक़म भेजनी हो, खरीदारी करनी हो तो मिस्ड कॉल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। खरीदारी करते समय व्यापारी के पास मौजूद नंबर पर मिस्ड कॉल देने पर ग्राहक के पास वापस फ़ोन आएगा। फ़ोन पर यूपीआई पिन डालते ही रक़म व्यापारी के पास पहुंच जाएगी। आईवीआर के जरिये भी ऐसे कई काम किए जा सकते हैं।

कंपनियां (एनबीएफसी) पूरे तामझाम के साथ सामान्य शाखा खोलने के बजाय वर्चुअल तरीके से काम कर रहे हैं। नए खाते खोलने और ग्राहक बढ़ाने में वहां भी वीडियो केवाईसी उनकी बहुत मदद कर रहा है। इसका इस्तेमाल शुरू होने के बाद बैंकों में खाते खुलने की रफ़्तार भी बढ़ गई है। उद्योग विशेषज्ञ मान रहे हैं कि वीडियो केवाईसी का इस्तेमाल दूसरे क्षेत्रों में भी बढ़ेगा।

एईपीएसः आधार से चलने वाली भुगतान प्रणाली (एईपीएस) अभी बहुत ज़ोर नहीं पकड़ पाई है मगर झटपट रक़म भेजने के लिए यह भी बहुत कारगर है। इसमें किसी कार्ड या स्मार्टफ़ोन की ज़रूरत नहीं होती। उसके बजाय ग्राहक का बायोमेट्रिक्स यानी अंगूठे की छाप सत्यापन का काम करती है। यह आम तौर पर गरीबों, निरक्षरों या प्रवासी कामगारों के लिए बनाया गया था, जिन्हें अपने घर पर धन भेजने के लिए किसी ख़ास भुगतान प्रणाली या बैंक की ज़रूरत नहीं होती। बैंक और भुगतान कंपनियां दूर-दराज के ऐसे इलाक़ों और गांवों में इनका इस्तेमाल बढ़ा रही हैं, जहां एटीएम पर खर्च करने की कोई तुक नहीं। बायोमेट्रिक रीडर वाले माइक्रो एटीएम या छोटी पॉइंट ऑफ सेल मशीनों के ज़रिये लोगों को घर बैठे ही अपने बैंक खातों से रक़म फ़ौरन मिल जाती है।

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. * Delhi *

बाय नाउ पे लेटरः एमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स से ख़रीदारी करने वाले बाय नाउ पे लेटर (बीएनपीएल) से अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे। अगर आपके पास पर्याप्त रक़म नहीं है तो भी ये प्लेटफॉर्म आपको सामान खरीदने देते हैं और बाद में आप एकमुश्त या किस्तों में क़ीमत चुका सकते हैं। इसमें आपका पैन और कुछ जानकारी मांगी जाती है, जिसके बाद कृत्रिम मेधा तथा अल्गोरिदम की मदद से देखा जाता है कि आप कर्ज़ वापस चुकाने की क्षमता रखते हैं या नहीं। इसके साथ ही आपको मिलने वाले कर्ज़ की सीमा भी तय कर दी जाती है।

जिनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं होते हैं, उनके बीच बीएनपीएल तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा है। प्रबंधन सलाहकार फर्म रेडसियर ने फरवरी 2022 में जारी अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि छोटे कर्ज़ लेने वाले ऑनलाइन खरीदारी, फूड डिलिवरी, बिल भुगतान, ई-स्वास्थ्य, कैब के बिल आदि में इसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए कैब सेवा प्रदान करने वाली ओला भी ओला पोस्टपेड के ज़रिये अपने ग्राहकों को यात्रा के कुछ दिन बाद किराया अदा करने की सुविधा दे रही है। यही देखकर सिंपल, लेज़ीपे, ज़ेस्टमनी, ईपेलेटर, पेटीएम, फ़ोनपे जैसी कंपनियां बीएनपीएल के मैदान में उतर आई हैं। रेडसियर की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2025 तक भारत में बीएनपीएल का बाज़ार 4,000 करोड़ डॉलर के क़रीब पहुंच जाएगा। इस क्षेत्र की स्टार्टअप कंपनियों में निवेश भी बहुत तेज़ी से हो रहा है।

फ़िनटेक स्टार्टअप हमारी आपकी ज़िंदगी को सहूलियत भरा ही नहीं बना रहे हैं बल्कि रोज़गार भी दे रहे हैं। स्विगी, ज़ोमैटो हों या ओला, उबर अथवा ई-कॉमर्स कंपनियां हों, पर्दे के पीछे काम करने वालों की भर्तियां बढ़ी हैं और डिलिवरी के लिए बड़े पैमाने पर लोगों को काम दिया गया है। डिजिटल बैंकिंग ने भी देहाती इलाक़ों में रोज़गार के बड़े साधन दिए हैं, जिनमें बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट भी शामिल हैं। इनमें संभावनाएं देखकर निवेश भी खूब आ रहा है। महामारी के दौरान तो इनमें कई बड़े निवेशकों ने रक़म लगाई। साइबरमीडिया रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई-अगस्त 2021 में इन स्टार्टअप में साल भर पहले के मुकाबले लगभग 6 गुना अधिक पूंजी आई और निवेश 460 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया। इसमें से क़रीब 58 प्रतिशत रक़म डिजिटल भुगतान स्टार्टअप में आई। इनमें पेटीएम जैसे स्थापित नामों के साथ पॉलिसीबाजार, फ़ोनपे, भारतपे, पाइन लैब्स भी शामिल रहे।

फ़िनटेक की आगे की कहानी इन निवेशकों पर भी निर्भर करेगी। बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में बदलाव लाने की इच्छा वाले निवेशक देख रहे हैं कि ग्राहक किस तरह प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक सहारा लेते जा रहे हैं। इसकी छोटी सी बानगी इसी बात से ली जा सकती है कि कम शिक्षित लोग भी बीमा पॉलिसी खरीदने या क्रेडिट कार्ड चुनने से पहले फ़ोन या कंप्यूटर पर तमाम विकल्प तलाशते हैं और नापतोल के बाद ही फ़ैसला करते हैं। वास्तव में इस प्रकार की तुलना की सुविधा देने वाली वेबसाइट विज़िट करने वालों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। डिजिटल बैंकिंग की बढ़ती पैठ भी निवेशकों को इसमें रक़म लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। फ़ोन बैंक बन गया है और अंगुलियां नचाने भर से सब कुछ हो जा रहा है। बेन ऐंड कैपिटल की मार्च 2022 में आई रिपोर्ट बता रही है कि किस तरह नई पीढ़ी के ग्राहक पारंपरिक बैंकों को छोड़कर फ़िनटेक कंपनियों या नियो बैंकों (डिजिटल ढांचे पर चलने वाले नई पीढ़ी के बैंक) में खाते खुलवाने के लिए तैयार हैं।

फ़िनटेक का जलवा केवल बड़े शहरों में सीमित नहीं है। कोविड-19 महामारी ने इसे छोटे शहरों और कस्बों में भी पहुंचा दिया है मगर वहां प्रौद्योगिकी की पैठ अभी कम है और बड़ा बाज़ार अनछुआ पड़ा है। उसे पाने के लिए फ़िनटेक कंपनियां में होड़ मची हुई है। अभी बाय नाउ पे लेटर और डिजिटल ऋण का बाज़ार तो वहां खंगाला ही नहीं गया है। बीमा में फ़िनटेक का असर अभी बैंकिंग के मुक़ाबले कुछ कम है। गांव क्या शहर में भी अब तक बड़ी संख्या में लोग पारंपरिक एजेंट के ज़रिये ही बीमा ख़रीद को तरजीह देते हैं। फ़िनटेक उद्योग इस क्षेत्र में भी जब नवाचार बढ़ाएगा तो बीमा भी काफ़ी हद तक डिजिटल हो जाएगा।

फ़िनटेक उद्योग ने भारत में पिछले 3-4 साल में लंबी छलांगें लगाई हैं। हालांकि उसे डेटा सुरक्षा, निजता पर सवाल और नियामकीय बदलावों की चुनौतियों से भी दोचार होना पड़ा है। मगर सरकार की नीतियां उसके अनुकूल हैं और नई पीढ़ी के भारतीय जिस तरह उसे हाथोंहाथ ले रहे हैं, उसे देखकर मगर यह कहने में हर्ज़ नहीं है कि यह सबसे अहम क्षेत्र होता जा रहा है और अर्थव्यवस्था का कायाकल्प करने में इसकी बड़ी भूमिका रहेगी। ■

अब उपलब्ध

आज़ादी का अमृत महोत्सव

संकलन 2021

योजना (अंग्रेजी)

जनवरी–दिसंबर 2021
मूल्य : ₹300/-

कुरुक्षेत्र (अंग्रेजी)

जनवरी–दिसंबर 2021
मूल्य : ₹300/-*

आजकल

जनवरी–दिसंबर 2021
मूल्य : ₹300/-*

*कुरुक्षेत्र (अंग्रेजी) और आजकल (हिंदी) के छमाही संकलन (जुलाई से दिसंबर 2021) भी उपलब्ध हैं।
प्रत्येक छमाही संकलन का मूल्य 150 रुपये है।

प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

संकलन ऑनलाइन खरीदने के लिए कृपया **www.bharatkosh.gov.in** पर जाएं।
ऑर्डर के लिए कृपया संपर्क करें : फोन : 011-24365609, ईमेल : businesswng@gmail.com
वेबसाइट : **www.publicationsdivision.nic.in**

/dpd_india @DPD_India /publicationsdivision

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

डिजिटल मुद्रा की तैयारी

अनिल बंसल

भारत के लिए डिजिटल करेंसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) कई मायनों में लाभदायक है। हमारा जीडीपी-मुद्रा अनुपात ज्यादा है। सीबीडीसी से बड़े लेनदेन में नक़दी की आवश्यकता खत्म हो जाएगी। मुद्रा को छपवाने, उसकी सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने, रखरखाव और प्रबंधन पर रिज़र्व बैंक को काफी बड़ा खर्च वहन करना पड़ता है। डिजिटल करेंसी रिज़र्व बैंक का लगभग चार हजार करोड़ रुपया हर वर्ष बचाने में सहायक होगी। डिजिटल करेंसी को जाली रूप में तैयार करना भी कठिन है। देश के पहले से ही सशक्त डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सीबीडीसी से और बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए सरकार जो तंत्र प्रस्तुत करेगी, उसे देखना और भी उत्साहजनक होगा। नए उत्पाद के रूप में भारत जैसे बड़ी आबादी और विविधताओं वाले देश में डिजिटल करेंसी के सफल प्रयोग से विश्व के दूसरे देश भी सबक ले सकेंगे।

भारतीय डिजिटल रुपया भी शीघ्र ही प्रचलन में दिखाई देगा यानी जल्द ही आपके लेन-देन का तरीका बदल जाएगा। रुपया अब जेब में रखने तक सीमित नहीं होगा। डिजिटल रुपया आपको जेब में रखने के लिए नहीं मिलेगा क्योंकि यह प्रिंट भी नहीं होगा, बल्कि टेक्नोलॉजी के जरिए आपके काम आएगा। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण डिजिटल करेंसी शुरू करने का ऐलान कर चुकी हैं। यह भारतीय अर्थ जगत और मौद्रिक क्षेत्र के लिए एक सुखद घटना है। भारत में करेंसी पर केंद्रीय बैंक यानी भारतीय रिज़र्व बैंक का नियंत्रण है। डिजिटल करेंसी भी रिज़र्व बैंक ही जारी करेगा। इसे जल्दी जारी किया जा सके, इसके लिए वित्त मंत्रालय और रिज़र्व बैंक के बीच अब तक कई दौर की मंत्रणा हो चुकी है। रिज़र्व बैंक के डिप्टी गवर्नर ने भी बताया था कि रिज़र्व बैंक इस दिशा में पिछले दो वर्ष से काम कर रहा है।

भारत में करेंसी को जारी करने और नियंत्रित करने वाले भारतीय रिज़र्व बैंक ने जो भी करेंसी (मुद्रा) अब तक जारी की हैं, वे सभी भौतिक स्वरूप में ही हैं। पर जो रुपया डिजिटल स्वरूप में जारी किया जाएगा वह भौतिक स्वरूप में नहीं होगा, डिजिटल मोड में ही होगा। इसके कोई कागज़ी नोट नहीं होंगे। अलबत्ता कानूनी मान्यता पुख्ता तौर पर रहेगी। साफ है कि रिज़र्व बैंक जो डिजिटल रुपया जारी करने की तैयारी में है, वह लीगल टेंडर होगा। लीगल टेंडर ऐसी मुद्रा होती है जिसे स्वीकार करने से देश के भीतर कोई भी इनकार नहीं कर सकता। किसी भी वस्तु या सेवा के भुगतान के रूप में उसे स्वीकार करना ही होगा। लेनदेन में इसका चलन भी आम मुद्रा की तरह ही होगा। पर इसका उपयोग डिजिटल रूप में ही किया जाएगा। इसे डिजिटल बटुए में रख सकेंगे। उसी से भुगतान और आनलाइन खरीदारी संभव होगी। डिजिटल रुपया एक तरह से कागजी नोट का ही डिजिटल संस्करण होगा।

डिजिटल रुपया और क्रिप्टो करेंसी में अंतर

जानकारों का मानना है कि डिजिटल रुपये के आने से क्रिप्टो करेंसी का आकर्षण घटेगा। हालांकि क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल रुपया दोनों बिल्कुल अलग-अलग हैं। बुनियादी रूप से दोनों में काफी अंतर है। डिजिटल रुपया आधिकारिक मुद्रा के तौर पर

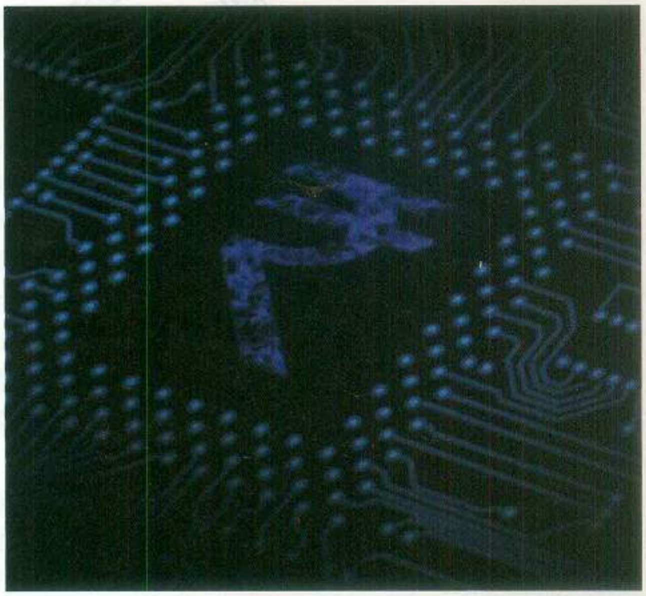

लेखक वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार और जनसत्ता के ब्यूरो प्रमुख हैं। ईमेलः abjansatta61@gmail.com

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी रुपया होगा। जबकि क्रिप्टो करेंसी में कोई पारदर्शिता नहीं है। कुल मिलाकर क्रिप्टो करेंसी सट्टेबाजी जैसा उत्पाद है, जो अनुमानों और अनिश्चितता पर आधारित है। डिजिटल रुपये के भाव में किसी तरह की अनिश्चितता नहीं होगी। क्रिप्टोकरेंसी पूरी तरह से प्राइवेट है और इस पर किसी सरकार या सेंट्रल बैंक का नियंत्रण नहीं होता। ऐसी करेंसी ग़ैरक़ानूनी होती हैं। लेकिन, भारतीय रिज़र्व बैंक जिस करेंसी पर काम कर रहा है, उसे पूरी तरह वही रेगुलेट करेगा और उसे सरकार की मंजूरी होगी।

डिजिटल रुपया का स्वरूप

डिजिटल रुपया भारत के मौद्रिक ढांचे में प्रौद्योगिकी का नया प्रवेश होगा। तकनीक के स्तर पर, कानूनी स्तर पर, जन चेतना के स्तर पर संभावित सभी चुनौतियों का रिज़र्व बैंक समाधान खोज रहा है। इसके बाद ही डिजिटल रुपये की राह साफ होगी। सरकार का प्रयास है कि डिजिटल रुपये को जारी करने में भले ही कुछ अतिरिक्त समय लगे पर जब यह जारी हो तो इसमें किसी तरह की चूक यानी लूप होल की संभावना न रहे।

जहां तक रिज़र्व बैंक का सवाल है, सारा दायित्व चूंकि उसी के हवाले है। लिहाजा उसे फूंक-फूंक कर कदम रखना पड़ रहा है। रिज़र्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास कह चुके हैं कि वे हड़बड़ी में नहीं हैं। इसीलिए अभी तक कोई निश्चित तिथि तय नहीं की गई है। आखिर साईबर सिक्योरिटी और कांउटर फीटिंग यानी जाली करेंसी जैसे जोखिम भी तो इसमें निहित हैं। इसमें दो राय नहीं कि इससे बड़े वैश्विक लेनदेन आसान हो जाएंगे। लेकिन रिज़र्व बैंक को तमाम तरह के क़ानूनी प्रावधानों से भी दो-चार होना पड़ेगा।

भारत में डिजिटल करेंसी के लिए जमीन तो नवंबर 2016 में ही तैयार हो गई थी जब सरकार ने पांच सौ और एक हजार रुपये के पुराने नोट वापस लेते हुए उनकी जगह नई करेंसी जारी की थी। नोटबंदी के दौरान ही डिजिटल लेनदेन में अप्रत्याशित वृद्धि देखने को मिली थी। यूनिफाईड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) के माध्यम से डिजिटल लेनदेन बहुत सरल हो गया। जनधन योजना ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। जब देश के हर नागरिक का सरकार ने शून्य जमा के आधार पर बैंक में खाता खोलना संभव कर दिखाया था। डिजिटल इंडिया अभियान आज देश की अर्थ व्यवस्था के लिए एक स्तंभ बन चुका है।

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

प्रौद्योगिकी से क्रांतिकारी बदलाव

यह तथ्य जगजाहिर है कि सूचना प्रौद्योगिकी में भारत ने क्रांति की है। हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर आज सारी दुनिया में नाम कमा रहे हैं। देश के भीतर भी संचार क्रांति ने विकास की नई बयार चलाई है। प्रौद्योगिकी ने जीवन को आरामदेह और सुखद बनाया है। चूंकि देश में इंटरनेट का 4जी डाटा नेटवर्क कम कीमत पर उपलब्ध है और स्मार्ट फोन भी अब पहले की तुलना में काफी सस्ते हुए हैं। जिसका प्रभाव हमें साफ दिखाई देता है कि बड़ी आबादी के पास आज मोबाइल सुविधा है। इससे देश में डिजिटलाइजेशन की राह आसान हुई है।

बाज़ार में यों तो तमाम आभासी मुद्राएं (डिजिटल करेंसी) उपलब्ध हैं। तो भी निजी क्षेत्र की डिजिटल करेंसी की पैठ अभी भी कम है। इसीलिए भारत को डिजिटल रुपया जारी करने की जरूरत महसूस हुई है। मुद्रा का अर्थ व्यवस्था में अहम स्थान है। सभ्यता के विकास के प्रारंभिक दौर में लेनदेन-वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था। फिर मुद्राएं आईं। भारत में तो प्राचीनकाल में कौड़ी भी लंबे दौर तक मुद्रा रही। उसके बाद स्वर्ण, रजत, ताम्र, एलुमीनियम और फिर लोहे जैसी धातुओं से बनी मुद्रा लेनदेन का माध्यम रही। अंत में कागज की मुद्रा का आविष्कार हुआ क्योंकि धातु की मुद्रा की लागत तो ज्यादा थी ही, इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना भी ज्यादा सुविधाजनक नहीं था। आज हम तकनीक के क्षेत्र में और आगे जा चुके हैं, तभी तो काग़ज़ की मुद्रा का स्थान भी आभासी मुद्रा (डिजिटल करेंसी) ले रही है।

डिजिटल करेंसी का इतिहास

डिजिटल करेंसी का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है। यह एक दशक के दौरान ही ज्यादा प्रचलन में आई है। चूंकि भारत भी अब विश्व की पांच बड़ी अर्थ व्यवस्थाओं में शामिल हो चुका है लिहाजा हमारा आयात और निर्यात दोनों ही निरंतर बढ़ रहे हैं। देश की वैधानिक डिजिटल करेंसी होगी तो एक तो बैंकों पर कामकाज का बोझ घटेगा, दूसरे निवेश सुगम और सुविधाजनक हो जाएगा। यह मुद्रा प्रभावी भी ज्यादा होगी। इसे वैधानिक बनाने की भी वजह है। प्रौद्योगिकी पर आज किसी एक देश या व्यक्ति का नियंत्रण नहीं है। अत: कोई एक ऐसा एजेंट भी नहीं है जो इसकी निगरानी रख सके। बिटक्वाइन के मामले में यही अड़चन सामने आई है। इसकी कीमत स्थिर नहीं हो पाने का कारण किसी नियामक का न होना ही है। इसके ज़रिए होने वाला लेनदेन धीमा भी है। इसकी प्रक्रिया का सरलीकरण आसान है भी नहीं। भारत में डिजिटल करेंसी के लिए जमीन तो नवंबर 2016 में ही तैयार हो गई थी जब सरकार ने पांच सौ और एक हजार रुपये के पुराने नोट वापस लेते हुए उनकी जगह नई करेंसी जारी की थी। नोटबंदी के दौरान ही डिजिटल लेनदेन में अप्रत्याशित वृद्धि देखने को मिली थी। यूनिफाईड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) के माध्यम से डिजिटल लेनदेन बहुत सरल हो गया। जनधन योजना ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। जब देश के हर नागरिक का सरकार ने शून्य जमा के आधार पर बैंक में खाता खोलना संभव कर दिखाया था। डिजिटल इंडिया अभियान आज देश की अर्थ व्यवस्था के लिए एक स्तंभ बन चुका है। जिसने सबको वित्तीय सुरक्षा, समावेश और पहुंच उपलब्ध कराई है। देश के समूचे वित्तीय तंत्र पर इसका चमत्कारिक प्रभाव दिखाई देता है।

डिजिटल रुपया एक दूर दृष्टि भरा कदम

यह देखना कितना सुखद है कि ठेले पर चाय और सब्जी बेचने वाला भी अब यूपीआई के माध्यम से अपना लेनदेन आसानी

से कर रहा है। न खुले पैसों का झंझट और न नक़ली नोट का कोई जोखिम। चोरी और लूटपाट का भी कोई डर नहीं। इस तरह डिजिटल रुपया एक दूर दृष्टि भरा कदम है। पांच वर्ष में इंटरनेट की देश के कोने-कोने तक सघन पैठ हो चुकी है। डिजिटल रुपये में सरकार ब्लाक चेन और दूसरी प्रौद्योगिकी का उपयोग करेगी। रिज़र्व बैंक ने अपने 1934 के अधिनियम में संशोधन पहले ही प्रस्तावित कर दिए हैं। रिज़र्व बैंक ने अपना अलग फिनटेक विभाग बनाकर इस अनुसंधान की राह पर भी अपने कदम पहले ही बढ़ा दिए थे।

सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी)

सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) लाने के प्रयास सारी दुनिया में चल रहे हैं। अटलांटिक काउंसिल के अनुसार वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 90 प्रतिशत की भागीदारी करने वाले 87 देशों में सीबीडीसी के प्रयास इस समय तेजी से चल रहे हैं। जबकि मई 2020 तक केवल 35 देश ही इस दिशा में सोच रहे थे। अभी विश्व में अधिकृत डिजिटल करेंसी की संख्या मात्र नौ है। जबकि 56 डिजिटल करेंसी जारी करने की दिशा में तेजी से प्रयास चल रहे हैं। जमैका जैसे देश ने भी हाल ही में घोषित किया है कि वह भी भारत की तरह 2022 में ही अपनी संप्रभु डिजिटल करेंसी जारी कर देगा। पूर्वी कैरेबियन देश भी डिजिटल करेंसी शुरू कर चुके हैं। डिजिटल रुपया जारी कर भारत भी वैश्विक पटल पर उचित कदम उठा रहा है।

सीबीडीसी एक डिजिटल टोकन तो है पर पूरी तरह क्रिप्टो करेंसी जैसा नहीं है। सीबीडीसी सरकारों की वैधानिक शक्ति से संपंन्न है। इसके माध्यम से लेनदेन करने वालों के लिए बैंक में खाता रखना आवश्यक नहीं होता। कोई भी व्यक्ति सीबीडीसी से नकद रुपये की तरह ही लेनदेन कर सकता है। सीबीडीसी के अभी तीन ही रूप हमारे सामने हैं। पहला-खाता आधारित, जिसमें केंद्रीय बैंक लोगों को खाता खोलकर उसके माध्यम से पैसा ट्रांसफर करने की इजाजत देता है। दूसरा स्वरूप टोकन आधारित या रिटेल आधारित है। जिसमें हर टोकन डिजिटल नक़दी जैसा माना जाता है जिसका प्रयोग आम आदमी या गैर बैंकिंग इकाई कर सकती हैं। तीसरा स्वरूप थोक आधारित है जिसमें प्रतिबंधित पहुंच वाला डिजिटल टोकन बड़े लेनदेन के लिए जारी किया जाता है। ऐसे डिजिटल टोकन आमतौर पर बैंकों के बीच होने वाले आपसी लेनदेन या दो देशों के बीच होने वाले लेनदेन का माध्यम बनते हैं।

खाता आधारित सीबीडीसी देश के भीतर परंपरागत मांग जमा का प्रत्यक्ष विकल्प हो सकता है। जबकि सीबीडीसी के बाकी दोनों स्वरूप एक तरफ तो खुदरा लेनदेन की लागत को कम कर सकते हैं। दूसरी तरफ मौजूदा बैंकिंग संस्थाओं को और प्रभावी व सक्षम बना सकते हैं। बैंकों की वित्तीय स्वायत्तता को बढ़ाने में भी ये मददगार हो सकते हैं। फिलहाल भारतीय रिज़र्व बैंक चरणबद्ध ढंग से इन स्वरूपों को लागू करने की रणनीति पर काम कर रहा है। यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि डिजिटल करेंसी डिजिटल भुगतान वाले पोर्टल पर होने वाले लेनदेन के समान नहीं हैं जिसमें लेनदेन करने वालों पक्षों के मध्य कोई भौतिक आदान-प्रदान नहीं होता। दूसरी तरफ डिजिटल करेंसी मुद्रा की ऐसी श्रेणी है जिसमें भौतिक कुछ होता ही नहीं, जो भी होता है, वह इलैक्ट्रानिक स्वरूप में होता है।

सीबीडीसी के लाभ

भारत के लिए डिजिटल करेंसी और भी कई मायनों में लाभदायक है। हमारा जीडीपी-मुद्रा अनुपात ज्यादा है। सीबीडीसी से बड़े लेनदेन में नक़दी की आवश्यकता खत्म हो जाएगी। मुद्रा को छपवाने, उसकी सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने, रखरखाव और प्रबंधन पर रिज़र्व बैंक को काफी बड़ा खर्च वहन करना पड़ता है। उदाहरण के लिए सौ रुपये के नोट को ही ले सकते हैं। कागज के नोट की औसत आयु चार वर्ष मानी जाती है। इस अवधि में सौ रुपये के एक नोट की छपाई से लेकर रखरखाव तक रिज़र्व बैंक को पंद्रह रुपये से 17 रुपये तक का खर्च वहन करना पड़ता है। बड़े नोट को चलन से हटाने के लिए कम मूल्य वाले ज्यादा नोट छापना जरूरी हो जाता है। इससे खर्च और ज्यादा बढ़ता है। डिजिटल करेंसी होने से रिज़र्व बैंक का काफी पैसा बचेगा।

न चाहते हुए भी विकासशील देश को हर वर्ष ज्यादा मात्रा में करेंसी नोट जारी करने पड़ते हैं। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक को 4.19 लाख नए नोट जारी करने पड़े थे। डिजिटल करेंसी रिज़र्व बैंक का लगभग चार हजार करोड़ रुपया हर वर्ष बचाने में सहायक होगी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 31 मार्च 2021 को देश में 28.32 लाख करोड़ रुपये की मुद्रा चलन में थी। रही डिजिटल करेंसी की बात तो इसे जाली रूप में तैयार करना भी कठिन है। इसमें स्थायित्व और सुरक्षा भी ज्यादा है। कागजी मुद्रा से कर चोरी वाले लेनदेन भी ज्यादा होते हैं, जो अर्थ व्यवस्था के लिए नुकसानदेह हैं, इस नाते भी उसमें निरंतर कटौती जरूरी है।

अब भविष्य की संभावनाओं और उपयोगिता की चर्चा भी कर ली जाए। डिजिटल करेंसी एक बार भारत में व्यापक हो जाएगी तो सरकारी समर्थन से इसे डीबीटी (सीधे लाभ के लिए हस्तानांतरण) में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। मसलन सरकार लाभार्थियों को नक़दी के बजाए सीबीडीसी भेजकर ई-कामर्स को भी बढ़ावा दे सकेगी। देश के पहले से ही सशक्त डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सीबीडीसी से और बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए सरकार जो तंत्र प्रस्तुत करेगी, उसे देखना और भी उत्साहजनक होगा। नए उत्पाद के रूप में भारत जैसे बड़ी आबादी और विविधताओं वाले देश में डिजिटल करेंसी के सफल प्रयोग से विश्व के दूसरे देश भी सबक ले सकेंगे। ■

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

ई-रुपी क्या है और यह कैसे काम करता है?

ई-रुपी मूल रूप से एक डिजिटल वाउचर है जो एक लाभार्थी को उसके फोन पर एसएमएस या क्यूआर कोड के रूप में मिलता है। यह एक प्रीपेड वाउचर है, जिसे वह किसी भी केंद्र पर, जो इसे स्वीकार करता है, जाकर उसका उपयोग कर सकता है।

उदाहरण के लिए, यदि सरकार अपने कर्मचारी का किसी निर्दिष्ट अस्पताल में विशेष उपचार का खर्च वहन करना चाहती है, तो वह एक भागीदार बैंक के माध्यम से निर्धारित राशि के लिए ई-रुपी का वाउचर जारी कर सकेगी। कर्मचारी को उसके फीचर फोन/स्मार्ट फोन पर एक एसएमएस या एक क्यूआर कोड प्राप्त होगा। वह निर्दिष्ट अस्पताल में जा कर उसकी सेवाओं का लाभ उठायेगा और अपने फोन पर प्राप्त ई-रुपी वाउचर से भुगतान कर सकेगा।

e₹UPI
PREPAID e-VOUCHER
पूरी तरह नगदरहित व संपर्करहित भुगतान

इस प्रकार ई-रुपी एक बार का संपर्क रहित, कैशलेस वाउचर-आधारित भुगतान का तरीका है जो उपयोगकर्ताओं को कार्ड, डिजिटल भुगतान ऐप या इंटरनेट बैंकिंग तक पहुंचे बिना वाउचर भुनाने में मदद करता है।

ई-रुपी को वैसी डिजिटल मुद्रा मानने का भ्रम नहीं होना चाहिए जिसे लाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक विचार कर रहा है। इसकी बजाय ई-रुपी एक व्यक्ति विशिष्ट, यहां तक कि उद्देश्य विशिष्ट डिजिटल वाउचर है।

ई-रुपी उपभोक्ता के लिए कैसे फायदेमंद है?

ई-रुपी के लिए लाभार्थी के पास बैंक खाता होना आवश्यक नहीं है, जो अन्य डिजिटल भुगतान माध्यमों की तुलना में इसकी एक प्रमुख विशिष्टता है। यह एक आसान, संपर्क रहित भुगतान पाने की दो-चरणीय प्रक्रिया सुनिश्चित करता है जिसमें व्यक्तिगत विवरण साझा करने की भी आवश्यकता नहीं होती है।

एक अन्य लाभ यह भी है कि ई-रुपी बुनियादी फोन पर भी संचालित होता है, इसलिए इसका उपयोग उन लोगों द्वारा भी किया जा सकता है जिनके पास स्मार्ट फोन नहीं है या उन जगहों पर जहां इंटरनेट कनेक्शन कमजोर है।

प्रायोजकों को ई-रुपी से क्या लाभ हैं?

प्रत्यक्ष-लाभ हस्तांतरण को मजबूत करने तथा इसे और अधिक पारदर्शी बनाने में ई-रुपी एक प्रमुख भूमिका निभा सकेगा ऐसी आशा है। चूंकि, वाउचर को भौतिक रूप से जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इससे लागत की भी कुछ बचत होगी।

सेवा प्रदाताओं को क्या लाभ होंगे?

ई-रुपी प्रीपेड वाउचर होने के नाते सेवा प्रदाता को रीयल टाइम भुगतान का भरोसा देगा।

ई-रुपी किसने विकसित किया है?

भारत में डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र की देखरेख करने वाले नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए यह वाउचर-आधारित भुगतान प्रणाली ई-रुपी लॉन्च की है।

वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से इसे विकसित किया गया है।

कौन से बैंक ई-रुपी जारी करते हैं?

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने ई-रुपी लेनदेन के लिए 11 बैंकों के साथ साझेदारी की है। ये बैंक हैं एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडियन बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया।

इन्हें लेने वाले ऐप्स हैं भारत पे, भीम बड़ौदा मर्चेंट पे, पाइन लैब्स, पीएनबी मर्चेंट पे और योनो एसबीआई मर्चेंट पे हैं। जल्द ही ई-रुपी स्वीकार करने वाले और अधिक बैंकों तथा ऐप्स के इसमें शामिल होने की उम्मीद है।

अभी ई-रुपी का उपयोग कहां किया जा सकता है?

शुरुआत में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 1,600 से अधिक अस्पतालों के साथ करार किया है जहां ई-रुपी को भुनाया अर्थात उससे भुगतान किया जा सकता है।

आने वाले दिनों में ई-रुपी का उपयोग का आधार व्यापक होने की उम्मीद है। यहां तक कि निजी क्षेत्र भी इसका उपयोग अपने कर्मचारियों को लाभ देने के लिए कर सकेंगे। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग भी इसे बिजनेस टू बिजनेस लेनदेन के लिए अपना सकेंगे। रिज़र्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने ऐलान किया है कि ई-रुपी डिजिटल वाउचर की सीमा को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है। इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि इसमें मल्टीपल यूज़ की मंजूरी दे दी गई है। ■

स्रोत : पत्र सूचना कार्यालय

Elite Academy For Education Training Pvt. Ltd. Delhi

भगत सिंहः अद्वितीय व्यक्तित्व

लेखकः चमन लाल
प्रकाशकः प्रकाशन विभाग

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★Delhi★

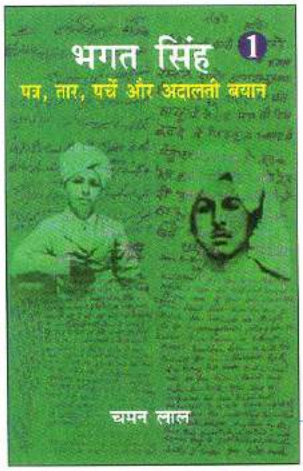

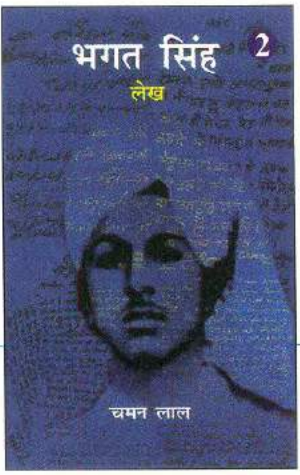

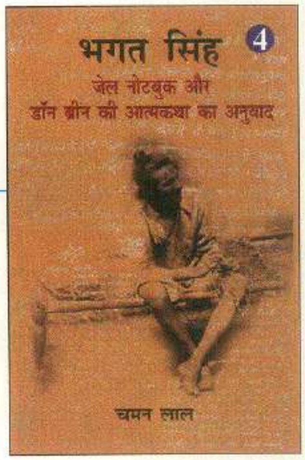

क्रांतिकारी स्वाधीनता सेनानी शहीद भगत सिंह का नाम भारतीय आज़ादी के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। भारतीय जनमानस में उनकी छवि एक लोकप्रिय युवा नेता के रूप में अंकित है। अपने आठ वर्ष के छोटे से राजनीतिक-सामाजिक जीवन में भगत सिंह की बौद्धिक-वैचारिक सक्रियता अभूतपूर्व रही। हिंदी, पंजाबी, उर्दू और अंग्रेजी में उनका लेखन उनकी अपूर्व बौद्धिक प्रतिभा और व्यापक अध्ययनवृत्ति का परिचायक है। भगत सिंह के सुहृद अध्येता एवं शोधकर्ता प्रोफ़ेसर चमन लाल ने बड़े ही परिश्रम से उनके लेखन को एकत्र एवं संपादित कर हिंदी पाठकों को उपलब्ध कराया है।

भगत सिंह का यह लेखन 'प्रकाशन विभाग' और 'सस्ता साहित्य मंडल प्रकाशन' की संयुक्त प्रकाशन योजना के अंतर्गत चार खंडों में प्रकाशित किया गया है। पहले खंड में भगत सिंह के पत्र, तार, पर्चे और अदालती बयान संकलित हैं। दूसरे खंड में विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में छपे भगत सिंह के लेख शामिल किए गए हैं। चौथे खंड में भगत सिंह की जेल नोटबुक है जिसमें 1929-31 के दौरान जेल में पढ़ी गई पुस्तकों से लिए गए नोट्स और उद्धरणों का हिंदी अनुवाद है। इसके साथ ही क्रांतिकारी डॉन ब्रीन की आत्मकथा का भगत सिंह द्वारा किया गया अनुवाद भी इस खंड में प्रस्तुत है।

क्रांतिकारी के वैयक्तिक, राजनीतिक, सामाजिक और बौद्धिक जीवन की अंतरंगता को उद्घाटित करते ये दस्तावेज़ स्वाधीनता संग्राम का दहकता इतिहास है जिसे पढ़ना और जानना आज के पाठक की बुनियादी ज़रूरत है ताकि वह अपनी जड़ों से, अपनी परंपरा से जुड़ सके और अपने वर्तमान को समझ सके।

ये चारों खंड एक-दूसरे से स्वतंत्र हैं और संबद्ध भी। इन्हें अलग-अलग पुस्तक के रूप में भी पढ़ा जा सकता है और सिलसिलेवार संबद्ध दस्तावेज़ों के रूप में भी। 'भगत सिंहः अद्वितीय व्यक्तित्व' शीर्षक संपादक की भूमिका प्रथम खंड में दी गई है। ■

आज़ादी का अमृत महोत्सव से जुड़ी अन्य किताबों के लिए
www.publicationsdivision.nic.in *पर जाएं।*

अब उपलब्ध है...

Azadi Ka Amrit Mahotsav

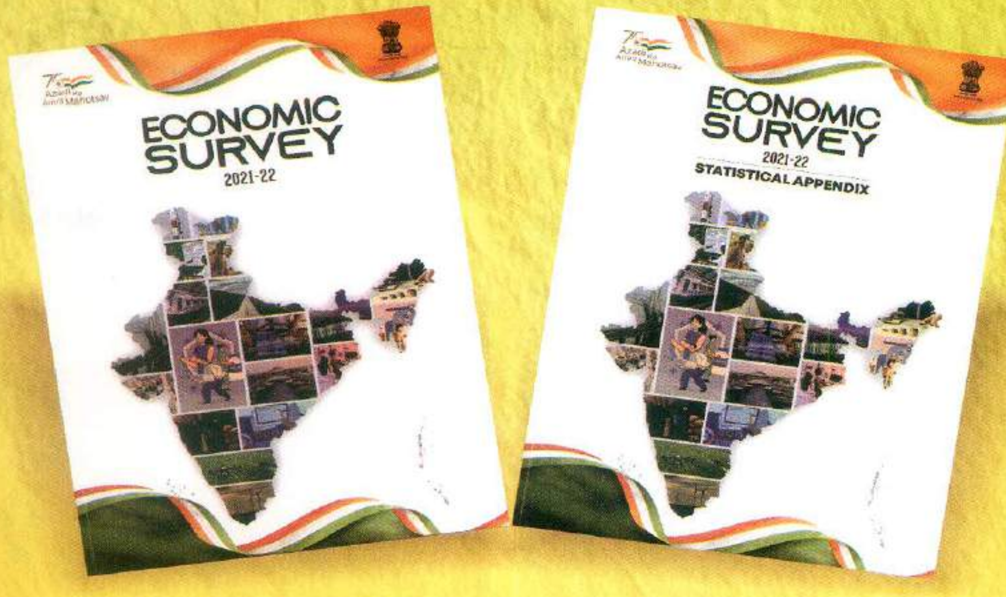

इकोनॉमिक सर्वे 2021–22 (अंग्रेजी संस्करण)

मूल्य- ₹495/- (पूरा सेट वाल्यूम 1 और 2)

- भारत के आर्थिक विकास की गहन समीक्षा
- देश के औद्योगिक, कृषि, विनिर्माण इत्यादि सभी क्षेत्रों के विस्तृत सांख्यिकीय आंकड़े

आज ही नज़दीकी
पुस्तक विक्रेता से खरीदें

ऑर्डर के लिए संपर्क करें :

फोन : 011-24365609
ई–मेल : businesswng@gmail.com
वेबसाइट : publicationsdivision.nic.in

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. * Delhi *

प्रकाशन विभाग
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार
सूचना भवन, सी जी ओ कॉम्पलेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली –110003

फोलो करें @DPD_India /dpd_india /publicationsdivision

हमारी पत्रिकाएं

योजना
विकास को समर्पित मासिक
(हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू व 10 अन्य भारतीय भाषाओं में)

प्रकाशन विभाग
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

कुरुक्षेत्र
ग्रामीण विकास पर मासिक
(हिंदी और अंग्रेजी)

आजकल
साहित्य एवं संस्कृति का मासिक
(हिंदी तथा उर्दू)

रोज़गार समाचार
साप्ताहिक
(हिंदी, अंग्रेजी तथा उर्दू)

बाल भारती
बच्चों की मासिक पत्रिका
(हिंदी)

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. Delhi

घर पर हमारी पत्रिकाएं मंगाना है काफी आसान...

आपको सिर्फ नीचे दिए गए 'भारत कोश' के लिंक पर जा कर पत्रिका के लिए ऑनलाइन डिजिटल भुगतान करना है–
https://bharatkosh.gov.in/Product/Product

सदस्यता दरें

प्लान	योजना या कुरुक्षेत्र या आजकल (सभी भाषा)	बाल भारती	रोज़गार समाचार	
वर्ष	रजिस्टर्ड डाक	रजिस्टर्ड डाक	मुद्रित प्रति (साधारण डाक)	ई-संस्करण
1	₹ 434	₹ 364	₹ 530	₹ 400
2	₹ 838	₹ 708	₹ 1000	₹ 750
3	₹ 1222	₹ 1032	₹ 1400	₹ 1050

सदस्यता शुल्क में रजिस्टर्ड डाक का शुल्क भी शामिल है। कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र **नए ग्राहकों को अब रोज़गार समाचार के अलावा सभी पत्रिकाएं केवल रजिस्टर्ड डाक से ही भेजी जाएंगी।** पुराने ग्राहकों के लिए मौजूदा व्यवस्था बनी रहेगी।

ऑनलाइन के अलावा आप डाक द्वारा डिमांड ड्राफ्ट, भारतीय पोस्टल आर्डर या मनीआर्डर से भी प्लान के अनुसार निर्धारित राशि भेज सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट, भारतीय पोस्टल ऑडर या मनीआर्डर '**अपर महानिदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय**' के पक्ष में **नई दिल्ली** में देय होना चाहिए। रोज़गार समाचार की 6 माह की सदस्यता का प्लान भी उपलब्ध है, प्रिंट संस्करण रु. 265/-, ई-संस्करण रु. 200/-, कृपया ऑनलाइन भुगतान के लिए https://eneversion.nic.in/membership/login लिंक पर जाएं। डिमांड ड्राफ्ट 'Employment News' के पक्ष में **नई दिल्ली** में देय होना चाहिए। अपने डीडी, पोस्टल आर्डर या मनीआर्डर के साथ नीचे दिया गया 'सदस्यता कूपन' या उसकी फोटो कॉपी में सभी विवरण भरकर हमें भेजे। भेजने का पता है-

संपादक, पत्रिका एकांश, प्रकाशन विभाग, कक्ष सं. 779, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003.

अधिक जानकारी के लिए ईमेल करें- pdjucir@gmail.com

हमसे संपर्क करें- **फोन: 011-24367453**, (सोमवार से शुक्रवार सभी कार्य दिवस पर प्रात: साढ़े नौ बजे से शाम छह बजे तक)

कृपया नोट करें कि पत्रिका भेजने में, सदस्यता शुल्क प्राप्त होने के बाद कम से कम आठ सप्ताह लगते हैं, कृपया इतने समय प्रतीक्षा करें और पत्रिका न मिलने की शिकायत इस अवधि के बाद करें।

सदस्यता कूपन (नई सदस्यता/नवीकरण/पते में परिवर्तन)

कृपया मुझे 1/2/3 वर्ष के प्लान के तहत .... पत्रिका .... भाषा में भेजें।

नाम (साफ व बड़े अक्षरों में) ....

पता : ....

.... जिला .... पिन ....

ईमेल .... मोबाइल नं. ....

डीडी/पीओ/एमओ सं. .... दिनांक .... सदस्यता सं. ....

कवर 2 से आगे...

करना है। सभी राष्ट्रीय जलमार्गों पर कार्गो की आवाजाही 2020 में 74 एमएमटी से बढ़ाकर 2024-25 तक 95 मिलियन मीट्रिक टन होगी। गंगा पर कार्गो की आवाजाही 2024-25 तक 9 एमएमटी से बढ़ाकर 29 एमएमटी की जाएगी। क्षेत्रीय संपर्क योजना- उड़ान द्वारा संचालित, नागरिक उड्डयन क्षेत्र में विमानन में वृद्धि हुई है। 2024-25 तक लगभग 20 हवाई अड्डे, हेलीपोर्ट और जल हवाई अड्डे चालू होने हैं। 2024-25 तक मौजूदा 51 हवाई पट्टियों, 18 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों, 12 जल हवाई अड्डों और 28 हेलीपोर्ट सहित कुल 109 हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा।

- एक्सप्रेस-वे के लिए प्रधानमंत्री गतिशक्ति मास्टर प्लान 2022-23 में लोगों और माल की तेज़ आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए तैयार किया जाएगा। 2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का 25,000 किलोमीटर तक विस्तार किया जाएगा। सार्वजनिक संसाधनों के पूरक के लिए वित्तपोषण के नवीन तरीकों के माध्यम से 20,000 करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे। भारतमाला द्वारा संचालित सड़क परिवहन और 2024-25 तक राजमार्ग क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क को दो लाख किलोमीटर मार्ग का किया जाना है। तटीय क्षेत्रों के साथ-साथ, चार और छह-लेन राष्ट्रीय राजमार्गों के 5590 किलोमीटर को 2024-25 तक पूरा किया जाना है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सभी राज्यों की राजधानियों को 2024-25 तक चार लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग या दो-दो लेन विन्यास के दो वैकल्पिक संरेखण से जोड़ा जाएगा।
- 2024-25 तक, भारतीय रेलवे को महत्वपूर्ण परियोजनाओं के पूरा होने के कारण भीड़भाड़ में 51 प्रतिशत की कमी देखने को मिलेगी। भारतीय रेलवे द्वारा संभाला जाने वाला कार्गो 2020 के 1210 मिलियन टन से 1600 मिलियन टन हो जाएगा। मालगाड़ियों की तेज़ आवाजाही के लिए पश्चिमी और पूर्वी समर्पित माल गलियारों को पूरा किया जाएगा। रेलवे पार्सल की आवाजाही के लिए निर्बाध समाधान प्रदान करने के लिए डाक और रेलवे नेटवर्क के एकीकरण में अग्रणी होने के अलावा, छोटे किसानों और छोटे तथा मध्यम उद्यमों के लिए नए उत्पादों और कुशल रसद सेवाओं का विकास करेगा। स्थानीय व्यवसायों और आपूर्ति शृंखलाओं की सहायता के लिए 'एक स्टेशन-एक उत्पाद' अवधारणा को लोकप्रिय बनाया जाएगा।

प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के दायरे में आर्थिक परिवर्तन, निर्बाध मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी और रसद दक्षता के लिए सात संचालक शामिल होंगे, जिनमें गतिशक्ति मास्टर प्लान के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा विकसित बुनियादी ढांचा भी शामिल होगा। नियोजन, वित्तपोषण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा जिसमें नवीन तरीके, प्रौद्योगिकी का उपयोग और तेज़ी से कार्यान्वयन शामिल है। नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में इन 7 वाहकों से संबंधित परियोजनाओं को प्रधानमंत्री गतिशक्ति ढांचे के साथ जोड़ा जाएगा। मास्टर प्लान की कसौटी विश्व स्तरीय आधुनिक बुनियादी ढांचा और लोगों तथा वस्तुओं दोनों की आवाजाही के विभिन्न तरीकों और परियोजनाओं के स्थान के बीच रसद तालमेल होगा। इससे उत्पादकता बढ़ाने और आर्थिक विकास में तेज़ी लाने में मदद मिलेगी।

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

केन-बेतवा परियोजना और नदियों को जोड़ने वाली अन्य परियोजनाएं

केन-बेतवा लिंक परियोजना का कार्यान्वयन 44,605 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से किया जाएगा। इसका उद्देश्य किसानों की 9.08 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई, 62 लाख लोगों को पेयजल आपूर्ति, 103 मेगावाट जलविद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा प्रदान करना है। इस परियोजना के लिए (संशोधित अनुमान) 2021-22

में 4,300 करोड़ रुपये और 2022-23 में 1,400 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। दमनगंगा-पिंजाल, पार-तापी नर्मदा, गोदावरी-कृष्णा, कृष्णा-पेन्नार, और पेन्नार-कावेरी नामक पांच नदी लिंक के ड्राफ्ट डीपीआर को अंतिम रूप दिया गया है। एक बार लाभार्थी राज्यों के बीच सहमति बन जाने के बाद, केंद्र कार्यान्वयन के लिए सहायता प्रदान करेगा।

आर्थिक क्षेत्र

- मास्टर प्लान की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक भारत में व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना है। कुछ क्षेत्र जहां आर्थिक क्षेत्र प्रस्तावित हैं, इस प्रकार हैं:
- उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, 2024-25 तक चार चरणों में स्वीकृति / परियोजनाओं वाले 11 औद्योगिक कॉरिडोर विकसित किए जाने हैं। उद्योगों के लिए विश्वसनीय, टिकाऊ, लचीला और गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ग्रीनफील्ड स्मार्ट औद्योगिक शहरों का निर्माण किया जाना है।
- 2024-25 तक 90 टेक्सटाइल क्लस्टर/मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित किए जाएंगे। मशीनरी निर्माण के लिए आंशिक रूप से समर्पित दो पार्कों के साथ पैमाने और दक्षता को बढ़ावा देने के लिए 10 मेगा एकीकृत कपड़ा क्षेत्रों / पार्कों में 'लगाओ और चलाओ' सुविधाएं, सामान्य सुविधाएं और एकीकृत मूल्यश्रृंखला होगी।
- 2024-25 तक 109 फार्मा और मेडिकल डिवाइस क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। प्रत्येक के लिए 20 करोड़ रुपये की सामान्य सुविधाओं का वित्तपोषण करके 10 फार्मा क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा, तीन बल्क ड्रग पार्क और चार मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित किए जाने हैं।
- इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए 2024-25 तक 38 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी) विकसित किए जाने हैं। इनमें से 23 नए समूहों में 'लगाओ और चलाओ' और सीएफसी सुविधाएं हैं।
- 2024-25 तक, दो रक्षा गलियारों को विकसित किया जाना है, जिनमें से प्रत्येक में 10000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश का लक्ष्य है। 2024-25 तक एयरोस्पेस और रक्षा वस्तुओं तथा सेवाओं में 35000 करोड़ रुपये के निर्यात सहित 170000 करोड़ रुपये का कारोबार किया जाएगा।।
- 2024-25 तक, 197 मेगा फूड पार्क और कृषि प्रसंस्करण केंद्र विकसित किए जाने हैं, जिससे खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमता 222 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 847 लाख मीट्रिक टन हो जाएगी। इसके अलावा, क्लस्टर आधार पर कृषि-खाद्य उत्पादों का मूल्य शृंखला विकास किया जाएगा।
- 2024-25 तक 70 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त मछली उत्पादन और मत्स्य निर्यात को दोगुना करने के साथ 202 मछली पकड़ने के समूह/मछली पकड़ने के बंदरगाह और प्रमुख मछली पकड़ने के केंद्र विकसित किए जाएंगे। विविध मत्स्य पालन गतिविधियों के हब के रूप में एकीकृत जल पार्क विकसित किए जाएंगे।

संस्थागत ढांचा

त्रि-स्तरीय प्रणाली के लिए रोल आउट, कार्यान्वयन, निगरानी और सहायता तंत्र के लिए संस्थागत ढांचा डिज़ाइन किया गया है:

1. सचिवों का अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओ)
2. नेटवर्क नियोजन समूह (एनपीजी)
3. तकनीकी सहायता इकाई (टीएसयू)

ईजीओ का नेतृत्व कैबिनेट सचिव करेंगे और इसमें सदस्य के रूप में 18 मंत्रालयों के सचिव और रसद विभाग के प्रमुख सदस्य संयोजक के रूप में शामिल होंगे। ईजीओएस को रसद दक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री गतिशक्ति के कार्यान्वयन की समीक्षा और निगरानी का अधिकार दिया गया है। इसे मास्टर प्लान में बाद के किसी भी संशोधन को करने के लिए रूपरेखा और मानदंड निर्धारित करने का अधिकार है।

आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी (सीसीईए) ने नेटवर्क नियोजन समूह (एनपीजी) के गठन, संरचना और संदर्भ की शर्तों को भी मंजूरी दे दी है, जिसमें संबंधित बुनियादी ढांचा मंत्रालयों के नेटवर्क नियोजन शाखा के प्रमुख शामिल हैं और यह ईजीओ की सहायता करेगा।

इसके अलावा, नेटवर्क के समग्र एकीकरण में जटिलताओं को देखते हुए, किसी भी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए कार्यों के दोहराव से बचने के लिए अनुकूलन बढ़ाने के साथ-साथ सूक्ष्म योजना विवरण के माध्यम से रसद लागत को कम करने के लिए, टीएसयू को आवश्यक दक्षता प्रदान करने के वास्ते अनुमोदित किया गया है।

गतिशक्ति मास्टर प्लान को सभी हितधारकों के बीच दृश्य समझ, समन्वय के लिए नवीनतम उपग्रह चित्रों के उपयोग द्वारा दक्षता बढ़ाने और एक एकीकृत दृष्टिकोण रखने के लिए परियोजनाओं के कार्यान्वयन में संकलन, मार्ग नियोजन, भूमि अधिग्रहण, अनुमति तथा भीड़ कम करने और प्रगति के लिए डैशबोर्ड आधारित आवधिक निगरानी के लिए नियोजन उपकरण डिज़ाइन किया गया है।

प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान आत्मनिर्भरता के संकल्प की ओर भारत के आत्मविश्वास को प्रेरित करेगा। यह राष्ट्रीय मास्टर प्लान 21वीं सदी के भारत को गति प्रदान करेगा। इस राष्ट्रीय योजना से अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे और मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी को गति मिलेगी। यह राष्ट्रीय योजना नियोजना से लेकर क्रियान्वयन तक बुनियादी ढांचे से संबंधित सरकारी नीतियों को गति प्रदान करेगी। यह गतिशक्ति राष्ट्रीय योजना सरकार की परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए सटीक जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान करेगी। ■

स्रोत: पीआईबी

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★Delhi★